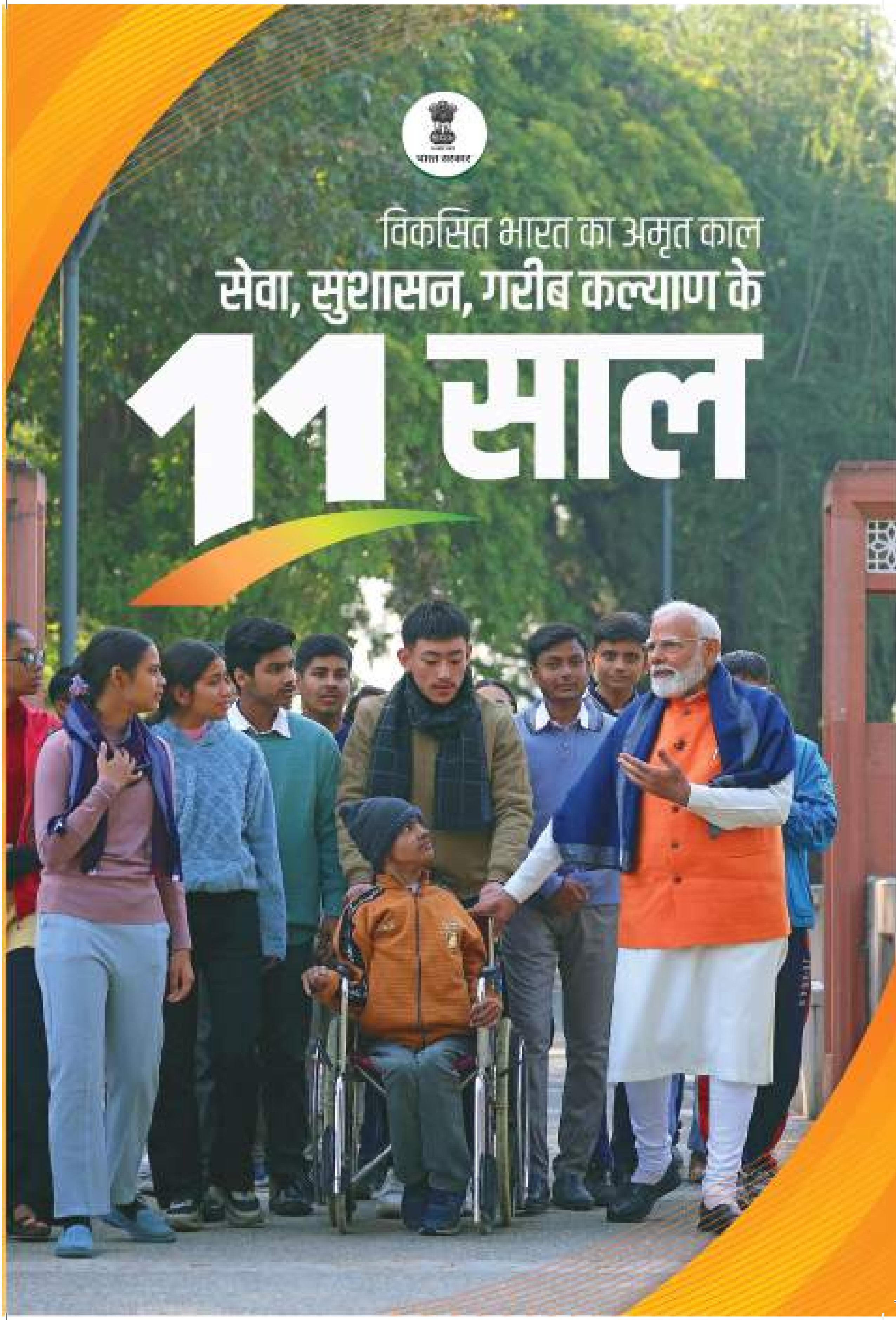
भारत सरकार
विकसित भारत का अमृत काल
सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के
11 साल

विकसित भारत का अमृत काल

सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के

11 साल

विषय-सूची

1	गरीबों की सेवा, वंचितों का सम्मान	1
2	किसानों का कल्याण सुनिश्चित	15
3	नारी शक्ति को मिला नया बल	33
4	भारत की अमृत-पीढ़ी हो रही सशक्त	47
5	मध्यम वर्ग का जीवन हुआ आसान	55
6	सभी के लिए सस्ती, सुलभ स्वास्थ्य सेवा	65
7	'राष्ट्र प्रथम'- विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा	75
8	भारत, वैश्विक आर्थिक महाशक्ति	89
9	ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस से कारोबार को लगे पंख	97
10	इंफ़्रास्ट्रक्चर- तेज़ी से हो रहा बेहतर	105
11	टेक्नोलॉजी से भारत को नई शक्ति	115
12	नॉर्थ ईस्ट बन रहा विकास का नया इंजन	125
13	विरासत और विकास	135
14	पर्यावरण एवं सतत विकास	153

परिचय

2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 वर्ष पूरे हो रहें हैं। ये 11 वर्ष समावेशी, प्रगतिशील और सतत विकास लाने के लिए समर्पित रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार अपने सभी नागरिकों के लिए समानता और अवसरों के सृजन की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने विकास की राजनीति अर्थात विकासवाद को केंद्र बिंदु बनाते हुए मुख्यधारा में ला दिया है और अब राजनीति संवाद एवं नीतिगत कार्य प्रक्रिया इसी के इर्द-गिर्द घूमती है। 2014 में पदभार ग्रहण करने के बाद से, प्रधानमंत्री मोदी हर नीति निर्माण और इसे कार्यान्वित करने में 'भारत प्रथम' के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के अपने संकल्प पर अडिग रहे हैं। यह संकल्प सरकार के बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक प्रबंधन, वंचित समूहों के लिए सशक्तिकरण योजनाओं, सांस्कृतिक संरक्षण के प्रयासों आदि के लिए समाधान निकालने में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है ।प्रधानमंत्री मोदी की सरकार हमेशा चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को तय करने और निर्धारित समय सीमा से पहले उन्हें प्राप्त करने में विश्वास रखती है। इस दृढ़ संकल्प को, चाहे वह कोविड-19 के खिलाफ रिकॉर्ड समय में पूरी पात्र आबादी का टीकाकरण करना हो, देश के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक निर्यात दर्ज करना हो, पूरे भारत में हो रही डिजिटल क्रांति हो, ग्रामीण क्षेत्र के विद्युतीकरण में महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण का हो अथवा घरों में पेयजल की सुविधा प्रदान करना हो, सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है।

पिछले 11 वर्षों में, जन, धन, आधार और मोबाइल के रुप में जेएएम-त्रिशक्ति का उपयोग करते हुए सार्वजनिक सेवा वितरण और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में एक आदर्श बदलाव लाया गया है। जेएएम-त्रिशक्ति भारत के रूपांतरित और बेहतर तरीके से विकसित डिजिटल परिदृश्य का प्रमुख प्रवर्तक है। इसने मध्यस्थों को हटा दिया है और लाभार्थी के बैंक खाते में लाभों के सीधे हस्तांतरण को सुलभ बना दिया है।

किसी देश को समृद्ध होने के लिए, यह आवश्यक है कि इसके बुनियादी ढांचे में तेजी से वृद्धि हो और प्रधानमंत्री मोदी के गतिशील नेतृत्व में सरकार इस तथ्य को बेहतर रूप से समझती है। दशकों से विलंबित परियोजनाओं को पूरा करने के साथ ही नई परियोजनाओं का शुभारंभ इस सरकार के विकासात्मक दृष्टिकोण की आधारशिला रही है।

पूर्व में विकास के दिशाहीन दृष्टिकोण के विपरीत, मोदी सरकार ने समग्र विकास की संस्कृति को अपनाया है जो किसी भी पक्ष को पीछे नहीं छोड़ती है। पिछले 11 वर्षों में कल्याण कवरेज के व्यापक विस्तार ने सभी भारतीय को बड़े सपने देखने और अधिक से अधिक उपलब्धियों की आकांक्षारखने के लिए प्रेरित किया है।

विकास और कल्याणकारी योजनाओं की समावेशी और समग्र पहुंच ने विभिन्न वंचित समूहों के लिए अपरिवर्तनीय सशक्तिकरण सुनिश्चित किया है, जिससे उन्हें महत्वाकांक्षी और आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिली है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना भारतीय विरासत को वैश्विक मान्यता की स्वीकृति है।

वैश्विक मंच पर भारत की दावेदारी में भी उल्लेखनीय बदलाव आया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता निर्णय लेने में दृढ़ निश्चयी, तीव्र और संप्रभुता से भरे एक नए भारत को प्रदर्शित करती है।

2001 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित होने के बाद और 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात, नरेंद्र मोदी ने सुधारों और शासन में एक नया मानदंड स्थापित किया है जो न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के कई हिस्सों के लिए समावेशी विकास का एक मॉडल बन गया है उन्होंने न केवल लोगों को आकांक्षा रखने के लिए प्रोत्साहित किया है बल्कि उनकी बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सरकारी सहायता भी प्रदान की है ताकि प्रत्येक भारतीय 'अमृत काल ' में भारत की विकास गाथा का हिस्सा बन सके।

यह पुस्तक प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में नीति निर्माण के 14 पहलुओं अर्थात बुनियादी ढांचे से होते हुए विदेश नीति से लेकर सामाजिक न्याय तक भारत के परिवर्तन को दर्शाने वाला एक व्यापक संग्रह है। यह वंचितों की सेवा करने, महिलाओं को सशक्त बनाने, युवाओं को अवसर प्रदान करने और किसानों को सम्मान दिलाने से जुड़ी,11 वर्षों की गाथा है। यह एक नए भारत की कहानी है।

* * *

डीबीटी हो या बिजली, पानी, टॉयलेट जैसी सुविधाएं गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने की योजना हों, इन सभी ने जमीनी स्तर पर एक क्रांति ला दी है। इन योजनाओं ने देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सम्मान और सुरक्षा के भाव से भर दिया है।

-नरेन्द्र मोदी

गरीबों की सेवा, वंचितों का सम्मान

1

सारांश

संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक को समानता प्रदान करता है, और उनमें से प्रत्येक के लिए गरिमापूर्ण जीवन की गारंटी देता है। फिर भी आजादी के कई दशकों के बाद भी, कई भारतीयों में सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए मूलभूत सुविधाओं की कमी बनी रही। इस दुर्भाग्यपूर्ण परिदृश्य को बदलने की आवश्यकता को समझते हुए समावेशी दृष्टिकोण के साथ विकास की सतत प्रक्रिया की शुरुआत की गई। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार विकास के एक मॉडल के लिए प्रतिबद्ध है जो यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी पीछे ना रहे।

यह विकास मॉडल जो न केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए, बल्कि सभी लोगों के लिए पीने के पानी, बिजली कनेक्शन, स्वास्थ्य सेवा, शौचालय, एलपीजी सिलेंडर, शिक्षा और वित्तीय समावेशन जैसी बुनियादी सुविधाओं की गारंटी देता है।

मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में, प्रत्येक भारतीय को सशक्त बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को लॉन्च और कार्यान्वित किया।

इस तरह के सीमलैस और त्वरित सशक्तिकरण पटलों के प्रभाव मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया जैसे कार्यक्रमों में देखे जा सकते हैं जो हाशिए के समूहों से युवा उद्यमियों का एक बड़ा पूल बना रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत दिए गए 52 करोड़ ऋणों में से आधे से अधिक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों के उद्यमियों को दिए गए हैं।

यह न केवल व्यक्तियों के सशक्तिकरण की शुरुआत कर रहा है, बल्कि पारंपरिक रुप से उपेक्षित समुदायों को सशक्त बनाने का एक साधन भी है। समावेशी सामाजिक कल्याण की भावना में, आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करने के मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले ने उच्च जातियों के गरीब परिवारों को बहुत आवश्यक सहायता प्रदान की है।

समावेशी विकास की अपनी दृष्टि के हिस्से के रूप में, सरकार ने दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, विमुक्त और खानाबदोश जनजातियों और अब तक सेवा से वंचित या कम सेवा वाले ऐसे अन्य समूहों को सशक्त बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। सामाजिक न्याय के लिए सरकार का संकल्प चिकित्सा शिक्षा में अखिल भारतीय कोटे की सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण को लागू करने के अपने निर्णय में स्पष्ट था, यह सुनिश्चित करते हुए कि इन समूहों के छात्र भी किफायती सरकारी कॉलेजों में डॉक्टर बनने की आकांक्षा कर सकते हैं। इसी तरह, नमस्ते योजना के तहत, सरकार का लक्ष्य असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई की प्रथाओं को खत्म करना है ताकि सफाई कर्मचारी सम्मान का जीवन जी सकें

जनजातीय गौरव दिवस का सबसे नवीनतम उत्सव जो एक श्रद्धेय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर 15 से 26 नवंबर, 2024 तक मनाया गया। इस उत्सव का उद्देश्य भारत के इतिहास और प्रगति में आदिवासी समुदायों के योगदान का सम्मान प्रदान करना था।

सरकार की कल्याण संबंधी प्रावधान और गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को वैश्विक संस्थानों से मान्यता मिली है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के एक पेपर में देश में अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने के लिए श्री मोदी की सरकार को श्रेय दिया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (ओपीएचआई) द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) ने भी भारत को अपने सभी दस बहुआयामी गरीबी संकेतकों में कमी लाने का श्रेय दिया है। गरीबों और वंचितों की सेवा करना श्री मोदी की सरकार का अंतर्निहित वादा रहा है, एक ऐसा वादा जो अंत्योदय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित है, जिसका अर्थ है कि विकास का लक्ष्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक की यह समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचता।

***

मुख्य बातें

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना
के तहत
81 करोड़
लोगों को मुफ्त अनाज

15+ करोड़
घरों में नल से जल कनेक्शन

प्रधानमंत्री आवास योजना
के तहत
4 करोड़
से ज्यादा
घरों का निर्माण

स्वच्छ भारत
के तहत
12 करोड़
शौचालयों का निर्माण

पीएम स्वनिधि
के माध्यम से
68 लाख
रेहड़ी-पटरी वालों को मिला आर्थिक बल

मुद्रा योजना
के तहत
छोटे उद्यमियों को मिले
52.5 करोड़
से ज्यादा के लोन

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को
संवैधानिक दर्जा

COVID लॉकडाउन के दौरान
20 करोड़
महिलाओं के खातों में कैश ट्रांसफर

स्टैंड अप इंडिया
के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को
₹14,700+ करोड़ रुपये
से अधिक का लोन

वर्तमान में केंद्र में
60%
मंत्री एससी, एसटी या ओबीसी हैं

2014 से एकलव्य आवासीय विद्यालयों की संख्या में
चार गुना
से अधिक वृद्धि

112 आकांक्षी जिले
विकास के मापदंडों पर अपने राज्यों के औसत से ज्यादा बढ़े

उपलब्धियां

अंत्योदय और सैचुरेशन कवरेज से तुष्टिकरण का अंत

2014 से कल्याणकारी योजनाएं **अंत्योदय के सिद्धांत** से प्रेरित रही हैं। (कोई भी न छूटे)। इसका मतलब है कि सरकार अपनी हर योजना में सैचुरेशन यानी शत-प्रतिशत लक्ष्य को टारगेट कर रही है।

शत-प्रतिशत कवरेज का मतलब ही है कि ऐसे शासन से सभी को लाभ मिलेगा।

विकसित भारत संकल्प यात्रा देश में 2.6 लाख ग्राम पंचायतों और 4,000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों तक पहुंची और जन कल्याण की योजनाओं को 100% सेचुरेशन तक ले जाने का लक्ष्य।

उपेक्षित वर्गों का स्थाई सशक्तिकरण

- पहले की कुछ सरकारों का रवैया केवल आंशिक लाभ देकर वंचित वर्गों पर कृपा दिखाना था।
- वे लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना चाहते थे और इसलिए उनका सशक्तिकरण नहीं किया गया।
- लेकिन अब, पीएम मोदी ने वंचित वर्गों का **स्थाई सशक्तिकरण** सुनिश्चित किया है।
- स्टैंड-अप इंडिया और मुद्रा योजना जैसी योजनाएं उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराकर कमजोर वर्गों के लोगों को सशक्त कर रही है।
- ये नए उद्यमी न केवल नई आकांक्षाओं को आकार देंगे, बल्कि **पूरे समुदाय के लिए रोल मॉडल** बन रहे हैं।

- **कामचलाऊ व्यवस्था वाली राजनीति का अंत**
- अगर एक बार गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या फिर पानी का कनेक्शन दे दिया गया तो फिर **कोई उसे छीन नहीं सकता।**
- यह सुनिश्चित करता है कि गरीब आकांक्षी बनें, क्योंकि उनकी बुनियादी आवश्यकताएँ पूरी हो रही हैं।
- परिणामस्वरुप, लोग अपनी सरकारों से ज़्यादा उम्मीद करने लगते हैं, जिससे सरकार बेहतर सेवाएँ देने के लिए प्रेरित होती है।
- बहुत लंबे समय तक, लो डिलीवरी और लो एक्सपेक्टेशन ने भारत का अहित किया है - लेकिन अब पीएम मोदी के नेतृत्व में इसमें बदलाव आ रहा है।

* * *

सरकार के बड़े काम

आंकड़े गवाह हैं कि सरकार गरीबों के लिए बड़ा सोचती है। बीते 11 वर्षों के दौरान करोड़ों परिवारों को पहली बार सबसे जरूरी बुनियादी सुविधाएं मिली हैं।

55.22 करोड़
जन-धन खाते खोले गए

51+ करोड़
लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल

23.64 करोड़
लोगों को जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ

77+ करोड़
आयुष्मान भारत हेल्थ एकाउंट बने

4 करोड़
से अधिक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत

₹ 43.8 लाख करोड़
से अधिक सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में 2014 से

100% इच्छुक घरों का सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकरण

10.33 करोड़ से अधिक उज्ज्वला योजना एलपीजी कनेक्शन

वंचितों की सेवा सर्वोपरि

71% प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले किसान SC/ST/OBC वर्ग से

80% छोटे और सीमान्त किसान जिसमें ज्यादातर ST/SC/OBC वर्ग के किसान शामिल हैं, PM-KISAN के तहत आय प्राप्त कर रहे हैं

44.19%% घर PMAY(G) के तहत SC/ST को मिले

58% छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले ST/SC/OBC वर्ग के छात्र

51% मुद्रा योजना के52+ करोड़ लाभार्थियों में SC/ST/OBC वर्ग से

जनसेवा के काम में बदलती मानसिकता

पहले

सरकार 1 रुपया भेजती है, उसमें से लोगों तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते है।

अब

सैचुरेशन मेरा सपना है। हमें 100 प्रतिशत कवरेज के लक्ष्य की ओर बढ़ना है। सरकारी मशीनरी को इसकी आदत डाल लेनी चाहिए।

सबका साथ
सबका विकास
सबका विश्वास
सबका प्रयास

समावेशी शासन

केंद्रीय मंत्रिपरिषद में SC, ST और OBC का अब तक का **सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व**

उच्च शिक्षा में **10 प्रतिशत EWS Quota** लागू

OBC और EWS के लिए मेडिकल एजुकेशन में अखिल भारतीय कोटा सीटों पर आरक्षण

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा

Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 से ट्रांसजेंडरों के अधिकारों का संरक्षण

युवाओं को मादक पदार्थों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए **नशा मुक्त भारत अभियान** की शुरुआत

डीनोटिफाइड, घुमंतु और अर्ध-घुमंतु जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना

मान्यता प्राप्त अक्षमता की संख्या **7 से बढ़ाकर 21** किए जाने से दिव्यांगजनों को लाभ

पीएम विश्वकर्मा योजना

- पीएम विश्वकर्मा **₹13 हज़ार करोड़** की लागत से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना
- विश्वकर्मा भाई-बहनों को **₹3 लाख तक का बिना गारंटी ऋण**
- **₹15 हज़ार** तक का टूलकिट प्रोत्साहन, कौशल उन्नयन, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता

क्या आप जानते हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजनों की मदद के लिए कैंप आयोजित कर उन्हें सहायक उपकरण वितरित करता है। 2014 के बाद करीब 18 हज़ार+ कैंप का आयोजन हो चुका है, जिससे 31 लाख से अधिक दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण हुआ है।

श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण

प्लेटफॉर्म वर्कर्स पर ध्यान

एग्रीगेटर्स जैसे नए युग के प्लेटफॉर्म के विकास का मतलब श्रमिकों के लिए नए प्रकार की नौकरियां। भारत उन पहले कुछ देशों में से एक है जो अपने श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा के बारे में सोचता है।

एग्रीगेटर्स को लाभ प्रदान करने के लिए टर्नओवर के 1-2% के योगदान पर 5% तक फायदे का प्रावधान किया गया है।

e-Shram सशक्तिकरण के लिए

30.82 करोड़
असंगठित श्रमिक पोर्टल पर पंजीकृत

400 व्यवसाय, कौशल सेट, शिक्षा, आय, सामाजिक श्रेणी, बैंक खाता विवरण संबद्ध

36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश असंगठित श्रमिकों को सामाजिक कल्याण की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए, डाटा साझा करने हेतु इ-श्रम से जुड़े

प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन

51.31 लाख
असंगठित क्षेत्र के कामगार स्वघोषणा के आधार पर पंजीकृत

₹3,000
न्यूनतम पेंशन है, जो उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद मिलेगी

बोझ हुआ कम, अनुपालन में सुधार

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंशदान दरों में कमी	नियोक्ताओं का योगदान 4.75% से घटाकर 3.25% किया गया	कर्मचारियों का योगदान 1.75% से घटाकर 0.75% किया गया

श्रमिकों के लिए COVID-19 राहत कार्य

24%

₹ 15,000 प्रति माह से कम वेतन पाने वाले श्रमिकों के ईपीएफ खातों में भुगतान की गई मासिक मजदूरी का अनुपात।

लगभग ₹ 54,200 करोड़

2019-20 से 2024-25 के दौरान ईपीएफओ कार्यालयों द्वारा 2.56 करोड़ श्रमिकों को वितरित किए गए

उद्यमिता से सशक्तिकरण

PM-SVANidhi योजना के तहत 68 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को लोन सुविधा

52.5+ करोड़ MUDRA लोन में से आधे से ज़्यादा SC/ST/OBC उद्यमियों को

Standup India के तहत महिलाओं/SC/ST उद्यमियों के लिए 2.74 लाख ऋण स्वीकृत

सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रतीकों को पहचान

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर से जुड़े 5 मुख्य स्थलों का 'पंचतीर्थ' के रूप में पुनर्विकास

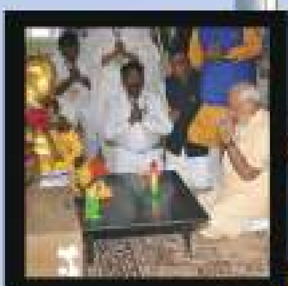

15 नवंबर, 2024 को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। मई 2025 तक, भारत सरकार ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी नेताओं के योगदान को सम्मानित करने के लिए 10 राज्यों में 11 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को स्वीकृति दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी प्रमुखजन को श्रद्धांजलि दी और पूरे भारत में आदिवासी समुदायों के उत्थान के उद्देश्य हेतु कई पहलों की शुरुआत की।

गरीब

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) से सभी के लिए खाद्य सुरक्षा

विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजना,
5 वर्षों के लिए बढ़ाई गयी, **81 करोड़** से अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य

पीएम आवास योजना से गरीबों के लिए पक्के मकान

पीएम आवास योजना 4 करोड़ से अधिक पक्के घर
अपने घर का सपना पूरा कर सम्मान से जीवन जीने का मिला अधिकार

पीएम उज्ज्वला योजना से धुआं रहित रसोई

10.33 करोड़ से ज़्यादा परिवार
खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन कनेक्शन के साथ जी रहे स्वस्थ जीवन

> **"भारत बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। आज लोगों का आत्मविश्वास, सरकार के प्रति उनका विश्वास, और नए भारत के निर्माण का संकल्प चारों तरफ दिखता है।"**
>
> - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

गरीब अन्नदाता युवा नारी शक्ति का सशक्तिकरण

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र के समावेशी विकास पर विशेष जोर दिया है, और इसलिए उन्होंने हमें GYAN: गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने का रोडमैप दिया है।

महिलाओं के लिए सामुदायिक सहायता

10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ीं; **3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी** बनाने का संकल्प

युवा

मुद्रा योजना से युवा उद्यमियों के लिए ऋण

युवा भारत के सपनों को पंख देने और आत्मनिर्भरता के अवसर पैदा करने के लिए ₹ **33.8 लाख करोड़** से अधिक के **52.5+ करोड़** ऋण स्वीकृत

स्टार्टअप इंडिया के तहत स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार सृजन

भारत तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न सिस्टम बन गया है। **1,60,000+** मान्यता प्राप्त स्टार्टअप **17.6 लाख** से अधिक रोजगार का सृजन कर रहे हैं

खेल जगत में खुले नए द्वार

खेलो इंडिया और टारगेट ओलंपिक पोडियम जैसी योजनाओं से प्रेरित होकर टोक्यो ओलंपिक, पैरालंपिक और हांगझोऊ एशियन गेम्स में **भारतीय खिलाड़ियों का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन**

अन्नदाता

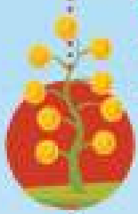

पीएम किसान सम्मान निधि से खुशहाल किसान

किसानों को हर साल ₹ 6,000 की आय सुनिश्चित की गई; उनकी वित्तीय सुरक्षा के लिए अब तक **11+ करोड़ किसानों को ₹ 3.7 लाख करोड़ की सहायता** की सहायता दी गई

किसान क्रेडिट कार्ड से तत्काल ऋण की सुविधा

किसान क्रेडिट कार्ड के साथ **7.71 करोड़ किसानों को ₹10 लाख करोड़** प्रदान किए गए हैं, जिससे कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों के लिए उनकी अल्पकालिक कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण तक सरल और किफायती पहुंच संभव हो गई है।

कृषि अवसंरचना कोष से कृषि बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण

एआईएफ के तहत **₹1 लाख करोड़** के निवेश को स्वीकृति दी गई, जो खेती के तरीकों को आधुनिक बनाने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

नारी शक्ति

सुकन्या समृद्धि योजना से बेटियों के लिए वित्तीय सुरक्षा

10 वर्ष से कम उम्र की हर बेटी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए **4.2 करोड़ सुकन्या समृद्धि खाते खुले,** एक सशक्त भविष्य का वादा

जल जीवन मिशन से स्वच्छ पेयजल

15.6 करोड़ से अधिक परिवारों के लिए नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की सभी महिलाओं ओर परिवारों का अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित

किसानों की आय बढ़ाना, खेती का खर्च कम करना, बीज से बाजार तक किसानों को आधुनिक सुविधाएं देना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है।

-नरेन्द्र मोदी

किसानों का कल्याण सुनिश्चित

2

सारांश

किसान, कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियाँ हमेशा से भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन और अर्थव्यवस्था की प्रमुख घटक रहीं हैं। पिछले 11 वर्षों में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के "बीज से बाजार तक" के दृष्टिकोण पर आधारित मार्गदर्शन से भारतीय कृषि को नयी गति मिली है।

सरकार ने किसानों को धनराशि का सुनिश्चित नकद हस्तांतरण करते हुए, पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनकी आय को समर्थन दिया है। प्रत्यक्ष नकद धनराशि अंतरण के जरिये किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 प्रदान किये जाते हैं। नियमित किस्तों के माध्यम से प्राप्त होने वाली इस पूरक आय ने बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर दिया है तथा छोटे और सीमांत किसानों को भी बेहतर गुणवत्ता के इनपुट खरीदने, अपनी भूमि की उत्पादकता में सुधार करने और अपनी आय बढ़ाने के प्रति सक्षम बनाया है।

कृषि से जुड़े जोखिमों के प्रभाव को कम करने के लिए, सरकार ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना शुरु की जो एक कृषि बीमा प्रणाली है तथा बेमौसम बारिश, कीट क्षति, फसल कटाई के बाद के नुकसान आदि कारकों के खिलाफ किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना ने सिंचाई कवरेज का विस्तार किया है। भारत के खाद्यान्न उत्पादन ने 2024- 25 में 347 एमएमटी का नया रिकार्ड बनाया है।

परिणाम सभी के सामने हैं, 2021-22 की कोविड-अवधि के दौरान, भारत के खाद्यान्न उत्पादन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया तथा 2022-23 के अनुमान और भी अधिक उत्पादन का संकेत देते हैं। बागवानी क्षेत्र में भी तेजी से विकास हुआ है। भारतीय कृषि के संबद्ध क्षेत्रों - पशुधन, वानिकी और लकड़ी आपूर्ति, मत्स्य पालन तथा जलीय-कृषि में तेज वृद्धि देखी जा रही है और ये क्षेत्र कृषि आय के संभावित स्रोत बन रहे हैं।

आठ करोड़ से अधिक किसानों को रोजगार देने वाला डेयरी क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। भारत विश्व स्तर पर दुग्ध उत्पादन में प्रथम, अण्डा उत्पादन में द्वितीय, मत्स्य उत्पादन में द्वितीय तथा मांस उत्पादन में पंचम स्थान पर है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र की विकास क्षमता का उपयोग करने के लिए, सरकार ने कृषि अवसंरचना निधि की शुरुआत की है। यह वर्ष 2020-21 से 2032-33 तक फसल कटाई के बाद के लिए आवश्यक प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के निर्माण के लिए एक वित्तपोषण सुविधा है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट (श्री अन्न) वर्ष घोषित किया गया । मोटे अनाज, मनुष्यों द्वारा खेती की जाने वाली सबसे पुरानी फसलों में से एक हैं और इन्हें भविष्य की फसलें भी कहा जाता है। सुपरफूड के रुप में इनके मूल्य को दर्शाने के लिए मोटे अनाजों को 'श्रीअन्न' का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री के शब्दों में, "मोटे अनाज उपभोक्ता, किसान और जलवायु के लिए अच्छे हैं।"

2014 से सरकार की प्राथमिकता, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करने की रही है। इसे 'स्मार्ट' खेती की ओर आगे बढ़ते हुए लगातार बदलाव करने के जरिये किया जा रहा है। सरकार द्वारा जारी किए गए मृदा स्वास्थ्य कार्डों के उपयोग से किसानों को विभिन्न इनपुट का कुशल उपयोग करने और उनकी उपज को अधिकतम करने में मदद मिली है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) जैसे कई कार्यक्रमों, जो रसायन मुक्त और जलवायु स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देते हैं, के माध्यम से छोटे किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों से इनपुट पर कम निवेश, उच्च कृषि आय और जलवायु परिवर्तन के खतरों व विभिन्न अनिश्चितताओं से सुरक्षा आदि का लाभ मिला है।

"बीज से बाजार तक" के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए कृषि उपज की तैयारी के बाद की व्यवस्थाओं को मजबूत करना आवश्यक है। ई-एनएएम पहल के माध्यम से पूरे देश में कृषि बाजारों को जोड़ने से पारदर्शिता आई है और कृषि बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है।

पिछले 11 वर्षों में भारतीय कृषि क्षेत्र से जुड़ी पूरी व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है, जिससे यह आधुनिक, वैज्ञानिक और समृद्ध बन गया है। आज, भारतीय किसान न केवल भारत के लिए खेती कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में अपने उत्पादों के व्यापक बाज़ार के रूप में देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि दुनिया के हर खाने की मेज़ पर भारतीय उत्पाद हों।

* * *

मुख्य बातें

वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2025-26 में कृषि बजट में
5 गुना
की वृद्धि

कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से
₹1 लाख करोड़

प्रधानमंत्री किसान लाभार्थियों को
₹3.7 लाख करोड़
वितरित किए गए

करीब
25 करोड़
मृदा स्वास्थ्य कार्ड
वितरित किए गए

वर्ष 2025-26 में **केसीसी** के तहत ऋण सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर
₹5 लाख
की गई

पीएम फसल बीमा योजना के तहत दावों में
₹1.75 लाख
से अधिक का निपटान

एमएसपी पर **दलहन** खरीद में
7350%
की वृद्धि

पीएम धन धान्य कृषि योजना से 100 जिलों के
1.7 करोड़
किसानों को लाभ

eNAM के माध्यम से अब
1473 मंडियां
जुड़ी हुई हैं

एमएसपी पर **तिलहन** खरीद में
1500%
की बढ़ोतरी

2021-26 के लिए **पीएम कृषि सिंचाई योजना** के लिए
₹93,000+ करोड़ आवंटित

उच्च उपज वाले बीजों पर
राष्ट्रीय मिशन
के लिए
₹100 करोड़
की घोषणा

उपलब्धियां

जोखिम से किसानों को सुरक्षा

MSP में ऐतिहासिक बढ़ोतरी
लागत से 50% अधिक MSP ने किसानों को कीमतों में उतार-चढ़ाव से दी सुरक्षा

PM Kisan के माध्यम से निश्चित आय
11 करोड़ से अधिक किसानों को ₹6,000 की सालाना निश्चित आय

मामूली प्रीमियम पर फसल बीमा
₹ 1.75 लाख करोड़ से अधिक के क्लेम बीमाधारी किसानों को दिए गए

वर्षा जल पर निर्भरता कम
पीएमकेएसवाई के तहत वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए ₹93000 सेअधिक करोड़ के निवेश के साथ 112 सिंचाई परियोजनाएं

खेती को तकनीक से जोड़तीं 'नमो ड्रोन' दीदी

बीज से बाजार तक

- मोदी सरकार भारतीय किसानों के साथ खड़ी है और Agriculture Cycle के सभी चरणों में मदद दे रही है।
- **Seeds से Soil Health, Insurance से Irrigation, MSP से Markets** तक-एक व्यापक अप्रोच ने किसानों को हर कदम पर मजबूत बनाया है।

आय बढ़ाने के लिए किसानों को बाजारों से जोड़ा गया

- **eNAM**: एकीकृत राष्ट्रीय बाजार से प्रतियोगिता बढ़ी। कृषि उत्पादों के लिए बेहतर कीमत मिली।
- **किसान उत्पादन संगठन**: FPO के जरिए बिक्री से बेहतर कीमत मिलना संभव हुआ और किसानों की आमदनी बढ़ी।
- **अग्रिम कड़ी:** वर्ष 2014 से वर्ष 2024 में मेगा फूड पार्कों की संख्या में 3 से बढ़कर 24 हो गई है
- **कृषि में स्टार्ट-अप इकोसिस्टमम:** आरकेवीवाई के नवाचार और कृषि-उद्यमिता कार्यक्रम के तहत वित्त वर्ष 2019-20 से 2024-25 के दौरान अब तक 1943 कृषि-स्टार्टअप को तकनीकी और वित्तीय सहायता दी गई है।
- **प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र** 1 लाख 80 हज़ार से अधिक प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र वन स्टॉप शॉप के रुप में विकसित; घर के नजदीक ही किसानों को मिल रहीं अत्याधुनिक सुविधाएं और जानकारी

* * *

सरकार के बड़े काम

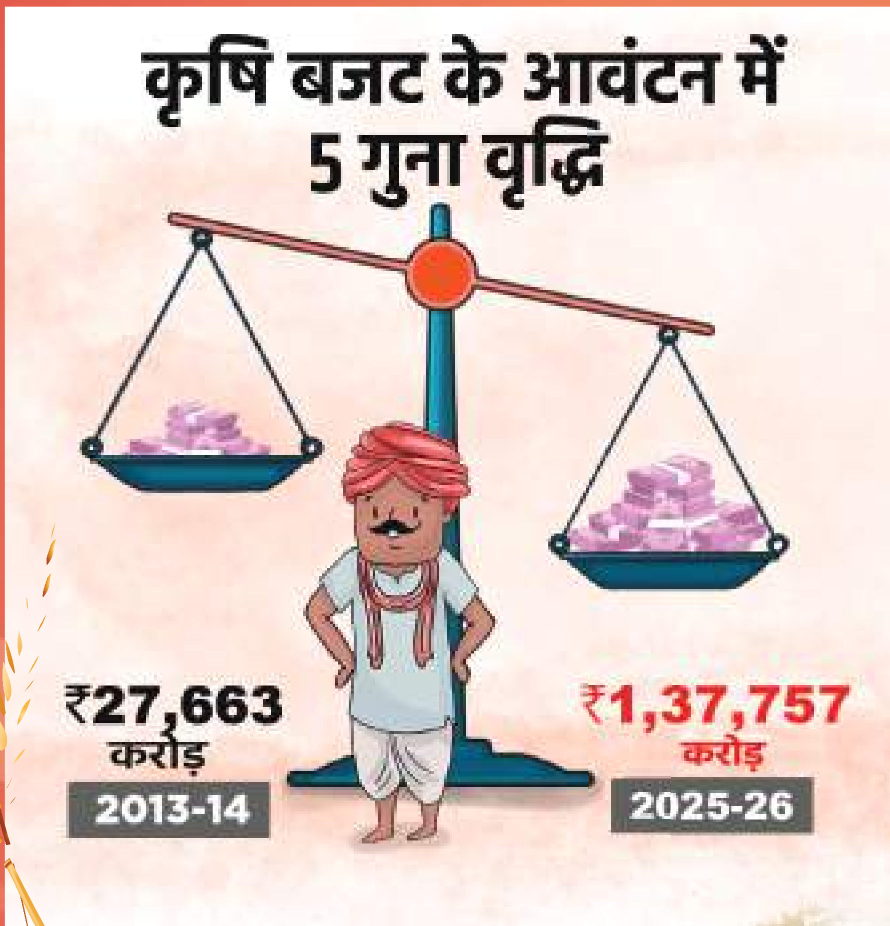

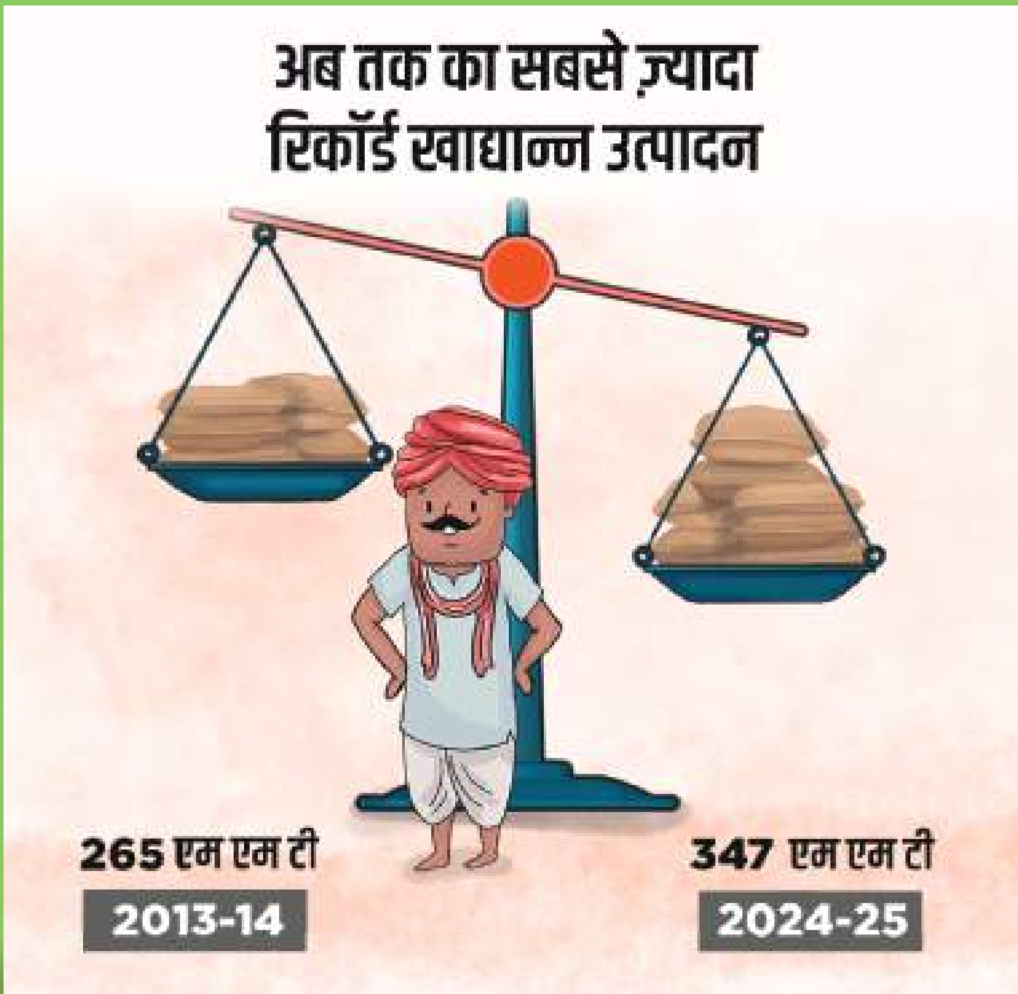
अब तक का सबसे ज़्यादा
रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन
265 एम एम टी
2013-14
347 एम एम टी
2024-25

चावल के एम एस पी का भुगतान (ग्रेड-ए)
₹ 1345
प्रति क्विंटल
2013-14
₹ 2203
प्रति क्विंटल
2023-24

गेहूँ के लिए एम एस पी का भुगतान
₹ 1350
प्रति क्विंटल
2013-14
₹ 2125
प्रति क्विंटल
2023-24

एम एस पी पर दालों की खरीद में वृद्धि
1.52
एल एम टी
2009-14
82.98
एल एम टी
2020-25

गेहूँ के लिए एम एस पी का भुगतान
₹ 2.26
2004-14
₹ 6.04
2014-24

किसानों की आय के साधन बढ़े

सोलर पैनल

बंजर भूमि पर सोलर पैनल लगा कर आमदनी में बढ़ोतरी को प्रोत्साहन

दुग्ध उत्पादन में वृद्धि

63.56% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज करते हुए दूध उत्पादन 14.6 करोड़ टन से बढ़कर 23.9 करोड़ टन हुआ।

Blue Revolution की शुरुआत

मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अलग विभाग का गठन, मत्स्य उत्पादन रिकॉर्ड 184 लाख टन तक पहुंचा।

SWEET REVOLUTION

पिछले 11 वर्षों में शहद के निर्यात में तीन गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है

इथेनॉल की खरीद

इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) में अप्रैल 2025 तक इथेनॉल की खरीद में 2013-14 में 38 करोड़ लीटर से 440+ करोड़ लीटर की वृद्धि हुई

अंतर्राष्ट्रीय मिलेट (श्री अन्न) वर्ष

मोटे अनाज के महत्व को पहचान कर लोगों को पोषक भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराने और स्वदेशी व वैश्विक मांग का सृजन करने के क्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को **अंतरराष्ट्रीय मिलेट (श्री अन्न) वर्ष** के रूप में घोषित कराने में अग्रणी भूमिका निभाई। भारत के इस प्रस्ताव को 72 देशों ने समर्थन दिया और मार्च 2021 में ही संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट (श्री अन्न) वर्ष के रूप में घोषित कर दिया।

पहले और अब

ऑपरेशनल मेगा फूड पार्कों में ऐतिहासिक वृद्धि

पहले	अब
2014 से पहले	2024 के बाद
3	24

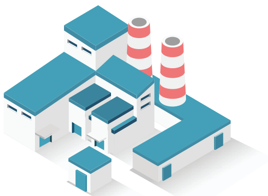

किसानों के लिए सौर पंपों की मांग में 92 गुना से अधिक की वृद्धि

पहले	अब
1992-14	2014-25
0.116 लाख	10.74 लाख

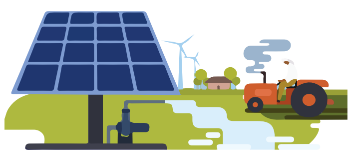

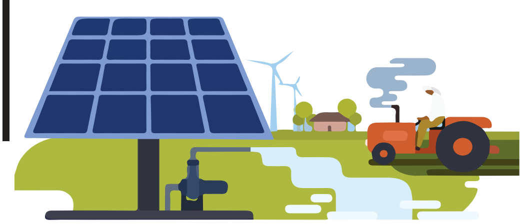

पहले और अब

खाद्य प्रसंस्करण क्षमता में 20 गुना से अधिक वृद्धि

पहले	अब
2013-14	2024-25
12 लाख मीट्रिक टन	242 लाख मीट्रिक टन

प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में लगभग 2 गुना वृद्धि

पहले	अब
2013-14	2024-25
4.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर	9.03* बिलियन अमेरिकी डॉलर

*अप्रैल 2024-फरवरी 2025

सहकारिता: समावेशी विकास को बढ़ावा

सहकारिता भारत की विरासत का अभिन्न अंग रहा है

हमारे धर्मग्रंथों के अनुसार, "अल्पानाम् अपि वस्तूनाम्, संहतिः
कार्य साधिका ||"

यहाँ तक कि छोटी-छोटी चीजें या सीमित संसाधनों को
एकजुट करने पर महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं

श्री नरेंद्र मोदी

माननीय प्रधानमंत्री

सहकारिता क्षेत्र में अनेक प्रमुख पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास समारोह (24 फरवरी, 2024)

क्यूआर कोड स्कैन

सहयोग की भावना को पुनर्जीवन

सामूहिक प्रगति के भारत के सदियों पुराने मूल्यों पर आधारित, सहकारिता आंदोलन एक सुदृढ़ पुनरुद्धार के दौर से गुजर रहा है। प्रणालीगत अक्षमताओं के कारण एक बार कमजोर हो चुका यह आंदोलन अब 2021 में स्थापित सहकारिता मंत्रालय के तहत सुधारों के माध्यम से पुनः ऊर्जावान हो गया है।

संस्थागत सुधार और डिजिटल सशक्तिकरण

- 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अपनाए गए आदर्श उपनियमों से 1 लाख से अधिक प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को डेयरी, जल, ईंधन और फार्मा सेवाओं सहित 25 से अधिक गतिविधियों में विविधता लाने में मदद मिलेगी।
- नाबार्ड से जुड़े 70,641 पीएसीएस (59,810 शामिल) के ईआरपी-आधारित कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन।
- एनसीसीएफ/नेफेड द्वारा नए प्लेटफॉर्म एमएसपी खरीद को सुव्यवस्थित करते हैं, जबकि राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस और रैंकिंग फ्रेमवर्क पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं।.

बुनियादी ढांचा और आय विस्तार

• 20,707 नई सहकारी समितियां बनाई गईं; 7,109 डेयरी समितियों को मजबूत किया गया।

• विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत गई: 11 पायलट गोदाम (9,750 मीट्रिक टन) और 500 से अधिक निर्माणाधीन।

• प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) निम्नलिखित रुप में कार्य करती हैं:

- सीएससी (ई-सेवाओं में 81.6 करोड़ की 46,571 डिलीवरी),
- जन औषधि केंद्र (753 प्रचालन),
- पीएमकेएसके (36,592 अपग्रेड किए गए),
- एलपीजी/ईंधन डीलर, जल आपूर्ति प्रबंधक और एफपीओ।

वैश्विक दृष्टिकोण वाली राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियाँ

- एनसीईएल: ₹5,396 करोड़ का निर्यात; 9,425 सदस्य।
- बीबीएसएसएल: प्रमाणित बीजों के लिए 21,037 सदस्य।
- एनसीओएल: 7,037 सदस्य; ₹167.1 लाख मूल्य के 24 जैविक उत्पाद लॉन्च किए गए।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया, भारत वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने के लिए तैयार

सहकार से समृद्धि

- **01** 32,000 से अधिक पीएसीएस को ईआरपी सिस्टम में शामिल किया गया
- **02** नए डेटाबेस के अंतर्गत 8.32 लाख सहकारी समितियां शामिल हैं।
- **03** श्वेत क्रांति 2.0 के तहत डेयरी सहकारिता समितियों को बढ़ावा मिला है।
- **04** 2025 को अन्तराष्ट्रिय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया (आईवाईसी)
- **05** प्रदर्शन आधारित सहकारी मूल्यांकन के लिए रैंकिंग फ्रेमवर्क
- **06** चीनी मिलों में मक्के से एथनॉल बनाने के लिए सहायता दी गई
- **07** नाबार्ड के तहत साझा सेवा इकायों की स्थापना
- **08** मक्का हाईब्रीड विकास के लिए बीबीएसएसएल- आईसीएआर समझौता ज्ञापन
- **09** राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का बनाया जाना प्रस्तावित है
- **10** 68.9 लाख सहकारी सदस्यों को रुपे केसीसी दिए गए
- **11** 17,163 बहुउद्देशिय सहकारिता समितियां पंजीकृत या सुदृढ़ हुईं।
- **12** आईसीए वैश्विक सम्मेलन में 3,000 से अधिक सहकारी नेताओं की प्रतिभागिता
- **13** जैविक खेती के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
- **14** एनसीडीसी के द्वारा मिलने वाले ऋण वितरण की राशि बढ़कर 95,000 करोड़ हुई
- **15** देश भर में पीएसीएस कंप्यूटरीकरण के लिए एसओपी जारी की गई
- **16** सुनिश्चित मक्का की पुनः खरीद के माध्यम से बायोएथानॉल को बढ़ावा

भारत में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना चल रही है

त्रिभुवनदास पटेल विश्वविद्यालय: प्रथम राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय

सहकार से समृद्धि

क्या आप
जानते हैं?
NABARD

प्रधानमंत्री
किसान समृद्धि केन्द्र
पीएमकेएसके
को गति दे
रहा है
पीएसीएस

पीएसीएस के
प्रमुख लाभ
डिजिटलीकरण

राष्ट्रीय सहकारिता
निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल)

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
(IYC), 2025
के उद्देश्य

आयकर अधिनियम
के तहत सहकारी समितियों
के लिए कर राहत के
मुख्य बिंदु
सरचार्ज में कमी
न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) में कमी
नई निर्माण सहकारी समितियों पर कर में कटौती
नकद जमा और ऋण सीमा में वृद्धि
नकद निकासी पर TDS सीमा में वृद्धि
नकद लेन-देन में राहत (धारा 269ST)
INCOME TAX
ACT

“

शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलायें हों, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलायें हों, या घर के काम में व्यस्त महिलायें हों, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते 10वर्षों में सरकार ने अनेक कदम उठाएँ हैं।

-नरेन्द्र मोदी

”

नारी शक्ति को मिला नया बल

3

सारांश

भारत का विकास दरअसल देश की महिलाओं के विकास से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बीते 11 वर्षों में नारी शक्ति को भारत की विकास यात्रा में सबसे आगे रखा है।

मोदी सरकार का मानना है कि सशक्तिकरण वन स्टॉप समाधान नहीं है, बल्कि इसके लिए महिला सशक्तिकरण के लिए जीवनचक्र-आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस संबंध में, महिलाओं के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम इस तरह से तैयार किए गए हैं कि जीवन के विभिन्न चरणों में उनके सशक्तिकरण के लिए सामाजिक आर्थिक बाधाओं को दूर करने में उनकी सहायता की जा सके।

मिशन पोषण एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है ताकि बच्चों, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान किया जा सके। इसमें पोषण सामग्री और वितरण में एक रणनीतिक बदलाव लाया गया है और इसमें एक ऐसे सम्मिलित इकोसिस्टम का निर्माण किया जाता है जो ऐसी प्रथाओं को विकसित और प्रोत्साहित करे जो स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा का पोषण करती हों। मिशन शक्ति की बात करें तो इसमें महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए दो उप-योजयएं संबल और सामर्थ्य शामिल है। नारी अदालत के एक नए घटक के साथ वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (181-डब्ल्यूएचअल), और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) की मौजूदा योजनाओं को संबल उप-योजना का हिस्सा बनाया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), शक्ति सदन (उज्ज्वला और स्वाधार गृह), कामकाजी महिला छात्रावास (सखी निवास) और राष्ट्रीय शिशुगृह योजना (पालना) जैसी योजनाओं को सामर्थ्य में शामिल किया गया है।

इन पहलों का प्रभाव परिणामों में स्पष्ट हो रहा है,जैसे कि शिशु जन्म दर में बेहतर लिंगानुपात, जो अब पहली बार प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हुआ है, वहीं संस्थागत प्रसव में वृद्धि, शिशु मृत्यु दर में कमी और मातृ मृत्यु दर में कमी आई है।

मोदी सरकार के लिए महिलाओं को सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान करना शासन की आधारशिला है। यह वादा उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडरों के बढ़ते उपयोग में खुद को प्रकट करता है, जिसने करोड़ों महिलाओं को धुआँ मुक्त रसोई के माध्यम से पुरानी श्वसन संबंधी बीमारियों से बचाया है। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के साथ, करोड़ों महिलाएँ अब बिना किसी सुरक्षा या सम्मान के उल्लंघन के अपने घरों में शौचालय का उपयोग करने में सक्षम हैं। दैनिक उपयोग के लिए पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करना अतीत की बात हो गई है क्योंकि देश भर के घरों को जल जीवन मिशन के तहत नल के पानी के कनेक्शन मिल रहे हैं, जिससे यह कष्ट समाप्त हो गया है।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के बिना महिला सशक्तिकरण निरर्थक है। उदाहरण के लिए, मुद्रा लोन का 68% या 14.72 लाख करोड़ रुपये के 35.38 करोड़ लोन महिला उद्यमियों को दिए गए, जिससे देश भर में करोड़ों महिलाओं को सूक्ष्म स्तर की उद्यमिता को आगे बढ़ाने तथा आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में सहायता मिली। महिलाओं के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के एक भाग के रूप में महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र पेश किया गया, जो विशेष रूप से महिला निवेशकों के लिए एक छोटी बचत योजना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत महिलाओं को घर का मालिक बनाया जा रहा है, जिससे वे घरेलू निर्णय लेने में सक्रिय भागीदार बन रही हैं।

मोदी सरकार के 11 सालों में महिलाओं की स्थिति दिन-प्रतिदिन बेहतर होती गई है। उनकी सफलता महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि, देश के लिए खिलाड़ियों द्वारा जीते गए पुरस्कारों और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में महिलाओं के नामांकन में देखी जा सकती है। अब महिलाएं विकास में वास्तविक भागीदार हैं, जबकि पहले के दौर में योजनाओं के नाम पर उनके आँखों में धूल झोंका जाता था। आज यह महिला विकास नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास है।

* * *

मुख्य बातें

भारत में पहली बार प्रति 1,000 पुरुषों पर

1,020 महिलाएं

(एनएफएचएस-5)

सवेतन मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर

26 सप्ताह

किया गया

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत

6 करोड़

से अधिक निःशुल्क प्रसवपूर्व जांच की गई

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत

3.98 करोड़

से अधिक गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को **₹18,593 करोड़** से अधिक की राशि वितरित की गई

जन औषधि केंद्रों में **₹1** की दर से

77 करोड़

से अधिक सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए गए

4.2 करोड़

सुकन्या समृद्धि खाते

10.33 करोड़

से अधिक धुआँ मुक्त रसोई

लगभग 2.75 करोड़ **पीएम आवास-ग्रामीण लाभार्थियों** में से

73%

महिलाएँ हैं

10 करोड़

महिलाओं को 90 लाख से अधिक **स्वयं सहायता समूहों (एस एच जी)** में संगठित किया गया है

महिलाओं को

₹14.72 लाख करोड़

के 35.38 करोड़ (68%) मुद्रा ऋण दिए गए

2023 में

मातृ मृत्यु दर

घट कर 80 हो गई है

3 करोड़

महिलाओं को **लखपति दीदी** बनाने का संकल्प

उपलब्धियां

महिलाएं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का समर्थन क्यों करती हैं- महिला सशक्तिकरण के लिए सामाजिक परिवर्तन

- महिलाओं की **विवाह योग्य आयु** 18 से **बढ़ाकर** 21 वर्ष करने का प्रस्ताव शिक्षा और रोजगार के अवसरों में मदद करता है।।
- **तीन तलाक के खिलाफ कानून** से मुस्लिम महिलाओं की शोषण से सुरक्षा।
- **Paid Maternity Leave की अवधि** 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने से कामकाजी महिलाओं के लिए जीवन हुआ आसान।
- **Article 35A** के अंत से जम्मू-कश्मीर में महिलाओं को वो अधिकार मिले, जिन्हें पहले ऐतिहासिक रुप से नकार दिया गया था।

* * *

सरकार के बड़े काम

क्या आप जानते हैं ?

मुद्रा योजना के तहत 52+ करोड़ ऋण लेनेवालों में 68% महिला उद्यमी हैं। इसके अतिरिक्त 50 हजार से अधिक स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक।

10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ीं; 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का शपथ

जीवन चक्र आधारित अप्रोच व्यापक स्तर पर मददगार

जन्म

चुनौती:
जन्म लेने की

समाधान:
बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

परिणाम:
भारत का लिंगानुपात 1020 (प्रति 1000 पुरुषों) हुआ [NFHS-5]

बेटियां

चुनौती:
पोषण तक पहुंच

समाधान:
मिशन पोषण

परिणाम:
15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान ₹1.81 लाख करोड़ से अधिक मूल्य का 'एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम-मिशन पोषण 2.0' लागू किया जाएगा

स्कूलिंग

चुनौती:
अलग शौचालय तक पहुंच

समाधान:
स्वच्छ विद्यालय ने हर स्कूल में शौचालय सुनिश्चित किया

परिणाम:
सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए लगभग 9.8 लाख अलग शौचालय का निर्माण

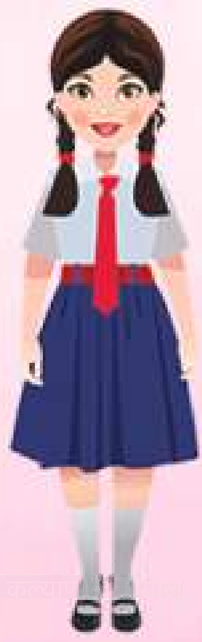

शिक्षा

चुनौती:
वित्तीय संसाधनों तक पहुंच

समाधान:
45 लाख लड़कियों / महिलाओं को छात्रवृत्ति

परिणाम:
मार्च 2025 तक 4.2 करोड़ सुकन्या समृद्धि खातों में ₹3 लाख करोड़ की शुद्ध जमा राशि

महिलाओं को हर कदम पर, प्रत्येक निर्णय और हर अवस्था में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसी पहल की है, जहां हर चुनौती के लिए एक समाधान है।

राष्ट्र की सेवा

चुनौती:
सशस्त्र बलों में प्रवेश प्रतिबंधित

समाधान:
सभी विंग में महिलाओं को स्थायी कमीशन

उद्यमिता

चुनौती :
फंड तक पहुंच

समाधान:
मुद्रा योजना के तहत 52.5+ करोड़ ऋण लेने वालों में 68% महिला उद्यमी हैं

परिवार

चुनौती :
निर्णय लेने की शक्ति

समाधान:
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण घरों की 73% एकल/संयुक्त स्वामी महिलाएँ हैं

महिलाओं से संबंधित विभिन्न नतीजों में सुधार

पहली बार भारत का समग्र लिंग अनुपात 1020 # हुआ
(प्रति 1000 पुरुष) [NFHS-5]
#कुल आबादी का लिंगानुपात

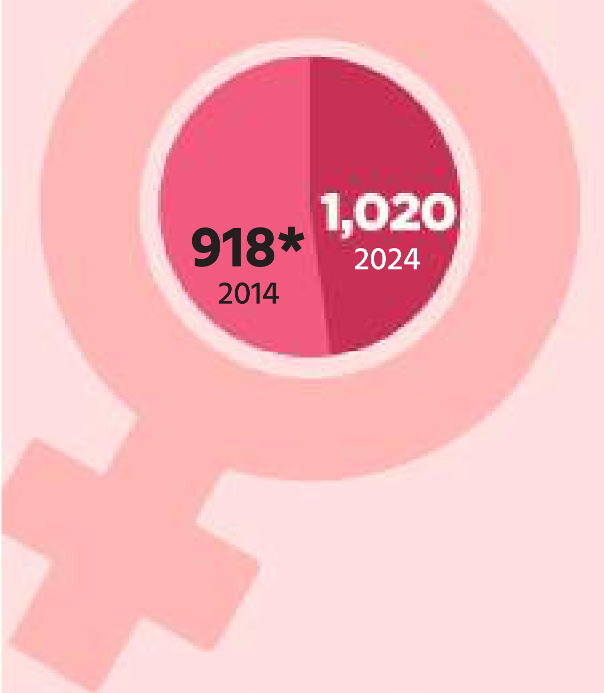

मातृ मृत्यु दर

*जन्म के समय लिंगानुपात

नारी शक्ति वंदन अधिनियम

से महिलाओं के नेतृत्व में विकास सुनिश्चित

"आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं, तो बहुत आवश्यक है कि नीति-निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। योगदान ही नहीं, वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।"

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

नारी शक्ति वंदन अधिनियम: देशभर में खुशी की लहर

- नारी शक्ति वंदन अधिनियम से भारत ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ाए **मजबूत कदम**।
- लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों ने उनकी **आवाज़ को सशक्त बनाया**।
- आरक्षित कोटे के अंतर्गत **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण**।
- यह अधिनियम **लैंगिक समानता** और **समावेशिता** के प्रति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- यह कानून **महिला नेतृत्व को बढ़ावा** देता है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में महिलाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।

निरंतर आगे बढ़ती नारी शक्ति

- रक्षा सेवाओं में **महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन** प्रदान किया गया।
- **सैनिक स्कूल अब लड़कियों के लिए भी खुले।**
- **सशस्त्र बलों ने राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी (एनडीए) में महिला उम्मीदवारों** के लिए प्रवेश खोले।
- जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर **पहली बार** राइफल महिलाओं की तैनाती।
- **दुनिया भर में सबसे ज़्यादा महिला पायलट भारत में हैं।**
- 100 से अधिक **महिलाओं ने चंद्रयान-3** मिशन को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- भारत में लगभग **50% स्टेम (एसटीईएम) स्नातक** महिलाएँ हैं जोकि विश्व में उच्चतम है

पहले और अब

अब भारत की राजनीति में महिला नेताओं के लिए मतदान दुर्लभ नहीं होगा!

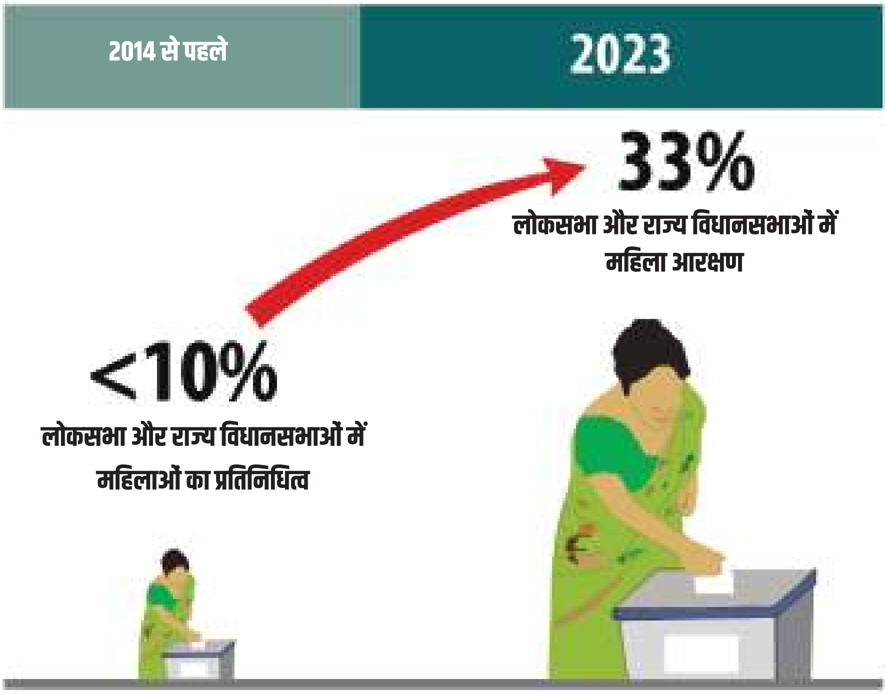

सरकारी प्रयास से आईआईटी में महिलाओं के नामांकन में अच्छी बढ़त में सफलता

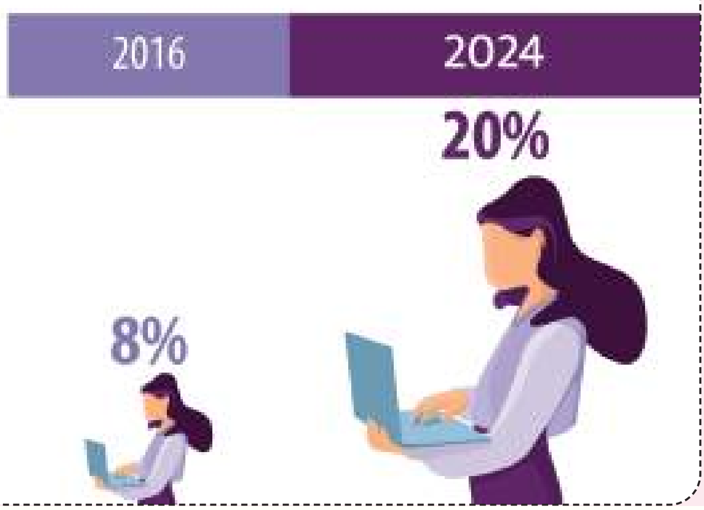

पहले और अब

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने सामूहिक चेतना जगाई बढ़ा लिंग अनुपात

(NFHS-5)

2024

1020
प्रति 1000 पुरुषों पर

2014

918*
प्रति 1000 पुरुषों पर

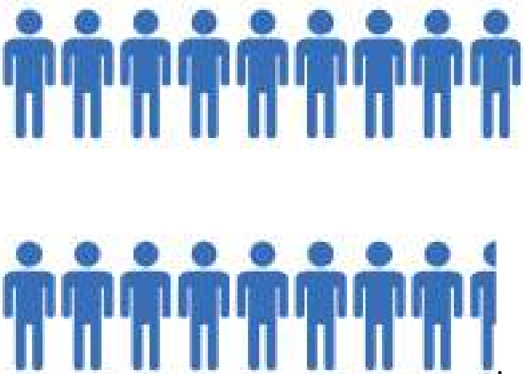

* जन्म के समय लिंग अनुपात

मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन जागरूकता अभियान का उल्लेखनीय प्रभाव

2020 से पहले	वर्ष 2023
11% ग्रामीण क्षेत्र में सैनिटरी पैड के उपयोग में वृद्धि	**45%** ग्रामीण क्षेत्र में सैनिटरी पैड के उपयोग में वृद्धि

विकसित भारत के विज़न को लेकर देश की
अमृतयात्रा का नेतृत्व हमारे युवा ही कर रहे हैं।

-नरेन्द्र मोदी

4

भारत की अमृत-पीढ़ी हो रही सशक्त

सारांश

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह बयान खासा चर्चित रहा है, "दुनिया ने मान लिया है कि भारत के पास दो असीमित शक्तियां हैं - जनसांख्यिकी और लोकतंत्र।" भारत में वर्तमान में दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अपनी इस क्षमता का पूर्ण रुप से दोहन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) ने 30 साल से ज्यादा वक्त के बाद मौजूदा शिक्षा प्रणाली का कायाकल्प कर दिया है। एनईपी भारतीय स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में एक आदर्श बदलाव की कल्पना करती है जो भारतीय लोकाचार में निहित है, अधिक ज्ञान पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर ज्ञान की महाशक्ति बनाना है। पिछले 11 साल के दौरान, देश भर में रिकॉर्ड संख्या में नए आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय खुले हैं। मोदी सरकार का शिक्षा के साथ-साथ शिक्षा, कौशल और कौशल विकास पर भी जोर रहा है। पीएम कौशल विकास योजना के लॉन्च के बाद से, 1.6 करोड़ से अधिक युवाओं ने इस योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिससे उनके लिए रोजगार की संभावनाओं में सुधार हुआ है।

युवाओं के लिए नए औपचारिक रोजगार सृजित करने की मोदी सरकार की प्राथमिकता की सफलता को नए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन खातों में भारी वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। भारत को निवेश के एक आकर्षक केंद्र में बदलने की दिशा में लगातार प्रयास, एमएसएमई को सहायता और घरेलू उत्पादन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आदि कार्यक्रमों ने युवा भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में योगदान दिया है।

सरकार ने केंद्र सरकार में 10 लाख नौकरियों के लिए एक भर्ती अभियान रोजगार मेला शुरु किया है। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर भी दिया जा रहा है। इससे सशस्त्र बलों में नए 'जोश' और 'जज़्बे' का संचार होगा, साथ ही तकनीक तौर पर ज्यादा कुशल सेना की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाएगा।

सरकार का जोर सिर्फ रोजगार सृजित करने पर ही नहीं, बल्कि उद्यमिता का विकास, युवाओं को रोजगार खोजने वाले से रोजगार देने वाला बनाने पर भी है। पहले जहां लोग जोखिम लेने से बचते थे और वेतनभोगी नौकरियों का विकल्प चुनते थे, इसके विपरीत आज युवा अनुकूल नीतिगत माहौल के कारण आगे बढ़ने को उत्सुक हैं।

2016 में शुरु किए गए स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से, मोदी सरकार ने कई कर लाभ प्रदान करके, नियमों को आसान बनाकर और अनुपालन बोझ को कम करके उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं।

उद्यमशीलता की तरह, खेल को अधिकांश युवाओं के लिए पेशेवर नहीं माना जाता था, और उन्हें इनमें पेशेवर रूप से आगे बढ़ने के प्रति हतोत्साहित किया जाता था। हालांकि, पीएम मोदी एक महत्वपूर्ण व्यवहार और मानसिकता में बदलाव लेकर आए और कई नीतियां पेश कीं, जिससे असंख्य युवाओं को खेल को करियर बनाने में मदद मिली है। भारत ने वर्ष 2021 में टोक्यो ओलंपिक और पैरालिंपिक के दौरान इतिहास में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन देखा है। यह मुख्य रूप से टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के माध्यम से दीर्घकालिक योजना और समर्थन का परिणाम रहा है।

जैसे कि भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है, इसका जनसांख्यिकीय लाभांश तेजी से सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी नवाचार और उन्नति के युग में प्रवेश करने के लिए विशिष्ट रूप से तैयार है। पिछले 11 वर्षों के दौरान सरकार अपने सभी लक्ष्यों और प्रयासों में युवाओं का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रही है।

* * *

मुख्य बातें

तीन दशक से अधिक समय बाद **राष्ट्रीय शिक्षा नीति**

1.6+ लाख मान्यता प्राप्त स्टार्टअप **17.6 लाख से अधिक** नौकरियां पैदा कर रहे हैं।

टॉप्स कार्यक्रम के तहत टॉप्स कोर ग्रुप में **94** और टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में **112** एथलीटों को मदद

ओलंपिक में पदकों की संख्या में इज़ाफा टोक्यो, पेरिस ओलंपिक और पैरालिंपिक में 61 पदक।

पीएम कौशल विकास योजना के तहत **1.6 करोड़** लोगों को प्रशिक्षित किया गया

8 नए आईआईएम स्थापित, 2023 तक कुल संख्या 21

पीएम श्री योजना के तहत **14,500 स्कूल** और बेहतर बनाए जाएंगे तथा उनका विकास होगा

2017-2024 में डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त **तकनीकी स्टार्ट-अप्स** द्वारा **4.8 लाख** से अधिक **प्रत्यक्ष नौकरियां** सृजित की गईं।

23 एम्स के साथ भारत में **एम्स की संख्या तिगुनी**

देशभर में **7 नए आईआईटी** खोले गए, 2025 तक कुल आईआईटी 23 हो जाएंगे; **6,500 सीटें** और जोड़ी जाएंगी

2,045 मेडिकल कॉलेज, जिनमें **780** एलोपैथी, **323** डेंटल और **942** आयुष संस्थान शामिल हैं।

490 नए विश्वविद्यालय स्थापित

उपलब्धियां

भारतीय युवा:नौकरी चाहने वालों से नौकरी देने वालों तक

- प्रधानमंत्री मोदी समाज की सोच बदल रहे हैं और **जोखिम लेने वालों के लिए व्यापक स्वीकृति** पैदा कर रहे हैं।
- स्वरोजगार और उद्यमिता लोकप्रिय व्यावसायिक विकल्प बन रहे हैं।
- विभिन्न योजनाओं का लक्ष्य **उद्यमियों को संस्थागत सहायता** देना है।

फिट इंडिया मूवमेंट - फिटनेस इन फ्रीडम

- राष्ट्रव्यापी अभियान नागरिकों को नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय दिनचर्या के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है।

भारतीय खेलों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

- भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2021 और पेरिस पैरालिंपिक 2024 में अपने इतिहास में अब तक का सबसे अधिक पदक जीता।
- 2014 से जारी दीर्घकालिक योजना से रिकॉर्ड सफलता मिली।
- **TOPS** कार्यक्रम के माध्यम से खिलाड़ियों को मिला व्यापक सहयोग ।
- **खेलो इंडिया खेलों को एक जन आंदोलन** बना रहा है और पूरे भारत में खेल संस्कृति का निर्माण कर रहा है।

युवा भारत के लिए रोजगार सुनिश्चित करना

- मजबूत आर्थिक नीतियों से हर साल लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं।
- भारत का कुल निर्यात 2024-25 में रिकॉर्ड $ 824.9 बिलियन तक पहुंच गया। यह 2013-14 में $ 466.22 बिलियन से एक महत्वपूर्ण छलांग है, जो पिछले दशक में निरंतर वृद्धि को दर्शाता है।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत **1.60 करोड़** लोगों को कौशल प्रदान किया गया, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े ।
- सितंबर 2017 और फरवरी 2025 के बीच **8.59 करोड़ नए ईपीएफओ** ग्राहक जुड़े –यानि इतने नए लोगों को नौकरी मिली।
- **महामारी के बावजूद** 2021-22 में **1.09 करोड़** नए ई.पी.एफ.ओ. खाते जोड़े गए।
- अधिकांश सर्वेक्षण **महामारी से पहले** के वर्षों की तुलना में **कम बेरोजगारी** और ज्यादा भर्तियों को लेकर मजबूत संकेत दे रहें हैं।
- **मुद्रा योजना** ने करोड़ों नए उद्यमियों को सहायता प्रदान की और रोजगार सृजित किए
- 2017-2024 में **DPIIT** द्वारा मान्यता प्राप्त टेक स्टार्ट-अप द्वारा **4.8 लाख** से अधिक **प्रत्यक्ष रोजगार** सृजित किए गए।

* * *

क्या आप जानते हैं?

प्रत्यक्ष नौकरी संकेतक

- अप्रैल 2020 से 18-28 वर्ष की आयु के बीच 3.45 करोड़ से अधिक युवा ईपीएफओ से जुड़े
- नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स- जो कि व्हाइट- कॉलर हायरिंग का एक प्रमुख बैरोमीटर है- अप्रैल 2025 में 2,878 अंकों पर रहा, जो कि अप्रैल 2021 से 39% की वृद्धि दर्ज करता है।
- सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा कौशल स्तर 6 और उससे ऊपर के लिए 40 योग्यता पैक (क्यूपी) बनाकर पूंजीगत सामान क्षेत्र में कौशल, पुनः कौशल और कौशल उन्नयन को बढ़ावा देना।
- डब्ल्यूआरआई त्रिची के तहत सीईएफसी ने त्रिची, रानीपेट, हरिद्वार, भोपाल, झांसी औ वाराणसी में अपने प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से विभिन्न वेल्डिंग तकनीकों में अब तक कुल 8,143 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है।

अप्रत्यक्ष नौकरी संकेतक

- भारत का कुल निर्यात 2024-25 में रिकॉर्ड $ 824.9 बिलियन तक पहुँच गया।
- इंजीनियरिंग निर्यात 2014-15 में $ 73 बिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2024- 25 में $ 117 बिलियन हो गया
- सभी वस्त्रों के रेडीमेड परिधानों के निर्यात में 2024-25 में 10% की वृद्धि देखी गई।

सरकार के बड़े काम

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा अधिनियम - गोपनीयता प्रथम

भारत का पहला डिजिटल गोपनीयता कानून 2023 में लागू किया गया।
डिजिटल अर्थव्यवस्था में नवाचार को बढ़ावा देते हुए व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए 2025 में मसौदा नियम जारी किए।

* मेडिकल के अन्तर्गत दंत चिकित्सा, एलोपैथी, आयुर्वेद और होमियोपैथी होंगे शामिल
ऑल इंडिया सर्वे ऑफ़ हायर एडुकेशन 2020-2021 के अनुसार

अग्निवीर: सेना में युवा शक्ति का संचार

15 जून, 2022 को शुरू की गई अग्निवीर योजना चार साल की सैन्य सेवा के लिए युवाओं की भर्ती करती है, जिसमें 30,000 रुपये मासिक वेतन, सेवा के बाद 11.71 लाख रुपये सेवा निधि, कौशल प्रमाणन और व्यापक समर्थन और करियर विकास के लिए 1.65 करोड़ रुपये शहादत मुआवजा दिया जाता है।

परीक्षा धोखाधड़ी पर नकेल कसना: 2024 अधिनियम भारत के भविष्य की रक्षा करता है!

सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2024 परीक्षा धोखाधड़ी के लिए कठोर दंड लागू करता है, सुरक्षित डिजिटल परीक्षा मानकों को अनिवार्य करता है, और देश भर में सार्वजनिक परीक्षाओं में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकारियों को मजबूत उपकरण प्रदान करता है।

हमारा लक्ष्य सभी का कल्याण और भलाई है। हमारा लक्ष्य सबका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण है।

-नरेन्द्र मोदी

मध्यम वर्ग का जीवन हुआ आसान

5

सारांश

एक घर का मालिक होना एक प्रतिष्ठित जीवन स्तर की निशानी है, जिसमें नल से पानी, खाना पकाने के लिए ईंधन, स्वच्छता, बिजली और इंटरनेट के साथ सुरक्षा बीमा, कर लाभ और सार्वजनिक उपयोगिताओं तक आसान पहुंच जैसी बुनियादी सुविधाएं हों। 2014 से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रत्येक भारतीय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अथक प्रयास किया है।

मोदी सरकार ने सभी भारतीयों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए एक घर के सपने को हकीकत में बदल दिया है। मोदी सरकार अपने कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि समाज के सभी वर्गों के नागरिकों को बैंकिंग, एलपीजी कनेक्शन, स्वच्छता, बिजली, नल का पानी, सस्ती स्वास्थ्य सेवा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। पीएम आवास योजना के तहत ब्याज दरों में कमी और मोदी सरकार की क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना ने लोगों को अपना पहला घर खरीदने में सक्षम बनाया है। इसके साथ-साथ, रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (आरईआरए, रेरा) अधिनियम 2016 को लागू करने जैसे कदमों के माध्यम से नियामक ढांचे को मजबूत करना यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों की जीवन भर की कमाई एक कानूनी ढांचे द्वारा सुरक्षित है जो घर खरीदने वालों के अधिकारों को सुरक्षित रखती है।

स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए इलाकों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना की दिशा में एक सुधारात्मक कदम है। इसमें ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि खंडों का मानचित्रण करना और संपत्ति के मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड (संपत्ति कार्ड/टाइटल डीड) जारी करने के साथ ग्रामीण क्षेत्र में घर के मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करना शामिल है।

कर में कमी और सस्ती उधार दरों ने मध्यवर्ग के परिवारों के लिए बड़े पैमाने पर बचत और उनके खर्च करने की क्षमता को बढ़ाया है। आयकर छूट और प्रत्यक्ष कर सुधारो में सकारात्मक बदलाव ने उन पर कर के बोझ को कम किया है और मध्यम वर्ग के लिए टैक्स भरने को आसान बना दिया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) उपभोक्ताओं के लिए दैनिक खर्चों में कमी का कारण बना है।

उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) योजना, जो अब अपने छठे वर्ष में है, ने आम आदमी के लिए हवाई यात्रा सस्ती और सुविधाजनक बना दी है। इसने कई टियर 2 और टियर 3 शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ा है और यह सुनिश्चित किया है कि हवाई यात्रा सभी के लिए सुलभ हो। 2014 के बाद से देश में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हो गई है।

शहरी नागरिकों के लिए परिवहन और दैनिक आवागमन को आसान बनाने के लिए कई शहरों में रिकॉर्ड संख्या में मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और चालू की गई है। नागरिक अब निजी वाहनों से सार्वजनिक परिवहन की ओर जा रहे हैं और अपने आराम से समझौता किए बिना काफी बचत कर रहे हैं।

भारत में उभर रही डिजिटल भुगतान क्रांति ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। मार्च 2025 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) पर लगभग ₹24.77 लाख करोड़ मूल्य के 1830.151 करोड़ यूपीआई पर लेनदेन किए गए।

इस प्रणाली का उपयोग अब करीब 46 करोड़ व्यक्तियों और 6 करोड़ पचास लाख व्यापारियों द्वारा किया जाता है। छोटे से छोटे लेनदेन के लिए भी डिजिटल भुगतान किया जा रहा है, जिसमें लगभग 50% को छोटे या सूक्ष्म भुगतान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

भारत के डिजिटल परिवर्तन और कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए, 5जी को 22 महीनों में देश के 99.6% जिलों में शुरू किया गया है, जो इसे सबसे तेज़ रोलआउट में से एक बनाता है। यह उच्च तकनीक प्रौद्योगिकी के साथ भारत के लिए बड़ी संभावनाएं बनाता है और कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, स्मार्ट शहरों, उद्योग 4.0, वित्तीय समावेशन आदि सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परिवर्तन लाने का मार्ग प्रशस्त करता है। सरकार ने पिछले 11 वर्षों में विभिन्न उपायों के माध्यम से अपने नागरिकों के दैनिक जीवन में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया है। सभी भारतीयों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का यह प्रयास "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास" प्रधानमंत्री के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है।

* * *

मुख्य बातें

12.75 लाख रुपये
तक की आय तक
फुल टैक्स रिबेट

देश के **99.6%** जिलों में
सिर्फ 22 महीनों में
5G सेवा शुरू

उमंग ऐप
के माध्यम से **2,297**
से अधिक सरकारी सेवाओं तक पहुंच

रुकी हुई रियल एस्टेट
परियोजनाओं को
फिर से चलाने के लिए
स्वामी फंड के तहत
₹37,000 करोड़

पूरे देश में **रेरा** द्वारा
1 लाख से अधिक
मामलों
का निपटारा

यूपीआई उपयोगकर्ताओं
की संख्या में अब करीब
46 करोड़
व्यक्ति और
6.5 करोड़
व्यापारी हैं

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण)
के तहत
4 करोड़
से अधिक घर

मेट्रो 2014 में
5 शहरों से बढ़कर
अब (2025)
23 शहरों में पहुंची

UDAN
योजना के तहत
1.50+ करोड़ लोगों ने
सस्ती हवाई यात्रा का
लाभ उठाया

52.14 करोड़
से अधिक **डिजिलॉकर**
उपयोगकर्ता

इंटरनेट डेटा की कीमतें
97% घटी

अब सभी शहर
ओडीएफ*
घोषित

*खुले में शौच मुक्त

उपलब्धियां

अब टैक्स की नो टेंशन...

- **ई-फाइलिंग** सामान्य प्रक्रिया बनी
- **रिफंड** अब कुछ दिनों में मिलता है, महीनों में नहीं
- Faceless Assessments और Appeals से **उत्पीड़न में कमी**
- Tax Rates में वास्तविक रूप से **कमी**

एक विश्वसनीय सरकार, विश्वास करने वाली सरकार

- मोदी सरकार ने **परस्पर विश्वास के माहौल** का वातावरण बनाया
- Self-Attestation जैसे कदम इस बात का प्रमाण है कि सरकार को अपने नागरिकों पर भरोसा है
- IT Returns की संख्या साल 2013-14 के 3.3 करोड़ से बढ़कर साल 2023-24 में 8.09 करोड़ तक पहुंच गई। इससे पता चलता है कि **जनता सरकार पर भरोसा** करती है कि उनके टैक्स का सदुपयोग हो रहा है।

सबकी पहुंच में अपने घर का सपना गरीब हो या मध्य वर्ग

- **गरीब के लिए**, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पीएम आवास योजना
- शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना और पीएम आवास योजना 2.0 के तहत 2015-25 में 92.6 लाख घरों का निर्माण पूरा हुआ
- रेरा ने समय पर घरों की डिलीवरी सुनिश्चित की, ताकि घर खरीदने वालों का पैसा न फंसे।
- **RERA** ने समय पर घरों की डिलीवरी सुनिश्चित की, ताकि घर खरीदने वालों का पैसा न फंसे

शहरों के बीच बढ़ा संपर्क, सफर हुआ आसान

- **मेट्रो रेल के विस्तार** से शहरों में रहने वालों की यात्रा और सुविधाजनक हुई
- **उड़ान** योजना से सस्ती हवाई यात्रा, टियर-2 और टियर -3 के कई शहर इससे जुड़े
- **कार लोन की ब्याज दर में** 2014 के मुकाबले **कमी**।

* * *

क्या आप जानते हैं?

- 40% भारतीय आयुष्मान भारत के अंतर्गत सुरक्षित है
- अनुमान के अनुसार, पूंजीगत व्यय सहित प्रति व्यक्ति व्यय 2015-16 में ₹ 1261, 2016-17 में ₹1418 और 2017-18 में ₹1753 था
- भारत ने इंटरनेट कनेक्शन में 285.77% (97.02 करोड़) की वृद्धि दर्ज की
- दुनिया की सबसे सस्ते सेनेटरी पैड (₹1) 16000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों में उपलब्ध कराए गए
- 26 सप्ताह के पेड मैटरनिटी लीव के साथ चीन, सिंगापुर, जर्मनी और अमेरिका से कहीं ऊपर भारत
- 2025 तक 780 एलोपैथी, 323 डेंटल और 942 आयुष कॉलेजों सहित 2045 मेडिकल कॉलेज खोले गए
- वंदे भारत मिशन ने लगभग 3 लाख उड़ानें भरी और दुनिया भर से 3.15 करोड़ से अधिक लोगों को भारत लाया

सरकार के बड़े काम

जुड़ रहा है भारत: आम लोगों का जीवन हो रहा सुगम

मेट्रो:

2014 में केवल 5 शहरों तक मेट्रो कनेक्टिविटी, अब 23 शहरों तक पहुंची

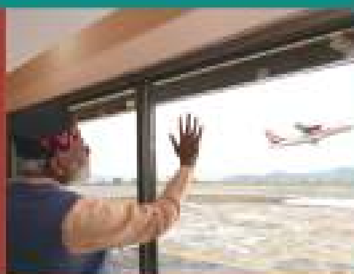

इलेक्ट्रिक बसें:

6,862 इलेक्ट्रिक बसें अनुमोदित (आपूर्ति – 5,165) फेम – II के तहत अब देशभर में सेवारत

हवाई यात्रा:

Operational Airports की संख्या करीब दोगुना हुई, 2014 के 74 से अब 2025 में 160 तक पहुंची

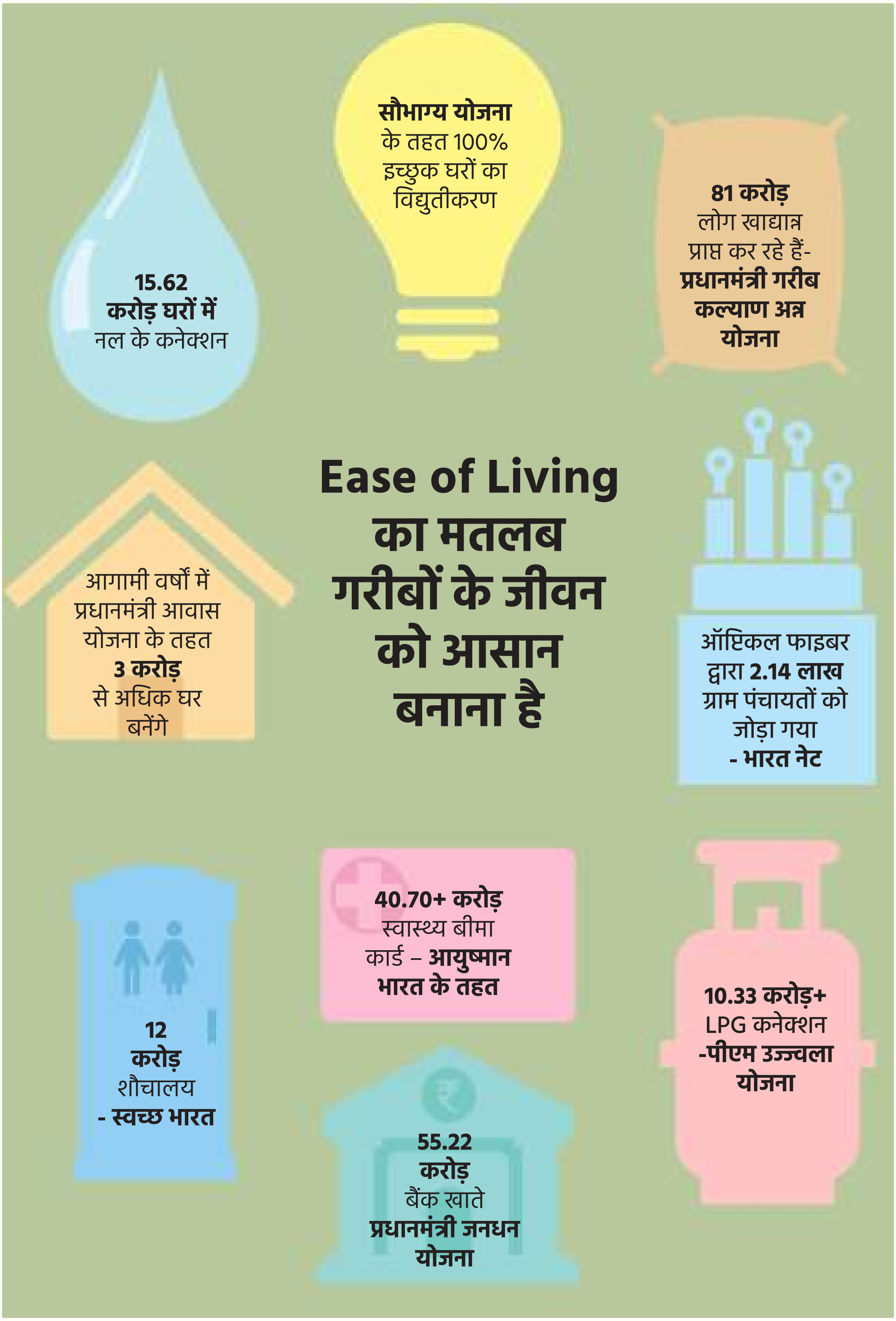
Ease of Living
का मतलब
गरीबों के जीवन
को आसान
बनाना है
सौभाग्य योजना के तहत 100% इच्छुक घरों का विद्युतीकरण
15.62 करोड़ घरों में नल के कनेक्शन
81 करोड़ लोग खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
आगामी वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक घर बनेंगे
ऑप्टिकल फाइबर द्वारा 2.14 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया - भारत नेट
40.70+ करोड़ स्वास्थ्य बीमा कार्ड – आयुष्मान भारत के तहत
12 करोड़ शौचालय - स्वच्छ भारत
10.33 करोड़+ LPG कनेक्शन -पीएम उज्ज्वला योजना
55.22 करोड़ बैंक खाते प्रधानमंत्री जनधन योजना

मध्यम वर्ग के लिए
EASE OF LIVING सुनिश्चित
मध्यम वर्ग के जीवन का एक दिन
RERA के कारण घर मिलेंगे सही समय पर
BHIM यूपीआई के माध्यम से किराना खरीदारी और परिवहन का भुगतान आसान और त्वरित हुआ
नवनिर्मित मेट्रो से काम पर जाना हुआ आसान
ई-फाइलिंग के माध्यम से कर देनदारी आसान और परेशानी मुक्त हुई
TAX
रिकार्ड टाइम में आयकर रिफंड
जन औषधि योजना के तहत मरीजों के लिए दवाइयों की खरीद, बाजार मूल्य से 50% से 90% कम कीमतों पर
उजाला LED लाइट्स से बिजली के बिल में भारी बचत
LED
पीएम सूर्य घर के जरिए लाखों परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई गई

रोजगार मेला- 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान। अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने के लिए सरकार एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है

मोबाइल
116 करोड़ उपभोक्ता
- धन का सुगम एवं तेज प्रवाह
- सीधे लाभार्थियों तक पहुंचना
- दोहराव एवं धोखाधड़ी में कमी
AADHAAR
आधार
141.88 करोड़
आधार आवंटित
जन-धन खाते
55.22 करोड़
जन-धन खाते

हमने तय किया कि किसी भी गरीब को पैसे के अभाव में अपना इलाज टालना न पड़े। हमने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि हमारे गरीब परिवारों को भी उनके घरों के पास बेहतर इलाज मिले।

-नरेन्द्र मोदी

सभी के लिए सस्ती, सुलभ स्वास्थ्य सेवा

6

सारांश

पिछले 11 वर्षों के दौरान, नरेंद्र मोदी सरकार के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य क्षेत्र प्रमुख मुद्दों में से एक रहा है। टीकों के 220 करोड़ से अधिक खुराक देने और जरूरत के समय दुनिया को भारी संख्या में टीकों का निर्यात करने के साथ-साथ वैश्विक महामारी से भारत की जीत में यह महत्वपूर्ण घटक रहा है।

सभी के लिए सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सरकार की प्राथमिकता रही है और भारत के नागरिकों के लिए एक वास्तविकता बन गई है। पहले कम आय वाले परिवारों के लिए चिकित्सा पर होने वाले खर्च भारी आर्थिक बोझ डाल देते थे और अक्सर उन्हें कर्ज के जाल में फंसा देता था। 2018 में मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम की शुरुआत की थी। यह योजना लगभग 55 करोड़ भारतीयों को चिकित्सा पर खर्च के बोझ से बड़ी राहत दे रही है। इसके अलावा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) डिजिटल रूप से जुड़े स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी के तंत्र के निर्माण के लक्ष्य को साकार कर रहा है।

54 करोड़ से अधिक लोगों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को उनके आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों (एबीएचए) से जोड़ा गया है। डिजिटल रूप से उपलब्ध स्वास्थ्य रिकॉर्ड एबीएचए धारकों को एबीडीएम नेटवर्क में कागज रहित स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाएंगे। सरकार का टेली मेडिसिन कार्यक्रम ई- संजीवनी देश के स्वास्थ्य से क्षेत्र में काफी बदलाव ला रहा है। इसके माध्यम से 37.15 करोड़ से अधिक लाभार्थी अपने घर से ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं, जिसने विशेषज्ञ चिकित्सा देखभाल सेवाओं में शहरी-ग्रामीण अंतर को पाटा है। सभी जिलों में स्थित 16000 से अधिक जन औषधि केंद्र सभी को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाई उपलब्ध करा रहे हैं।

सरकार टीके से रोके जा सकने वाले किसी भी रोग से लोगों को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में मिशन इंद्रधनुष के विभिन्न चरणों में 5.46 करोड़ बच्चों और 1.32 करोड़ गर्भवती महिलाओं को 12 बीमारियों के टीके लगाए जा चुके हैं। इस लक्षित सरकारी पहल के कारण देश में मातृ मृत्यु दर जो 2014-16 में यह दर 130 प्रति लाख जन्म से घटकर 2020 में यह दर 80 प्रति लाख जन्म हो गई है।

मोदी सरकार द्वारा चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया गया है। सरकारी कॉलेज की संख्या में कमी, निजी मेडिकल कॉलेज की भारी फीस, और सीट आवंटन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार ने चिकित्सा शिक्षा के अवसरों को गंभीर रूप से सीमित कर दिया था। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा कई राज्यों में नए एम्स और बड़ी संख्या में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। इनमें पूर्वोत्तर में असम में अब तक का पहला एम्स शामिल है। इसके अलावा, भारतीय चिकित्सा परिषद को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से बदले जाने के सरकार के साहसिक निर्णय ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया है। "न्यू इंडिया" में साधारण पृष्ठभूमि से आए प्रतिभाशाली छात्र भी अब डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। कोविड-19 महामारी पर भारत की त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया को दुनिया के सबसे बड़ी टीकाकरण अभियान के रोल आउट द्वारा मजबूती मिली, वह भी स्वदेशी रूप से विकसित टीकों का उपयोग करके। अतीत से एक ऐतिहासिक बदलाव में, जब नागरिकों को टीकाकरण अभियान शुरु करने के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता था, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने दो साल की छोटी अवधि में कोविड वैक्सीन की 2.2 बिलियन से अधिक खुराक का टीकाकरण सुनिश्चित किया।

सरकार ने पिछले 11 वर्षों में विभिन्न उपायों के माध्यम से अपने नागरिकों के दैनिक जीवन में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया है। सभी भारतीयों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का यह प्रयास "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास" प्रधानमंत्री के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरुप है।

* * *

मुख्य बातें

आयुष्मान भारत के तहत
9+ करोड़
अस्पताल में भर्ती होने पर **₹1.3 लाख करोड़** से ज़्यादा का मुफ़्त इलाज

1.76 लाख से ज़्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में
377 करोड़
से ज़्यादा विज़िट दर्ज की गई

16,000+
जन औषधि केंद्रों ने ग़रीबों और ज़रूरतमंदों को दवाइयाँ बाज़ार मूल्य से 50-90% कम कीमतों पर उपलब्ध करवाई

मिशन इन्द्रधनुष द्वारा
6.78 करोड़
से अधिक माताओं और बच्चों को मिली टीकों की सुरक्षा

23
एम्स और
2,045*
मेडिकल कॉलेज

6+ करोड़
नागरिकों ने **अमृत फार्मेसियों** से सस्ती दवाएं खरीदकर बचत की

220+ करोड़
COVID वैक्सीन डोज
दिए गए

77+ करोड़
डिजिटल हेल्थ आईडी
बनाए गए

जन औषधि केंद्रों के कारण
नागरिकों के लगभग
₹38,000 करोड़ बचे

2014 से अब तक
एमबीबीएस सीटें बढ़कर
1.18 लाख
हुई और **74,000 पीजी सीटें** जुड़ी

केंद्र सरकार द्वारा
1,500 से अधिक
पीएसए संयंत्र स्वीकृत

ई-संजीवनी के ज़रिए
37+ करोड़
टेली-परामर्श

*इसमें 780 एलोपैथी, 323 डेंटल और 942 आयुष संस्थान शामिल

उपलब्धियां

सक्रिय नेतृत्व बना संकटमोचक

- ऐसे समय में जब कई वैश्विक नेता COVID-19 के खतरे को भांपने में विफल रहे, भारत में एक भी मामला सामने आने से पहले ही **हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग** शुरु कर दी गई थी।
- कई अन्य देशों द्वारा इसे गंभीरता से लेने से बहुत पहले ही मार्च 2020 के प्रथम सप्ताह में **पीएम मोदी ने कह दिया था कि वह होली मिलन जैसे समारोहों से बचेंगे** और एक मिसाल कायम करेंगे।
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन** के ऐलान से बहुत पहले ही भारत के बहुत बड़े हिस्से में मास्क को अनिवार्य घोषित कर दिया गया था।
- जब कई देश केवल बड़े पैमाने पर लोगों की मौत पर मंथन कर रहे थे, तब अप्रैल 2020 में भारत ने लोगों की जान बचाने के लिए **वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन** कर दिया था।
- भारत ने WHO की सिफारिश से बहुत पहले **Rapid Antigen Tests** शुरु कर दिया था, ताकि **जांच में तेजी** लाई जा सके।
- भारत ने **शुरुआत में ही लॉकडाउन** का ऐलान कर दिया था, इसे पूरी दुनिया ने स्वीकारा और सराहा। इससे देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद मिली।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (PM-ABHIM) के साथ भारत का भविष्य सुरक्षित

- **₹64,180 करोड़** का निवेश।
- Focus States के 10 राज्यों के 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के लिए सहायता।
- सभी राज्यों में 11,024 शहरी Health और Wellness केंद्रों की स्थापना।
- Focus States के 11 राज्यों में 3,382 ब्लॉक **सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां**।
- सभी जिलों में Integrated **Public Health Labs** की स्थापना।
- 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी जिलों में **क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक** की स्थापना।

डिजिटल है सफलता की एकमात्र कुंजी- ABDHM

- CoWIN और Aarogya Setu की सफलता से **Healthcare में Tech की ताकत** दिखी।
- आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन (ABDHM) Healthcare के लिए एक Online Platform तैयार कर रहा है।
- नागरिकों ने अपना ABHA (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता) नंबर बनाया है, इनसे उनके **Digital Health Records जुड़े होते हैं**।
- नागरिकों की सहमति से, इस डेटा तक Healthcare Professionals द्वारा पहुंचा जा सकता है।
- ABDM **Evidence-Based Decision Making** की सुविधा देता है, इससे प्रभावी Health Intervention में मदद मिलती है।
- ***77 करोड़ ABHA*** बनाए जा चुके हैं!

* * *

भारत में टीकाकरण- इतिहास और वर्तमान

टीका	दुनिया में शुरुआत	भारत में शुरुआत
कोविड-19	दिसंबर 2020	एक महीना
IPV	1955	60 वर्ष
TT	1926	57 वर्ष
BCG	1927	51 वर्ष
खसरा	1971	46 वर्ष
DPT	1948	30 वर्ष
हेपेटाइटिस बी	1982	20 वर्ष
न्यूमोकोकल	2000	17 वर्ष
रोटावायरस	2006	10 वर्ष

जिस गति से भारत में COVID-19 टीके विकसित किए गए, वो इस न्यू इंडिया का जीता जागता उदाहरण है, जहां अब टीकों के लिए दशकों तक इंतजार नहीं करना पड़ता या दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है।

सरकार के बड़े काम

गरीबों की हर Healthcare जरूरत के लिए
व्यापक कवरेज

रोगों से बचाव के लिए
मिशन इंद्रधनुष

5.46 करोड़ बच्चों और 1.32 करोड़ गर्भवती महिलाओं को 12 रोगों के निषेध के लिए कई चरणों में टीकाकरण

AYUSH और योग को बढ़ावा

प्राथमिक सेवा के लिए
आयुष्मान आरोग्य मंदिर

1.76+ लाख AAM

उच्च रक्तचाप जांच - 55.66 करोड़

मधुमेह जांच - 48.44 करोड़

Teleconsultation- 37.15 करोड़

AB-HWCs पर सामान्य कैंसर (मुख, स्तन, गर्भाशय) की कुल जांच - 57.74 करोड़

Secondary और Tertiary care के लिए
आयुष्मान भारत- PMJAY

5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर

आयुष्मान कार्ड - 40.71 करोड़

अस्पताल में दाखिले - 9.59 करोड़

इलाज का खर्च - 1,31,827 करोड़ रुपये

दवाओं के लिए
जन औषधि केंद्र

16,000+ केंद्र कम कीमत पर देते हैं दवाएं

नागरिकों के 38,000 करोड़ रुपये की बचत

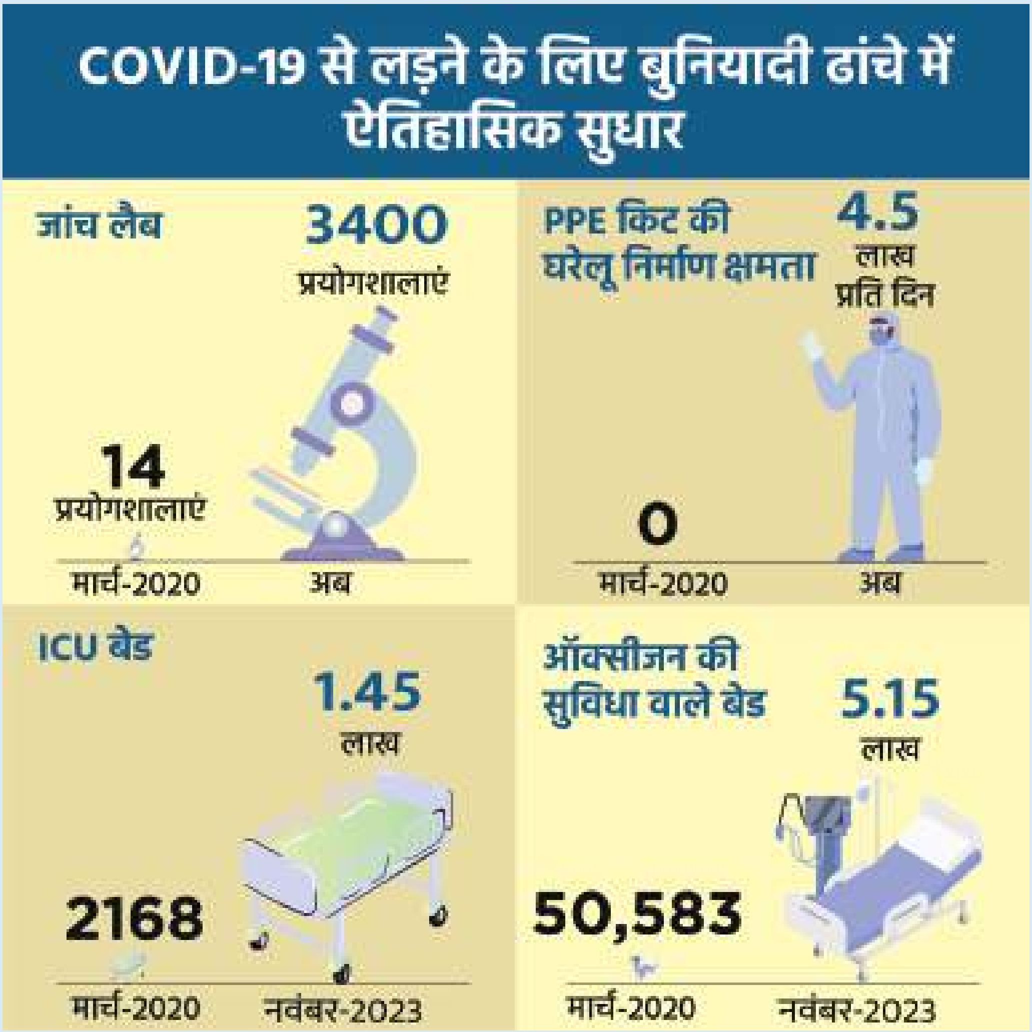
COVID-19 से लड़ने के लिए बुनियादी ढांचे में ऐतिहासिक सुधार
जांच लैब
3400
प्रयोगशालाएं
14
प्रयोगशालाएं
मार्च-2020
अब
PPE किट की घरेलू निर्माण क्षमता
4.5
लाख
प्रति दिन
0
मार्च-2020
अब
ICU बेड
1.45
लाख
2168
मार्च-2020
नवंबर-2023
ऑक्सीजन की सुविधा वाले बेड
5.15
लाख
50,583
मार्च-2020
नवंबर-2023

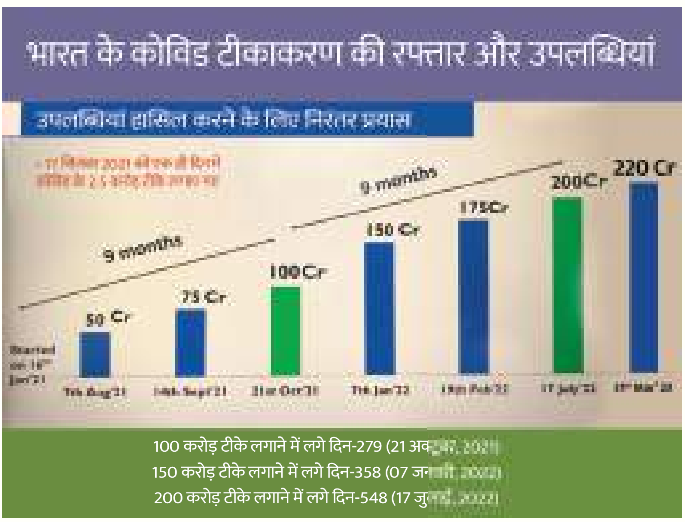
भारत के कोविड टीकाकरण की रफ्तार और उपलब्धियां
उपलब्धियां हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास
9 months
9 months
50 Cr
75 Cr
100Cr
150 Cr
175Cr
200Cr
220 Cr
100 करोड़ टीके लगाने में लगे दिन-279 (21 अक्टूबर, 2021)
150 करोड़ टीके लगाने में लगे दिन-358 (07 जनवरी, 2022)
200 करोड़ टीके लगाने में लगे दिन-548 (17 जुलाई, 2022)

अभिनव समाधानों से कोविड प्रबंधन सुधार

ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन
लगभग 900 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों से 36,840 टन से अधिक तरल ऑक्सीजन पंहुचायी गयी।

वायु सेना
क्रायोजेनिक टैंकर लाने - ले जाने के लिये वायु सेना की मदद ली गयी।

आइसोलेशन कोच
रेलवे ने 4,176 कोचों को क्वारंटीन/पृथकवास केंद्रों में बदला

मेक शिफ्ट फैसिलिटी
अर्द्ध सैनिक बलों और केंद्रीय एजेंसियों ने मेकशिफ्ट क्वारंटीन केंद्र संचालित किये।

पीएसए संयंत्र
केंद्र सरकार द्वारा 1500+ से अधिक पीएसए संयंत्र मंजूर किये गये।

आयुष्मान भारत वय वंदना

वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा

- **58 लाख से ज़्यादा वरिष्ठ नागरिकों का नामांकन**
- **2.67 लाख से ज़्यादा लोगों का ₹496 करोड़ का इलाज**
- **सिर्फ़ आधार पहचान पत्र से ही 70 से ज्यादा उम्र वालों के लिए आसान, सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना।**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के पहले एम्स का उद्घाटन

भारत में अब **23 एम्स,** इनमें से **एक उत्तर पूर्व** में

ये नया भारत है ! ये भारत शांति चाहता है... लेकिन अगर
मानवता पर हमला हुआ तो भारत युद्ध के
मैदान में दुश्मन को कुचलना भी जानता है।

-नरेन्द्र मोदी

‘राष्ट्र प्रथम’- विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा

7

सारांश

पिछले ग्यारह वर्षों में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने एक गतिशील और परिवर्तन आधारित विदेश नीति की परिकल्पना की है और इसका कार्यान्वयन किया है, जो परिणाम-उन्मुख, विकास-केंद्रित है और सरकार के "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के दृष्टिकोण के विज़न के अनुरूप है।

भारत की विदेश नीति का प्राथमिक ध्यान 'पड़ोसी प्रथम नीति' (नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी) के तहत, अपने नजदीकी पड़ोसी देशों पर है। इसे 'एक्ट ईस्ट', 'थिंक वेस्ट' और 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीतियों द्वारा सशक्त बनाया गया है, जो विस्तारित पड़ोस में हमारे संपर्क को और बढ़ाना चाहते हैं। सरकार के विज़न, भारत-प्रशांत क्षेत्र में कानून-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास' (SAGAR) डिज़ाइन किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI), पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली (LiFE), और इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) जैसी नई पहलों ने दुनिया के साथ हमारे बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत किया है। दुनिया भर में भारत की वैश्विक उपस्थिति का विस्तार करने के सरकार के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, मिशनों, वाणिज्य दूतावासों और प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। भारत ने 1 दिसंबर, 2022 को जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण की है । भारत की अध्यक्षता का विषय, "वसुधैव कुटुम्बकम" या "एक पृथ्वी-एक परिवार-एक भविष्य" एक अनूठी भारतीय अवधारणा है, जिसकी व्यापक रूप से सराहना की गई है।

60 शहरों में 200 से अधिक बैठकों ने जी-20 आयोजन के लिए एक अभूतपूर्व माहौल पैदा किया । परिणामस्वरूप, भारत की जी-20 अध्यक्षता वास्तव में जन-केंद्रित थी और एक राष्ट्रीय प्रयास के रूप में उभरी।

ई-शासन से जुड़े तरीकों के उपयोग के माध्यम से भारत के वाणिज्य दूतावास परिचालन को वैश्विक स्तर पर सबसे तेज़, सबसे पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया गया है। भारत ने विदेशों में भारतीय श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, छात्रों, पेशेवरों के पारस्परिक आगमन को बढ़ाने के लिए समझौते हुए हैं एवं अवैध प्रवासन को रोकने के लिए कई देशों के साथ समझौते किए हैं।

मानवीय संकट के समय भारत 'कार्रवाई करने वाले प्रथम राष्ट्र ' के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मानवीय संकट के दौरान प्रयासों के समन्वय के लिए विदेश मंत्रालय में एक विशेष प्रभाग के रूप में त्वरित कार्रवाई प्रकोष्ठ की स्थापना ने आपदा प्रोटोकॉल को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। भारत ने पिछले 11 वर्षों के दौरान विभिन्न राहत और निकासी अभियान चलाए हैं, जिनमें प्रमुख हैं- ऑपरेशन दोस्त (2023), ऑपरेशन गंगा (2022), ऑपरेशन देवी शक्ति (2021), और मिशन सागर (2021), आदि।

राष्ट्रीय सुरक्षा मोदी सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसे भारत के बाहर चलाए गए बचाव अभियानों, देश में आतंक नीति के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाने के साथ साथ वामपंथी उग्रवाद में आई महत्वपूर्ण कमी में देखा जा सकता है। वैश्विक मंच पर भारत की दावेदारी में भी उल्लेखनीय विकास हुआ है। **ऑपरेशन सिंदूर** की सफलता ने एक नए भारत को प्रदर्शित किया- जो निर्णय लेने में दृढ़, तीव्र और संप्रभु है ।

प्रधानमंत्री का दृढ़ विश्वास है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा साथ-साथ चलते हैं और इसने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है। भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत, INS विक्रांत, स्वदेशी विनिर्माण के क्षेत्र में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2024-25 में, रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX) फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया, जिसने सफल प्रोटोटाइप विकास के लिए स्टार्टअप्स और नवोन्मेषकों को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आज दुनिया के अवसरों का लाभ प्राप्त करने और चुनौतियों का जवाब देने के लिए एक गतिशील विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति आवश्यक है। एक स्थिर, मजबूत और सुरक्षित राष्ट्र बनाने के लिए, मोदी सरकार ने इस मोर्चे पर लगातार काम किया है।

* * *

मुख्य बातें

ऑपरेशन SINDOOR (सिंदूर)
की सफलता ने एक नए भारत को प्रदर्शित किया – जो निर्णय लेने में दृढ़, तीव्र और संप्रभु है

रक्षा स्वदेशीकरण सूची में
5,000
से ज्यादा Items जुड़े

वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा पूंजी अधिग्रहण बजट का
75%
घरेलू उत्पादन के लिए

ऑपरेशन कावेरी
युद्धग्रस्त सूडान से **3,000 से अधिक भारतीयों** को वापस लाया गया

वंदे भारत मिशन, एयर बबल उड़ानों द्वारा
3.15 करोड़
से अधिक लोगों को लाया गया

23,000
भारतीयों की **यूक्रेन से सुरक्षित वतन वापसी** हुई

रक्षा निर्यात 2024-25 में
23,622 करोड़ रुपये
के अब तक के उच्च स्तर पर पहुँचा

भारतीय संविधान से
अनुच्छेद 370 और **अनुच्छेद 35ए**
को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय

रक्षा निर्यात में 2014 से
34 गुना बढ़ोत्तरी;
ऑटोमैटिक रूट से रक्षा क्षेत्र में **74% एफडीआई**

सशस्त्र बलों के लिए iDEX स्टार्टअप और एमएसएमई से
2,400 करोड़ रुपये
से अधिक मूल्य के 43 Items की खरीद

वैक्सीन मैत्री के माध्यम से 100 से अधिक देशों के लिए
30 करोड़
से अधिक COVID-19 वैक्सीन

ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को
7 रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों
में बदला गया इनमें से छह लाभ में हैं

उपलब्धियां

आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस

- 2014 के बाद से non-conflict zones वाले भारतीय शहरों में **कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं**
- **वर्ष 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक**, 2019 में एयर स्ट्राइक और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से सीमा पार आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब
- आतंकवाद के प्रायोजकों को **वैश्विक स्तर पर अलग-थलग** किया और उनके प्रभाव को कम किया
- भारत ने **आतंकवाद को न केवल वैश्विक मुद्दा** बनाया, बल्कि वो इसके खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व भी कर रहा है।
- **UAPA** amendment से कानूनी ढांचे को मजबूत बनाया

Positive Indigenisation List क्या है और इसका महत्व

- प्रमुख उपकरणों वाली 5000 से अधिक वस्तुओं की सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी ।
- इन सूचियों में उन **Weapons, Arms और Systems का रोडमैप है, जिनका भारत भविष्य में आयात नहीं** करेगा। डीपीएसयू के लिए 4600 से अधिक वस्तुओं की 5 अलग-अलग सूचियाँ को अधिसूचित किया गया है।
- घरेलू खरीद के लिए इस तरह के रोडमैप और अधिदेश के सामने आने से घरेलू निर्माताओं को उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है।
- इससे भारत को रणनीतिक बढ़त मिलती है, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार सृजन भी होता है।

आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र के लिए निवेश

- **ऑटोमैटिक रूट के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74%** हुई।
- वर्ष 2025-26 के बजट में रक्षा के लिए **Capital Procurement Budget का 75%** घरेलू उद्योग के लिए रखा गया ।
- उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में **डिफेंस कॉरिडोर** के लिए प्रोत्साहन।
- उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर से इस इलाके को आर्थिक मजबूती मिलेगी।

* * *

भारतीय न्याय प्रणाली को औपनिवेशिक युग के कानूनों से आज़ादी

भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 - ये अधिनियम समाज के गरीबों, वंचितों और कमज़ोर वर्गों के लिए बढ़ी हुई सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। ये अधिनियम हमारे कानूनों, पुलिस और जांच प्रणालियों को प्रौद्योगिकी के साथ-साथ फोरेंसिक विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हुए आधुनिक युग में लाएंगे। साथ ही, ये अधिनियम संगठित अपराध, आतंकवाद और ऐसे ही अन्य अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में सहायक होंगे जो प्रगति की दिशा में हमारी शांतिपूर्ण यात्रा को कमजोर कर रहे हैं।

सरकार के बड़े काम

भारत के रक्षा निर्यात में वृद्धि
रक्षा निर्यातों का कुल मूल्य
23,622
करोड़ रूपए
2024-25
1,521
करोड़ रुपये
2016-17
अधिक रक्षा निर्यात का अर्थ है, रोजगार के अधिक अवसर

स्वदेश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर ((एलसीएच)) को 'प्रचंड' नाम दिया गया है, जिसे भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया है।

एलसीएच(LCH) दुनिया का एकमात्र ऐसा लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5,000 मीटर की ऊंचाई पर हथियारों और ईंधन के पर्याप्त भार के साथ उतर सकता है और उड़ान भर सकता है।

क्या आप जानते हैं?

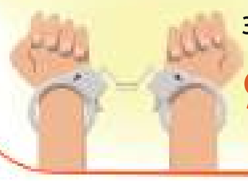

राष्ट्रीय अभिकरण एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांच किए गए आतंकवाद के वित्तपोषण मामलों में अपराध प्रमाणित होने की दर

95 प्रतिशत से अधिक है

सुरक्षा मामला: 2018 से जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में कमी

वर्ष	आतंकवादी
2018	228
2019	153
2020	126
2021	129
2022	125
2023	46
2024	28

भारत की G20 अध्यक्षता

"भारत ने G20 की अपनी अध्यक्षता के लिए 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' विषय का चयन किया है। यह उद्देश्य में एकता और कार्रवाई में एकता की आवश्यकता का संकेत देती है।"

-नरेंद्र मोदी

जी-20 शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली की सफलता

- नई दिल्ली शिखर सम्मेलन ने भारत की समकालीन प्रौद्योगिकी प्रगति के साथ-साथ हमारी विरासत, संस्कृति और परंपराओं के प्रदर्शन का अवसर प्रदान किया। जी-20 सदस्य देशों के नेताओं और प्रतिनिधियों द्वारा इसकी व्यापक सराहना की गई।

- शिखर सम्मेलन के दौरान भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा समझौते और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का निष्कर्ष काफी महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे।

प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस में कूटनीतिक उन्नयन

10-12 फरवरी 2025

1
AI Action की सह-अध्यक्षता
- राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ सह-अध्यक्षता
- सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद AI के लिए भारत- फ्रांस AI रोडमैप लॉन्च किया

2
गतिशील द्विपक्षीय सहयोग
- प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस की छठी यात्रा
- मार्सेय में भारत के महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया
- नई दिल्ली में भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का शुभारंभ किया जाएगा
- जलवायु संबंधी भारत-यूएई मैंग्रोव गठबंधन में फ्रांस शामिल हुआ
- प्रधानमंत्री मोदी ने Mazargues War Cemetery में भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी

3
Encrypting रक्षा और सुरक्षा
- भारत पर्यवेक्षक के रूप में Eurodrone MALE कार्यक्रम में शामिल हुआ
- रक्षा नवाचार के लिए FRIND-X लॉन्च किया
- DRDO-ONERA R&D साझेदारी को सुदृढ़ किया
- NSG-GIGN आतंकवाद-विरोधी सहयोग में वृद्धि
- परमाणु ऊर्जा सहयोग पर ध्यान केंद्रित

भा
वि
नी
Algo

प्रधानमं
फ्रांस और
के साथ स
मजबूत क

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस, फ्रांस में AI Action शिखर सम्मेलन में भाग लिया, 11 फरवरी, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस, वा

...रत
...देश
...ीति
...orithm

...मंत्री मोदी
...ौर अमेरिका
...थ संबंधों को
... कर रहे हैं।

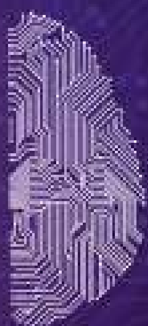

...स, वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप के साथ

अमेरिका के साथ **पीएम मोदी** की Adaptive Strategy

12-13 फरवरी 2025

1

रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी के लिए **नई यू.एस.-भारत Compact पहल** की शुरुआत

रक्षा और सुरक्षा

- **यू.एस.-भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी** के लिए 10 वर्षीय रूपरेखा
- AI सक्षम रक्षा तकनीक के लिए **ASIA गठबंधन** की शुरुआत
- **टाइगर ट्रायम्फ** अभ्यास का विस्तार
- **भारत-प्रशांत लॉजिस्टिक्स और खुफिया जानकारी** साझा करने में मजबूती

व्यापार और निवेश - 'मिशन 500'

- 2030 तक **व्यापार को दोगुना** करके $500 बिलियन करने का लक्ष्य
- **द्विपक्षीय व्यापार** मामलों की वार्ता 2025 के लिए निर्धारित
- यू.एस.ए. में नए भारतीय निवेश में **$7.35 बिलियन**

प्रौद्योगिकी और नवाचार - यू.एस.-भारत ट्रस्ट पहल

- **AI** इंफ्रास्ट्रक्चर रोडमैप
- अंतरिक्ष, ऊर्जा और तकनीकी साझेदारी के लिए **INDUS-X**
- **NASA-ISRO:** अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री को ISS और NISAR का मानचित्रण

2

ऊर्जा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी का अनुकूलन

- भारत की पूर्ण **अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी सदस्यता** के लिए अमेरिकी समर्थन
- **यू.एस.-भारत असैन्य परमाणु समझौते** को आगे बढ़ाना

3

बहुपक्षीय और भारत-प्रशांत सुरक्षा का विकास

- क्षेत्रीय सुरक्षा और व्यापार के लिए **क्वाड को मजबूत करना**
- बुनियादी ढांचे और वाणिज्य के लिए **Indian Ocean Stragegic Venture**
- यू.एस. ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी
- पाकिस्तान से 26/11 और पठानकोट हमलावरों पर कार्रवाई की मांग
- भारत, समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने के लिए **संयुक्त समुद्री बलों में शामिल** हुआ

4

People-to-People Ties को सुदृढ़ करना

- **3,00,000 भारतीय छात्रों** ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में $8 बिलियन का योगदान दिया
- Dual-Degree कार्यक्रमों के माध्यम से **उच्च शिक्षा संबंधों को सुदृढ़ किया**
- पेशेवरों और पर्यटकों के लिए **सुव्यवस्थित कानूनी गतिशीलता**
- तस्करी, संगठित अपराध और साइबर खतरों के खिलाफ सहयोग बढ़ाया

रक्षक

पीएम मोदी!

यूक्रेन-2022

23,000 लोग बचाए गए

यूक्रेन-2014

1,000 लोग

ज्यादातर छात्र सुरक्षित निकाले गए

सीरिया-2014

जुलाई 2014 में ISIS द्वारा बंधक 46 भारतीय नर्सों को बचाया गया था।

इराक और सीरिया में संकट के दौरान **7,000 भारतीयों को** सुरक्षित निकाला गया था।

लीबिया-2014

लीबिया संकट में फंसी 40 से अधिक भारतीय नर्सों को सुरक्षित घर पहुंचाया गया।

3,710 से अधिक भारतीयों को निकाला गया

यमन-2015

2015 में यमन में भारत ने न केवल अपने नागरिकों को बल्कि विदेशियों को भी बचाया।

ऑपरेशन राहत में **4,748 भारतीयों** और 41 देशों के 1,962 विदेशियों को बचाया गया

सूडान-2016

जुलाई 2016 में दक्षिणी सूडान से **153 लोगों को** बचाया गया था।

नेपाल-2015

2015 में आए भूकंप से नेपाल तबाह हो गया था।
भारत ने ऑपरेशन मैत्री का संचालन किया और कई विदेशियों को, **5,188 भारतीयों को** बचाया

यमन-2017

2017 में, यमन से एक पादरी टॉम उजुन्नलिल को, जो 2016 में ISIS द्वारा अगवा कर लिया गया था, छुड़ाया गया

अफगानिस्तान-2021

2021 में जब अफगानिस्तान तालिबान के हाथों में चला गया, **550 से अधिक लोगों को** वहां से निकाला गया।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब के कई पवित्र सरूप वापस लाए। महान सम्मान प्रदर्शित करते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 5 पवित्र सरूपों को बाद में दूसरी उड़ान से वापस लाया गया।

चीन-2020

2020की शुरुआत में, जब COVID-19 महामारी सामने आई, **637 भारतीयों को** वापस लाने के लिए वुहान के लिए उड़ानें भेजी गईं और **7 मालदीवियों** को भी बचाया गया।

वंदे भारत मिशन

कोरोना महामारी के दौरान महत्वपूर्ण बचाव अभियान वंदे भारत मिशन के माध्यम से 2.17 लाख उड़ानों द्वारा 2.97 करोड़ से अधिक लोगों को वापस लाया गया।

मिशन सागर

15 मित्र देशों को COVID-19 से संबंधित सहायता पहुँचाने के लिए 2020 में लॉन्च किया गया था

ऑपरेशन कावेरी

- युद्धग्रस्त सूडान से 3000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया।
- एयरपोर्ट हेल्थ ऑफ़िसर्स द्वारा चलाये जा रहे कॉरांटाइन सेंटर्स में निःशुल्क आवास व भोजन की व्यवस्था।

सटीक सैन्य जवाब

ऑपरेशन सिंदूर, 7 मई, 2025 को शुरू किया गया, पहलगाम आतंकी हमले के लिए तीनों सेनाओं द्वारा संयत , केंद्रित और गैर-एस्केलेटरी सटीक सैन्य जवाब था। भारत की एकीकृत कमान और नियंत्रण रणनीति के माध्यम से समन्वित, इसने सीमा पार नौ आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर दिया। इस ऑपरेशन ने भारत की संयुक्त बल क्षमता, रणनीतिक दूरदर्शिता और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ संकल्प को प्रदर्शित किया

साइबर सुरक्षा

डिजिटल इंडिया सुरक्षित

1662 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया; 71 मंत्रालय/विभाग संकट योजनाओं के साथ तैयार हैं। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की जांच के लिए 16 प्रयोगशालाओं को प्रमाणित किया गया। बड़ी चुनौतियाँ स्टार्टअप्स में साइबर सुरक्षा नवाचार को बढ़ावा देती हैं।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने अभूतपूर्व गति से किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए नई ई-जीरो एफआईआर पहल शुरू की। दिल्ली में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई यह नई प्रणाली एनसीआरपी या 1930 पर दर्ज साइबर वित्तीय अपराधों को स्वचालित रूप से एफआईआर में बदल देगी।

ये दशक और आने वाले 25 साल भारत को लेकर अभूतपूर्व विश्वास के हैं। सबके प्रयास से ही भारत अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करेगा।

-नरेन्द्र मोदी

भारत, वैश्विक आर्थिक महाशक्ति

8

सारांश

वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए पिछले कुछ वर्ष बड़े ही चुनौतीपूर्ण रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर की आर्थिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी और रुस-यूक्रेन संघर्ष होने जैसी बड़ी घटनाओं से उबर रही है। एक तरफ जहां दुनिया अपने पांव जमाने के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था नये पायदान पर चढ़ती जा रही है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक आर्थिक विकास के मुद्दे पर व्यक्त किये गए अपने नवीनतम अनुमानों में भारत को दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है।

जीएसटी संग्रह में पर्याप्त वृद्धि, पूंजीगत व्यय में वृद्धि और अद्वितीय निर्यात प्रदर्शन एक जीवंत और लचीली अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है जो महामारी से सफलतापूर्वक उबर चुकी है।

इसका श्रेय कोविड महामारी के दौरान और उसके उत्तरोत्तर की आर्थिक नीतियों के प्रबंधन के लिए न केवल मोदी सरकार के समग्र दृष्टिकोण को दिया जा सकता है, बल्कि अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2014 के बाद लगातार हो रहे प्रयासों को भी दिया जा सकता है। नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा शुरु किए गए संरचनात्मक सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पहले से बहुत मजबूत किया है और इसे कोविड महामारी के अभूतपूर्व प्रभावों का सामना करने के लिए भी सक्षम बनाया है।

मोदी सरकार ने भारत को विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 'आत्मनिर्भर भारत' के साथ-साथ 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत कई कार्यक्रम शुरु किए हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना से इस क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहित किया गया है। उत्पादन से जुड़ी इस प्रोत्साहन योजना को लाने के पीछे का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए घरेलू कारोबारियों को तैयार करना है। पीएलआई योजनाओं ने रोजगार के लाखों अवसर सृजित किये हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास के तीव्र पथ पर बनाए रखा है। भारत पहले मोबाइल फोन का एक बड़ा आयातक था, लेकिन अब एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन चुका है। 2014-15 में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 60 मिलियन से 5 गुना बढ़कर 2023-2024 में लगभग 330 मिलियन हो गया।

मोदी सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को अपनी आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु बनाया है। कोविड महामारी के दौरान सरकार की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ने एक करोड़ से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान की थी और उन्हें संभवतः स्थायी रुप से बंद होने से बचाया था। इसके अलावा, एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन भी किया गया। श्रम तथा पर्यावरण कानूनों में परिवर्तन जैसे सुधारों ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को अपने कामकाज का विस्तार करने और विकास की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के रोजगार उपार्जकों को लगातार नवाचार करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उनके प्रयासों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है यह भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) तथा भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के निर्माण के इसके विजन के लिए उनके व्यक्तिगत ध्यान में परिलक्षित होता है

प्रधानमंत्री मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत एक पसंदीदा निवेश केंद्र के रुप में भी उभरा है। जीएसटी, आईबीसी, एफडीआई व्यवस्था में लगातार सुधार, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नस, अनुपालन में कमी और कई एफटीए पर हस्ताक्षर करने के परिणामस्वरुप एफआईआई और एफडीआई निवेश दोनों में लगातार वृद्धि हुई है। कोविड के बाद निर्यात हर साल नई ऊंचाइयों को छू रहा है

भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 11 वर्षों में यह उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया है और इसका प्रभाव समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर को सकारात्मक रुप से प्रभावित कर रहा है।

* * *

मुख्य बातें

भारत के विश्व की सबसे **तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान** (2025-26 में 6.3% से 6.8%)

ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट का 49% हिस्सा भारत का (एसीआई वर्ल्डवाइड रिपोर्ट 2024)

कोविड के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए **29.8 लाख करोड़ रुपए** का आत्मनिर्भर भारत पैकेज

सितंबर 2024 में सकल एफडीआई प्रवाह **$1 ट्रिलियन*** तक पहुंच जाएगा

एफडीआई में **26% की बढ़ोतरी**, वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में एफडीआई **42 बिलियन अमेरिकी डॉलर** से अधिक

वित्त वर्ष 2024-25 में वस्तुओं और सेवाओं का रिकॉर्ड निर्यात **$825 अरब डॉलर** हुआ

ईसीएलजीएस के तहत एमएसएमई के लिए **रु 3.68 लाख करोड़** से अधिक की मंजूरी मिली

एमसीजीएस-एमएसएमई के तहत गारंटी कवर बढ़ाकर **₹100 करोड़** किया गया

इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात में **32%** से अधिक की छलांग, 2024-25 में **$38+ अरब** तक पहुंचा

दिसंबर 2024 में जीएनपीए घटकर **2.6%** पर आने से बैंकिंग प्रणाली मजबूत हुई

भारत का **गैर-पेट्रोलियम निर्यात** **$374.1 बिलियन** (वित्त वर्ष 2024-25) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया

पीएलआई योजना से **₹1.61 लाख करोड़** का निवेश, **₹14 लाख करोड़** का उत्पादन, **₹5.31 लाख करोड़** का निर्यात और **11.5 लाख** नौकरियां पैदा हुईं

(*अप्रैल 2020 से)

उपलब्धियां

विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था-क्यों यह वृद्धि मात्र संख्या नहीं है

- दुनिया भर में इस बात को लेकर सहमति है कि भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी
- हाई ग्रोथ से सरकार के पास बड़ी मात्रा में संसाधन उपलब्ध होंगे, इनसे कल्याणकारी और ढांचागत योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सकेगा
- हाई ग्रोथ से नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे
- नए अवसरों से आय में निरंतर वृद्धि होगी और इस ग्रोथ के लाभ समाज के हर वर्ग को मिलेंगे

आपदा को अवसर में बदलता आत्मनिर्भर भारत

- महामारी के प्रारंभ से ही प्रधानमंत्री मोदी के ठोस आर्थिक प्रबंधन ने आपदा को अवसर में बदल दिया.. सभी आर्थिक संकेतक भारत के आर्थिक पुनरुत्थान की ओर इशारा कर रहे हैं।
- एमएसएमईज़ से एमएनसीज़ तक सभी कंपनियों के उत्पादन में विस्तार हो रहा है। इसने सर्विसेज और एक्सपोर्ट्स सेक्टर में ऐतिहासिक योगदान दिया है।
- कई क्षेत्रों में हाईरिंग सेंटीमेंट अपने सबसे उच्च स्तर पर है इससे ग्रोथ का जॉब्स में परिवर्तित होना सुनिश्चित हुआ है

दृढ़ विश्वास और आम सहमति से सुधार

- प्रधानमंत्री मोदी ने कठिन दौर में कई संरचनात्मक सुधारों को व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ाकर दृढ़ विश्वास और आम सहमति से सुधारों का एक नया चलन शुरु किया
- सहकारी संघवाद का मतलब है कि केंद्र राज्यों को प्रोत्साहित करके उन्हें स्वेच्छा से सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करना
- सुधारों ने सभी हितधारकों के हितों की सुरक्षा की

बेहतर अर्थव्यवस्था का निर्माण

- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत से अधिक औपचारिकता काविस्तार
- बकाया वसूली के लिए सरकार की सख्त कार्रवाई से एनपीए और आर्थिक अपराधों में तेजी से कमी आई।
- आईबीसी ने भारतीय बैंकिंग और कॉर्पोरेट क्षेत्रों को मुश्किलों से उबारा
- भारत तेजी से 'डिजिटल अर्थव्यवस्था' में बदल रहा है।

* * *

'ग्रोथेड' के लिए आधार तैयार

- भारतीय कॉरपोरेट्स ने 2024-25 में आईपीओ के माध्यम से ₹1,62,387 करोड़ की सर्वकालिक उच्च राशि जुटाई।
- राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार 2014 में 91,287 किलोमीटर से बढ़कर मार्च 2025 तक 1,46,204 किलोमीटर हो गया
- देश में 160 परिचालन हवाई अड्डे हैं, जिनमें मार्च 2025 तक 145 हवाई अड्डे, 02 जल हवाई अड्डे और 13 हेलीपोर्ट शामिल है।
- नई निर्माण इकाइयों के लिए 2024 तक 15% कर दर रखने और स्टार्ट-अप के लिए एक साल तक कर प्रोत्साहन, उन क्षेत्रों को बढ़ावा देगा जो पिछले कुछ वर्षों में फले-फूले हैं और रोजगार सृजन किया है।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (जीएनपीए) अनुपात दिसंबर 2024 में 12 साल के निचले स्तर 2.6% पर आ गया

सरकार के बड़े काम

भारत का विश्व की सबसे तेज़ उभरती अर्थव्यवस्था का अनुमान (2025-26 में 6.3% से 6.8% तक) (आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार)

भारत की तेज आर्थिक वृद्धि को लेकर वैश्विक सहमति

विभिन्न वैश्विकसंस्थाओं के आकलन के अनुसार भारत तेजी से विकसित हो रही प्रमुख अर्थव्यवस्था

कर संग्रह से सुदृढ़ आर्थिक बहाली का संकेत

- अप्रैल 2025 में सर्वाधिक मासिक जीएसटी संग्रह
- सकल कर राजस्व-जीडीपी अनुपात वित्त वर्ष 2025 के लिए 11.9% और वित्त वर्ष 2026 के लिए 12% होने का अनुमान (केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार)
- कर सरलीकरण
  कॉर्पोरेट कर संरचना को युक्तिसंगत और सरल बनाया गया

'आईएमएफ द्वारा 2025 के लिए वैश्विक आर्थिक विकास पूर्वानुमान'

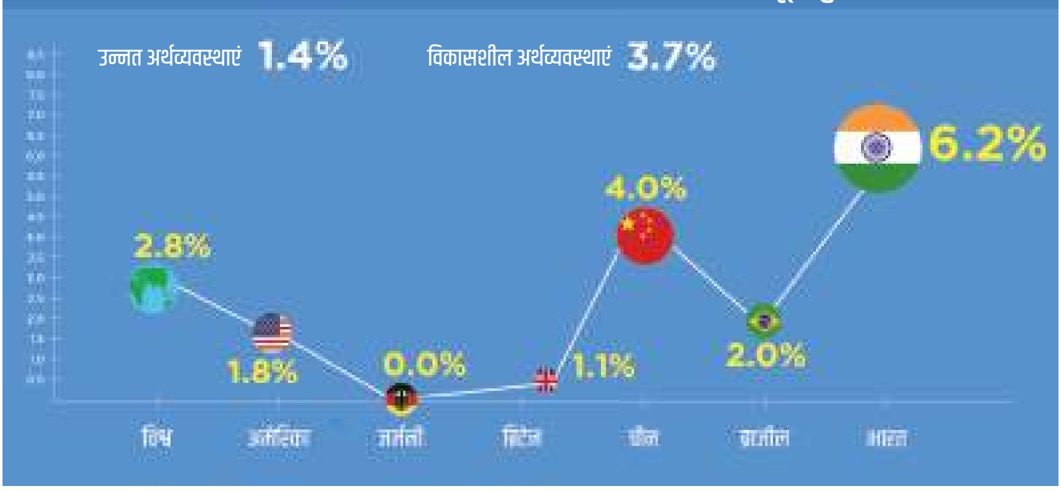

एक आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिये व्यापक सुधार
पूर्वप्रभावी कराधान की समाप्ति
वस्तु और सेवा कर लागू किया जाना
वाणिज्यिक कोयला खनन
कॉर्पोरेट कर में कमी
भारत के एफडीआई नियमों को दुरुस्त करना
दिवाला और दिवालियापन संहिता
श्रम सुधार कानून
रणनीतिक विनिवेश और परिसंपत्ति मौद्रिकरण
अंतरिक्ष और परमाणु सेक्टर में निजी निवेश की अनुमति

नया भारत
निर्यात रिकॉर्ड को तोड़ता विनिर्माण पावरहाउस
पीएलआई स्कीम से विनिर्माण को बढ़ावा
14 क्षेत्रों में विनिर्माण को सशक्त करती ₹1.97 लाख करोड़ की पीएलआई योजना
₹1.61 लाख करोड़ का निवेश उत्पन्न
विनिर्माण से निर्यात को बढ़ावा
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वस्तुओं का निर्यात 437 बिलियन डॉलर पर
भारत का गैर-पेट्रोलियम निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में 374.1 बिलियन अमरीकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना से एमएसएमई सेक्टर को संरक्षण

- एमएसएमई को ऋण उपलब्ध कराकर ₹2.39 लाख करोड़ से अधिक का एनपीए बनने से बचाया गया
- 1.13 करोड़ एमएसएमई को मदद मिली
- इससे अनुमानित 1.5 करोड़ से अधिक रोजगार बचाए गए
- और अगर प्रत्येक नौकरी से चार लोगों के परिवार को लाभ हुआ, तो इससे 6 करोड़ लोगों को मदद मिली

क्या आप जानते हैं ?

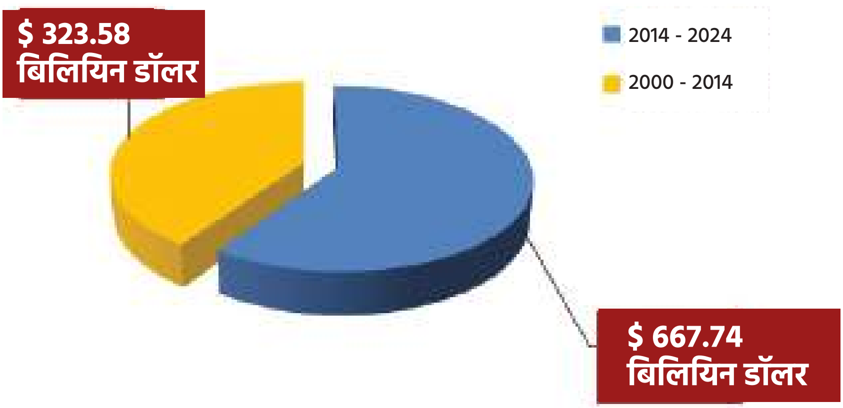

पिछले 10 वित्तीय वर्षों (2014-2024) में भारत में **667.74 बिलियन** अमरीकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) हुआ

एक समय था जब कहा जाता था- भारत क्यों? अब देश में हुए सुधारों के प्रभाव को देखते हुए कहा जा रहा है कि 'भारत क्यों नहीं?'

-नरेन्द्र मोदी

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कारोबार को लगे पंख

9

सारांश

आज दुनिया भारत को निवेश के लिए एक बेहद आकर्षक स्थान के रूप में देख रही है और वैश्विक कंपनियां यहां अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहती हैं। भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए परिवर्तनकारी व्यवस्था और आर्थिक सुधारों के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की सराहना की जा रही है। देश के कारोबारी माहौल में सुधार का सबसे बड़ा उदाहरण यहां के स्टार्टअप्स में देखा जा सकता है।इससे मौजूदा और साथ ही नए व्यवसायों और उद्यमियों को भारत में निवेश करने और व्यवसाय स्थापित करने में मदद मिली है। 2014 से पहले, भारत में लगभग कुछ सौ स्टार्टअप थे। पिछले दस वर्षों में, 1,60,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं जो 17.6 लाख से अधिक नौकरियां प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।

2014 के बाद से, किराए की मांग और लालफीताशाही की जगह रेड कार्पेट ने ले ली है। सरकार जोखिम उठाने वाले कारोबारियों के मार्ग में बाधक नहीं है, बल्कि सक्रियता के साथ उन्हें बल प्रदान कर रही है। भारत में उद्यमी और निवेशक अब व्यापार के अनुकूल माहौल और एक ऐसी सरकार से खुश हैं जो सक्रिय रूप से उनकी चिंताओं को दूर और शिकायतों का निवारण करती है। यह अभूतपूर्व बदलाव रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स व्यवस्था और एंजल टैक्स को हटाने के साथ-साथ कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने जैसे ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से संभव हुआ है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से अब व्यवसाय से जुड़ी सभी तरह की स्वीकृतियां एक जगह पर प्राप्त हो रही हैं। इसके अलावा, मोदी सरकार ने 1,500 से अधिक पुरातन कानूनों और हजारों अनुपालनों को निरस्त करके अनावश्यक अनुपालन बोझ को कम किया है। इससे भारतीय उद्यमों के लिए अनावश्यक लागत और बाधा पैदा होती थीं।

पारदर्शिता और अनुपालन आवश्यकताओं को कम करने का प्रधानमंत्री का मंत्र एक ऐसी सरकार को प्रदर्शित करता है जो अपने नागरिकों पर भरोसा करती है। करदाताओं की बढ़ती संख्या और रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन में इसका भरोसा साफ दिखता है। इसी तरह, टैक्स कलेक्शन की प्रक्रिया में सेल्फ-रेग्यूलेश, सेल्फ-सर्टिफिकेशन, कम्प्यूटर आधारित रैंडम लेबर इंस्पेक्शन और फेसलेस असेसमेंट को बढ़ावा देने से न केवल इंस्पेक्टर राज की कमर टूटी है, बल्कि अनुपालन में भी सुधार हुआ है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए भारत के प्रयासों को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है। यह विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में लगातार हो रहे सुधार से स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में देश की रैंकिंग 2014 में 142 से बढ़कर 2019 में 63 हो गई है।विश्व बैंक के लॉजिस्टिकपरफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीआई) 2023 में भारत छह स्थानों की छलांग लगाकर अब 139 देशों के सूचकांक में 38वें स्थान पर है।

यह भारत की वैश्विक स्थिति का एक मजबूत संकेतक है और यह भारत सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि विकास को पीएम गति शक्ति और नई नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आदि पहलों के माध्यम से लॉजिस्टिक से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है।

एमएसएमई और छोटे व्यवसायों के लिए अधिक पारदर्शिता और सभी को समान सुविधाओं पर जोर का उदाहरण जीईएम पोर्टल की सफलता के रूप में देखा जा सकता है जिसके माध्यम से सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपये की खरीदारी की है।

कई सुधारों और ऐतिहासिक फैसलों के अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसिकता परिवर्तन का भी सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। पिछली सरकारों के विपरीत, मोदी सरकार न केवल उद्यमियों को धन सृजक मानती है बल्कि उन्हें राष्ट्रीय विकास में भागीदार भी मानती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के ठोस प्रयासों से वेल्थ क्रिएटर्स के पूल में ऐतिहासिक विस्तार हुआ है। इसका बड़े पैमाने पर देश के जमीनी स्तर तक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे सुधारों से कल्याण और विकास कार्यक्रमों के लिए सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि हुई है, साथ ही साथ देश को रोजगार सृजन और उच्च आय प्राप्त करने में भी सक्षम बनाया है।

* * *

मुख्य बातें

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2014 में 142 से बढ़कर 2019 में

79 रैंक

की जबरदस्त छलांग के साथ 63 पर पहुंची

2022-23 की तुलना में 16% की वृद्धि के साथ 2023-24 में, भारत में

1.80 लाख

से अधिक नई कंपनियाँ पंजीकृत

श्रम कल्याण को बढ़ावा देने के लिए

4 नए

श्रम कोड

पूर्वव्यापी प्रभाव वाले टैक्स समाप्त

एंजेल टैक्स

खत्म

31 मार्च 2024 तक स्थापित नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए **कॉर्पोरेट टैक्स** घटाकर 15% किया गया

कंपनी एक्ट के तहत

81 में से 50

कम्पाउंडेबल अपराध गैर-अपराधकृत घोषित

केंद्र और राज्य सरकार में

45,051

स्वीकृतियों को तर्कसंगत बनाया गया

1,500

से अधिक पुराने कानून निरस्त

SPICe+

फॉर्म **एक ही फॉर्म** में कंपनी खोलने के लिए आवश्यक 10 सेवाओं को एकत्र करता है।

स्वीकृत पेटेंटों की संख्या 2014-15 में 5,978 से **सत्रह गुना बढ़कर 2023-24 में 1,03,057** हो गई।

राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली ने

आसान अनुपालन

सुनिश्चित किया

उपलब्धियां

पेनलेस, फेसलेस और सीमलेस टैक्स सिस्टम

- कर की दरें अब कष्टदायक नहीं रही है। भारत में आज घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए **सबसे कम 15 प्रतिशत कॉर्पोरेट कर दरें**

- मौजूदा कंपनियों के लिए सरकार ने **कॉर्पोरेट कर दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत किया।**

- पूर्वव्यापी प्रभाव वाले टैक्स ने वैश्विक निवेशकों के बीच भारत की छवि को खराब किया। इस टैक्स को अब समाप्त कर दिया गया है। **इसी प्रकार एंजेल टैक्स को भी अब खत्म कर दिया गया है।**

- अधिकांश कर प्रसंस्करण और मूल्यांकन ऑनलाइन हो रहे हैं। जो रिटर्न दाखिल करना, अपीलों और रिफ़ंड को **सीमलेस और तेज़** बनाते हैं।

- **फेसलेस मूल्यांकन और अपीलों ने उत्पीड़न** की संभावना को खत्म और इंस्पेक्टर राज को कम किया है।

रेड टेपिसम से रेड कारपेट तक

विभिन्न आर्थिक सुधारों और **प्रोत्साहनों ने भारत को निवेश के लिए** सबसे पसंदीदा स्थान बनाया है।

- **एकल विंडो प्रणाली** के माध्यम से अनुमोदन और मंज़ूरी मिल रही हैं, इससे बाधाएं कम हुई हैं।

- कंपनी के निगमन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या में कमी हुई है।

कई क्षेत्रों में **एफडीआई नियमों को उदार बनाया** है। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में एफडीआई ने सभी रिकार्ड तोड़े हैं।

उद्योग एवं उद्यमियों पर भरोसा

- **Growth Ambassadors of India** यानि हमारे
- उद्यमी नौकरियों का सृजन कर भारत की Growth Story को ताकत दे रहे हैं।

- भरोसे वाली सोच का निर्माण हो रहा है, जिसमें सरकार और नागरिक एक दूसरे पर भरोसा करते हैं।

- **Self-Regulation और Self-Compliance** आम हो चले हैं।

- **इंस्पेक्टर राज के अंत,**labour Inspection में Reforms और पर्यावरण कानून में सुधारों से Rent Seeking और Corruption पर लगाम लगी है।

* * *

क्या आप जानते हैं?

- SPICe+ फॉर्म एक ही फॉर्म में कंपनी खोलने के लिए आवश्यक 10 सेवाओं को एकत्र करता है।
- 2014 के बाद से, पीएम मोदी ने 1,500 से अधिक निरर्थक या पुराने केंद्रीय कानूनों को निरस्त कर दिया
- भारत की फिनटेक अपनाने की दर (87%) वैश्विक औसत (64%) से अधिक है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल
- बाजारों में से एक बनाती है।
- वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का वस्तु निर्यात 437 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया, जो कि पाकिस्तान की संपूर्ण जीडीपी ($350 बिलियन) से अधिक है
- 2014 से इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में पाँच गुना और निर्यात में छह गुना से अधिक वृद्धि हुई है, निर्यात CAGR 20% से अधिक और उत्पादन CAGR 17% से अधिक है।
- अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
- विश्व बैंक की 2020 की रिपोर्ट में भारत को 190 अर्थव्यवस्थाओं में 63वें स्थान पर रखा गया है, जो 2015 की 142वीं रैंकिंग से 79 पायदान ऊपर है।
- स्वीकृत पेटेंटों की संख्या 2014-15 में 5,978 से सत्रह गुना बढ़कर 2023-24 में 1,03,057 हो गई

सरकार के बड़े काम

एक जिला, एक उत्पाद

ODOP पहल भारत भर के 773 जिलों से 1,240 अद्वितीय उत्पादों को उजागर करके संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देती है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) बाज़ार पर 500 से अधिक श्रेणियों के साथ, ODOP स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ाता है, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देता है और सार्वजनिक खरीद को बढ़ावा देता है। 2020 में लॉन्च किए गए इस कार्यक्रम ने कारीगरों और छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाया है, जो भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

हर कदम पर आसानी

व्यवसाय शुरू करने में आसानी:

SPICe+ फॉर्म एक ही फॉर्म में कंपनी खोलने के लिए आवश्यक 10 सेवाओं को एकत्र करता है।

अनुपालना में आसानी:

राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली सभी आवश्यक अनुमोदनों की पहचान करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक एकल मंच प्रदान करती है।

बाहर निकलने में आसानी:

दिवाला और दिवालियापन संहिता कंपनियों के आसान अवसान की अनुमति देती है।

बौद्धिक संपदा की रक्षा करना आसान

पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट प्राप्त करना बहुत आसान हो गया है

- फाइलिंग फीस में कमी।
- ई-फाइलिंग की शुरुआत।
- प्रक्रिया को सरल बनाना और जारी करने के समय को कम करना।

अद्भुत प्रगति

	तब	अब
कारोबार सुगमता सूचकांक	142	63
लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक	54	38

वैश्विक इनोवेशन रैंकिंग

2015	2024
81	39

स्टार्ट-अप की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि
1,60,000+
अब
2014 से पहले लगभग कुछ सौ

यूनिकॉर्न
कई गुना
4
118+
2014 के अनुसार
2025 के अनुसार
भारत में यूनिकॉर्न की संख्या

नवोन्मेषी भारत
स्वीकृत पेटेंट की संख्या
1,03,057
2014-15
2023-24

जब ऐसी आधुनिक सड़कें बनती हैं, आधुनिक रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, मेट्रो, एयरपोर्ट बनते हैं, तो देश की प्रगति को गति मिलती है।

-नरेन्द्र मोदी

इंफ़्रास्ट्रक्चर- तेज़ी से हो रहा बेहतर

10

सारांश

किसी देश की आर्थिक प्रगति को आकार देने में उसके बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता की एक अहम भूमिका होती है। हमारे देश के एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की प्रक्रिया में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा एक महत्वपूर्ण मूलभूत तत्व है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बुनियादी ढांचे को अपने विकास के एजेंडे में सबसे ऊपर व केन्द्र में रखा है।

अतीत में, बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को अत्यधिक देरी का सामना करना पड़ता था। लेकिन पिछले ग्यारह वर्षों के दौरान, बड़ी सोच और बिना किसी देरी के काम को पूरा करना देश में बुनियादी ढांचे के विकास की पहचान रही है। प्रधानमंत्री ने नियमित रुप से प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी की है, जिसके कारण बुनियादी ढांचे की विभिन्न विलंबित व नई घोषित परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी की सुविधा पहुंचाने के लक्ष्य के अनुरुप, राजमार्ग निर्माण का दैनिक औसत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और यह 2014 के पूर्व के स्तरों की तुलना में लगातार अधिक बना हुआ है। इसी तरह, ग्रामीण सड़कों के निर्माण में हुई तेज वृद्धि ने दूरदराज के इलाकों में सड़क तक पहुंच को लगभग सर्वसुलभ बना दिया है।

भारतीय रेल ने भी पिछले ग्यारह वर्षों के दौरान रेलवे लाइनों के दोहरीकरण और रेलवे पटरियों के विद्युतीकरण के जरिए बड़े पैमाने पर अपनी क्षमता का विस्तार किया है। भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस 'मेक इन इंडिया' की सफलता की कहानी कहती है।

जहां तक हवाई यात्रा का प्रश्न है, मोदी सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों ने इसे सस्ता और सुलभ बना दिया है। केवल पिछले ग्यारह वर्षों के दौरान, 86 हवाई अड्डों का निर्माण करके वहां आवागमन शुरु किया गया है। इसके अलावा, 73 हवाई अड्डे, 13 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एयरोड्रोम सहित 88 कम आवागमन वाले / हवाई सेवा की सुविधा से वंचित स्थलों को उड़ान योजना के तहत जोड़ा गया है।

हवाई अड्डों की तरह, मेट्रो रेल भी अब बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गई है। पिछले ग्यारह वर्षों के दौरान मेट्रो रेल परियोजनाएं 23 शहरों तक पहुंच चुकी हैं।

ढांचागत जुड़ाव को और बढ़ाने तथा नागरिकों के लिए लागत को कम करने हेतु हाल ही में शुरु की गई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स संबंधी लागत को कम करना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, हमारे स्टार्टअप, व्यवसायों एवं किसानों को नए अवसर उपलब्ध कराना और देश में समृद्धि लाना है।

किसी देश के ढांचागत विकास को मजबूत वित्तीय प्रतिबद्धताओं द्वारा समर्थित होना चाहिए। इसी के अनुरुप, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) की घोषणा की थी। यह मास्टर प्लान संबंधित मंत्रालयों/विभागों के बीच एकीकृत एवं समग्र योजना निर्माण की दिशा में एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है ताकि मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी एवं लॉजिस्टिक्स संबंधी दक्षता को बेहतर बनाया जा सके और व्यवधानों को कम करने व परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर ध्यान देकर लोगों और सामानों की निर्बाध आवाजाही हेतु महत्वपूर्ण ढांचागत अंतराल को पाटा जा सके।

आजाद भारत के इतिहास में बुनियादी ढांचे के विकास की यह सबसे व्यापक योजना है, क्योंकि सरकार आने वाले वर्षों में लगभग 100 लाख करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बना रही है।

बुनियादी ढांचे के विकास का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का दृष्टिकोण भारत के आर्थिक विकास को नई उंचाइयों पर ले जाने में मदद करेगा। यह नागरिकों के जीवनयापन को आसान बनाएगा, रोजगार सृजन में बढ़ोतरी करेगा और समावेशी विकास सुनिश्चित करने हेतु अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी स्थापित करेगा।

* * *

मुख्य बातें

2014 से 2023-24 तक सड़क परिवहन और राजमार्ग बजट आवंटन में
570%
वृद्धि

400
विश्व स्तरीय
वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा, **136 ट्रेन सेवाएं** पहले से ही चालू हैं।

2025 में
हाईवे निर्माण की गति
34 किमी/दिन
तक

ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी
99%
कवरेज पर

2014 से रेलवे बजट में
9 गुना
से अधिक की वृद्धि हुई

मेट्रो की लंबाई 2014 में 248 किलोमीटर से बढ़कर
2025 में **1013 किलोमीटर**
हो गई।

प्रगति
बैठकों के माध्यम से पीएम मोदी ने **363** से अधिक परियोजनाओं की समीक्षा की

2014 से अब तक
86 हवाई अड्डे
चालू हो चुके हैं।

पिछले पांच वर्षों में
3600 किलोमीटर
हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए गए।

अमृत और
अमृत 2.0
के तहत शहरी विकास के लिए 6933 परियोजनाएं पूरी हुईं।

2014 से अब तक
3.96 लाख किलोमीटर
ग्रामीण सड़कें बनाई गईं

राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत
111 जलमार्गों
को राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) घोषित किया गया

उपलब्धियां

Delays से तेज Delivery तक

- **दशकों से रुके** महत्वपूर्ण Infrastructure Projects हो रहे पूरे।
- **पीएम मोदी ने व्यक्तिगत रूप से** PRAGATI Platform के माध्यम से इनकी निगरानी की।
- सरकार ने सुनिश्चित किया कि महामारी के प्रभाव से Infrastructure Projects को पूरा करने में देरी न हो।

नए भारत के लिए New Infrastructure का रिकॉर्ड

- हर साल **सबसे तेज हाइवे निर्माण** का रिकॉर्ड - 2020-21 में रोजाना 37 किलोमीटर
- **सबसे तेज सड़क निर्माण** का रिकॉर्ड
- दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे खंड पर 24 घंटे में 4 लेन वाली 2.5 किलोमीटर लंबी कंक्रीट की सड़क का निर्माण
- 21 घंटे में राष्ट्रीय राजमार्ग-52 के सोलापुर-बीजापुर खंड की 26 किलोमीटर लंबी सिंगल लेन बिटुमेन सड़क का निर्माण।
- दुनिया की **सबसे ऊंची प्रतिमा** - स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
- **दुनिया का सबसे ऊंचा बन रहा रेलवे पुल** - चिनाब पुल
- 10 हजार फीट से ऊपर विश्व की **सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग** - अटल टनल

गतिशक्ति के साथ Infrastructure का तेज विकास

- पीएम गतिशक्ति मास्टरप्लान से भारत के Infrastructure की जरूरतों के लिए **दीर्घकालिक योजनाएं**।
- Integrated Platform के माध्यम से 100 लाख करोड़ रुपये के **फंड का समुचित उपयोग** सुनिश्चित।
- पूरे भारत में **अंतिम छोर तक** Connectivity और Multi-Model Connectivity में सुधार।
- Infrastructure के निर्माण से **बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन**।
- ओखा मेनलैंड और बेत द्वारका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण। सेतु के निर्माण में 980 करोड़ की लागत आई। यह सेतुकरीब (2.32 किलोमीटर) देश में सबसे लंबा केबल ब्रिज है।
- 17,840 करोड़ की लागत से तैयार नवी मुंबई का अटल सेतु नागरिकों के जीवन को आसान बना रहा है।

* * *

क्या आप जानते हैं?

- पीएम गति शक्ति **सिंगल एकीकृत पोर्टल** के माध्यम से सभी योजनाओं और विभागों के भीतरी तालमेल को संस्थागत रूप दे रही है
- **44 केंद्रीय मंत्रालय/विभाग** और **सभी 36 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों** को एकीकृत पोर्टल पर शामिल करने से चल रही अवसंरचना परियोजनाओं की दृश्यता और हितधारकों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करेगा
- गति शक्ति सभी हितधारकों के बीच **बेहतर तालमेल** और विभिन्न परियोजनाओं की **रीयल-टाइम ट्रैकिंग** सुनिश्चित करेगी
- पीएम गति शक्ति से परियोजनाओं की **बेहतर कार्य योजना, भारी लागत से बचत** और परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी
- सरकार अगले तीन वर्षों में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए **100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल** विकसित करेगी

सरकार के बड़े काम

लंबित परियोजनाएं हुईं पूरी
उत्तर प्रदेश में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना
स्वीकृति का वर्ष:1978
4 दशकों की देरी
मोदी युग में पूरी
बिहार में कोसी रेल महासेतु
स्वीकृति का वर्ष: 2003-04
2 दशकों की देरी
मोदी युग में तैयार
केरल में कोल्लम बाईपास परियोजना
स्वीकृति का वर्ष-1975
लगभग 50 वर्षों से विलंबित
मोदी युग में पूरी
ब्रह्मपुत्र पर बोगीबील रेल-सह-सड़क पुल
स्वीकृति का वर्ष- 1997
2 दशकों की देरी
मोदी युग में बनाया गया
अटल सुरंग- 10,000 फीट की सबसे लंबी सुरंग
स्वीकृति का वर्ष- 2000
2 दशकों की देरी
मोदी युग में तैयार
दिल्ली के आस-पास ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे
स्वीकृति का वर्ष- 2006
एक दशक की देरी
मोदी युग में परियोजना पूरी

रेलवे ने 2024-25 में भारत के विकास को अग्रसर किया

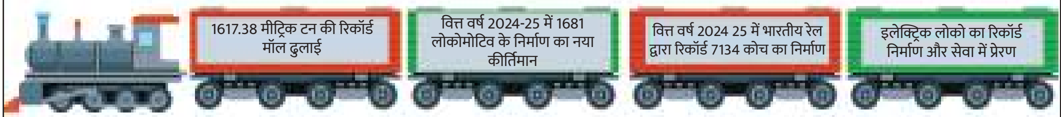

अर्ध-उच्च गति वाली स्वदेशी वंदे भारत रेलगाड़ियाँ भारतीय रेलवे को गति प्रदान कर रही हैं

200 नई वंदे भारत ट्रेन, 100 अमृत भारत ट्रेन, 50 नमो भारत रैपिड रेल और आम जनता के रेल सफर में। क्रांतिकारी परिवर्तन हेतु अगले 2 से 3 वर्षों में 17, 500 जनरल नॉन एसी कोच।

भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का विकास

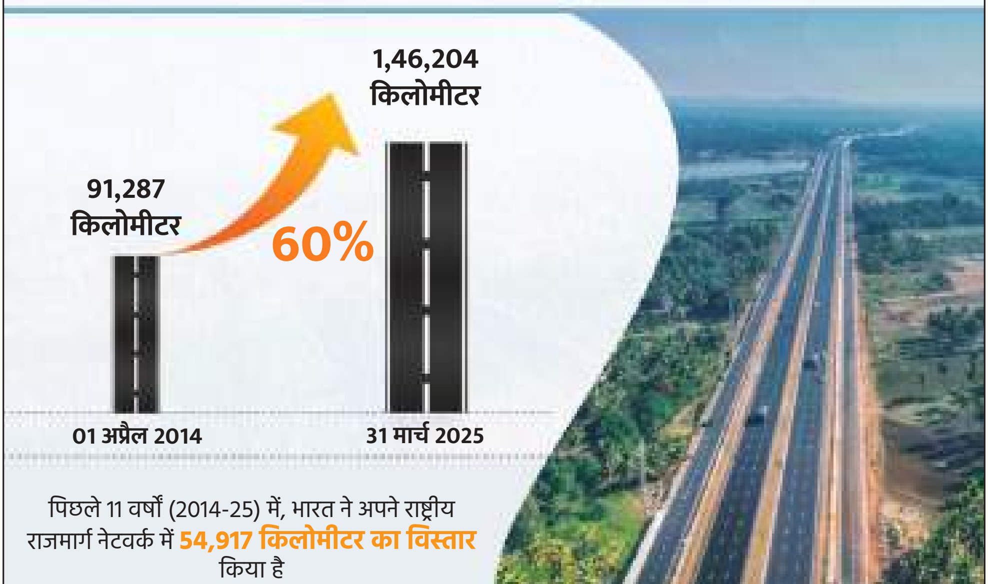

पिछले 11 वर्षों (2014-25) में, भारत ने अपने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में **54,917 किलोमीटर का विस्तार** किया है

भारत वाणिज्य और लॉजिस्टिक्स के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है

बदलाव का समय

देश	दिन (दिवस)
भारत	0.9
सिंगापुर	1.0
मलेशिया	1.0
न्यूज़ीलैंड	1.1
इंडोनेशिया	1.1
यूएई	1.1
आयरलैंड	1.2
जर्मनी	1.3
बेल्जियम	1.3
यूएसए	1.5
ऑस्ट्रेलिया	1.7
रूसी संघ	1.8
कनाडा	2.0
दक्षिण अफ्रीका	2.8

स्रोत:-विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023

उड़ान

तब	अब
74 प्रचालनरत हवाई अड्डे	**160** प्रचालनरत हवाई अड्डे
2014	2025

नए पम्बन ब्रिज का उद्घाटन

नए पम्बन ब्रिज का उद्घाटन 06 अप्रैल 2025 को
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया

जनवरी 2025 में सीआरएस का सुरक्ष निरीक्षण किया गया

चिनाब ब्रिज नदी तल से 359 मीटर ऊपर है, जो पेरिस के एफेल टॉवर से भी ऊंचा है।

रेलवे स्टेशनों का आधुनिक स्वरूप

भारतीय रेलवे की महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 103 नए स्टेशनों का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य देश भर यात्रियों के आराम, स्वच्छता और कनेक्टिविटी को बढ़ाने तथा रेलवे के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करने पर जोर देना है।

"हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे है, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे।

- नरेंद्र मोदी"

टेक्नोलॉजी से भारत को नई शक्ति

11

सारांश

मोदी सरकार ने समावेशी विकास और सहज जीवन (ईज़ ऑफ लिविंग) को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखाई है। टेक्नोलॉजी की पहुँच सुनिश्चित करने और सरकारी कामकाज (गवर्नेंस) में तेजी से डिजिटलीकरण लाने के लिए सरकार काफी तेजी से काम कर रही है।

देश में डिजिटल भुगतान को लोकप्रिय रूप से अपनाने में उल्लेखनीय सफलता की कहानी जगजाहिर है। मार्च 2025, में यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस पर 18,301.51 मिलियन (1830 करोड़) के लगभग 24.77 लाख के लेन-देन किए गए। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली विश्व स्तर पर विभिन्न देशों से जुड़ी हुई है। आधार ई-केवाईसी सेवाएं भी पारदर्शी और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करके और व्यापार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) में मदद करके बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत में आज फिनटेक अपनाने की दर दुनिया में सबसे अधिक है।

पिछले 11 वर्षों में, पूरे भारत में मोबाइल स्वामित्व में जबरदस्त तेजी हुई है। डेटा की लागत में तेज गिरावट ने शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटते हुए इंटरनेट की गहरी पैठ बनाई है। हाल ही में 5 जी सेवाओं की शुरुआत के साथ, देश डिजिटल बदलाव और कनेक्टिविटी में अगली लहर का साक्षी बनेगा। भारत के 99.6% जिलों में 5 जी रोलआउट के साथ, देश डिजिटल परिवर्तन और कनेक्टिविटी की अगली लहर का गवाह बनेगा। भारत नेट परियोजना के तहत, देश की 2.14 लाख ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।

पिछले 11 वर्षों में सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी को अपनाने से शासन के कामकाज में आई पारदर्शिता में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित हुई है। आज सभी सरकारी कार्यक्रमों में एक डिजिटल डैशबोर्ड होता है जो लाभार्थियों के सभी विवरण प्रदान करता है, सार्वजनिक सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी से भ्रष्टाचार समाप्त हो रहा है और जीवन सुगमता को बढ़ावा मिल रहा है।
कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीकों की डिजिटल डिलीवरी ने भारत को वेक्सीन वितरण में इक्विटी और पहुँच को सुनिश्चित करना आसान कर दिया है। अन्य देश अब कोविन प्लेटफ़ॉर्म जैसे प्रौद्योगिकी समाधान हासिल करने के लिए भारत की ओर देख रहे हैं।

मोदी सरकार ने शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और खामियों को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल उपकरणों को प्रभावी ढंग से तैनात किया है। उद्धारण के लिए, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और आधार प्रमाणीकरण की शुरुआत में लाखों फर्जी लाभार्थियों का सफाया हुआ है, सरकार के लिए भारी बचत हुई है, और नागरिकों को समय पर लाभ मिला है। 2015 से 2023 के बीच, सरकार ने डीबीटी के माध्यम से लाभ वितरण के कारण 3.48 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत की है।

सार्वजनिक खरीद, जो पहले नौकरशाही भ्रष्टाचार के लिए एक आम तरीका था, अब डिजिटल हो गया है क्योंकि सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा खरीद के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। यह पोर्टल देश में भ्रष्टाचार को सफलतापूर्वक समाप्त कर रहा है और सार्वजनिक खरीद को सुव्यवस्थित कर रहा है।

पिछले 11 वर्षों में, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम लगातार मजबूत हुआ है। भारत के अब तक के पहले निजी लॉन्च वाहन विक्रम-एस के हालिया लॉन्च के साथ इसके विभिन्न मिशनों के बारे में व्यापक रूप से बात की जाती है। भारत अब इस क्षेत्र में नवाचार और उन्नति के एक नए दशक में प्रवेश करने के लिए तैयार है।

* * *

मुख्य बातें

वर्ष 2025 में भारत में
116 करोड़
मोबाईल सबस्क्राइबर
होंगे

2.14 लाख
ग्राम पंचायतें **ऑप्टिकल फाइबर** से जोड़ा गया

डेटा की लागत प्रति जीबी
308 रुपये से घट कर ₹9.34 हो गई

गरीब और जरूरतमंदों को सीधे तौर पर लगभग
44 लाख करोड़ रुपये
का **डीबीटी**

मार्च 2025 तक
जीईएम पोर्टल पर
₹13.41 लाख करोड़
के ऑर्डर

टियर 2 और **टियर 3**
शहरों से
51%
स्टार्टअप

अप्रैल 2025 में
₹24 लाख करोड़
के **यूपीआई लेन-देन**

रियल-टाइम में विश्व में
49%
डिजिटल लेन-देन
भारत में हुआ

पिछले 11 वर्षों में
इंटरनेट उपयोगकर्ताओं
की संख्या **285% तक बढ़ी**

डिजिटल इंडिया के तहत
5.76 लाख
कॉमन सर्विस सेंटर संचालित (सीएससीएस)

भारत नेट के तहत
6.93 लाख किमी
ऑप्टिकल फाइबर केवल बिछाई गई

इसरो द्वारा एक ही बार में
104 सैटेलाइट
लॉन्च किए गए-एक अभूतपूर्ण विश्व रिकार्ड

उपलब्धियां

डिजिटल इंडिया का सपना हो रहा साकार

- डिजिटल डिवाइड को पाट रही है , **स्मार्ट फोन धारकों की संख्या में भारी वृद्धि।**
- **डेटा की कीमत में काफी गिरावट** से इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि हुई है।
- **डिजिटल साक्षरता** से शासन के डिजिटलाइजेशन में मिल रही मदद

डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर से डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तक

- डीबीटी जैम द्वारा क्रियाशील **जनधन-आधार-मोबाईल फोन**
- **लीकेज को रोक कर** पब्लिक सर्विस डिलीवरी का कायाकल्प
- कल्याणकारी योजनों के लाभ के लिए **बिचौलियों के कमीशन से मुक्ति**
- **फर्जी लाभार्थियों को हटाने से भारी बचत**

भाषिणी :- भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करता:- एआई द्वारा 22 भारतीय भाषाओं का अनुवाद

- IRCTC, NPCI IVRS, और पुलिस रिकॉर्ड जैसे Apps को भारतीय भाषाओं के समावेशन के माध्यम से भारत की विभिन्न भाषाओं से जोड़ना

कर्मयोगी भारत + आईगॉट—सिविल सेवा की पुनर्कल्पना

- एक करोड़ से ज्यादा ऑनबोर्ड सिविल सेवक। 3.1 करोड़ से अधिक लर्निंग सर्टिफिकेट जारी हुए **प्लेटफॉर्म पर 2400+ पाठ्यक्रम** बहु भाषीय और **एआई संवर्धित** पाठ्यक्रम से अधिकारियों का निरंतर सशक्तिकरण

* * *

सरकार के बड़े काम

सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार समाप्त

जीईएम (जेम) सरकार का **ई-बाज़ार**

मार्च 2025 तक ₹13.41 लाख करोड़ से अधिक के 2.83 करोड़ ऑर्डर दिए गए

29,000 से अधिक स्टार्ट-अप और 1.8 लाख महिला नेतृत्व वाले व्यवसायों सहित 22 लाख से अधिक विक्रेता पंजीकृत

सभी भारतीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 100 प्रतिशत कवरेज प्राप्त

वित्तीय वर्ष 2024-25 में

जीईएम पर **97%** लेन-देन शुल्क मुक्त हुआ, इस से छोटे विक्रेताओं को लाभ हुआ है।

5.4 लाख करोड़ की वार्षिक खरीद

37% से अधिक की खरीद एमएसएमई के माध्यम से

डीबीटी के माध्यम से लीकेज बंद

बड़ी संख्या, बड़ा प्रभाव

2024-25 में कुल डीबीटी :- **6.7 लाख करोड़** से अधिक

कुल बचत (2014-23) **₹3.48 लाख करोड़**

वर्ष **2014** से लगभग 44 लाख करोड़ का कुल प्रत्यक्ष लाभ (कुल)

फर्जी लाभार्थियों का सफाया

5.87 करोड़ अयोग्य राशन कार्ड लाभार्थियों के नाम हटाए गए

4.23 करोड़ नकली या फर्जी एलपीजी कनेक्शन रद्द

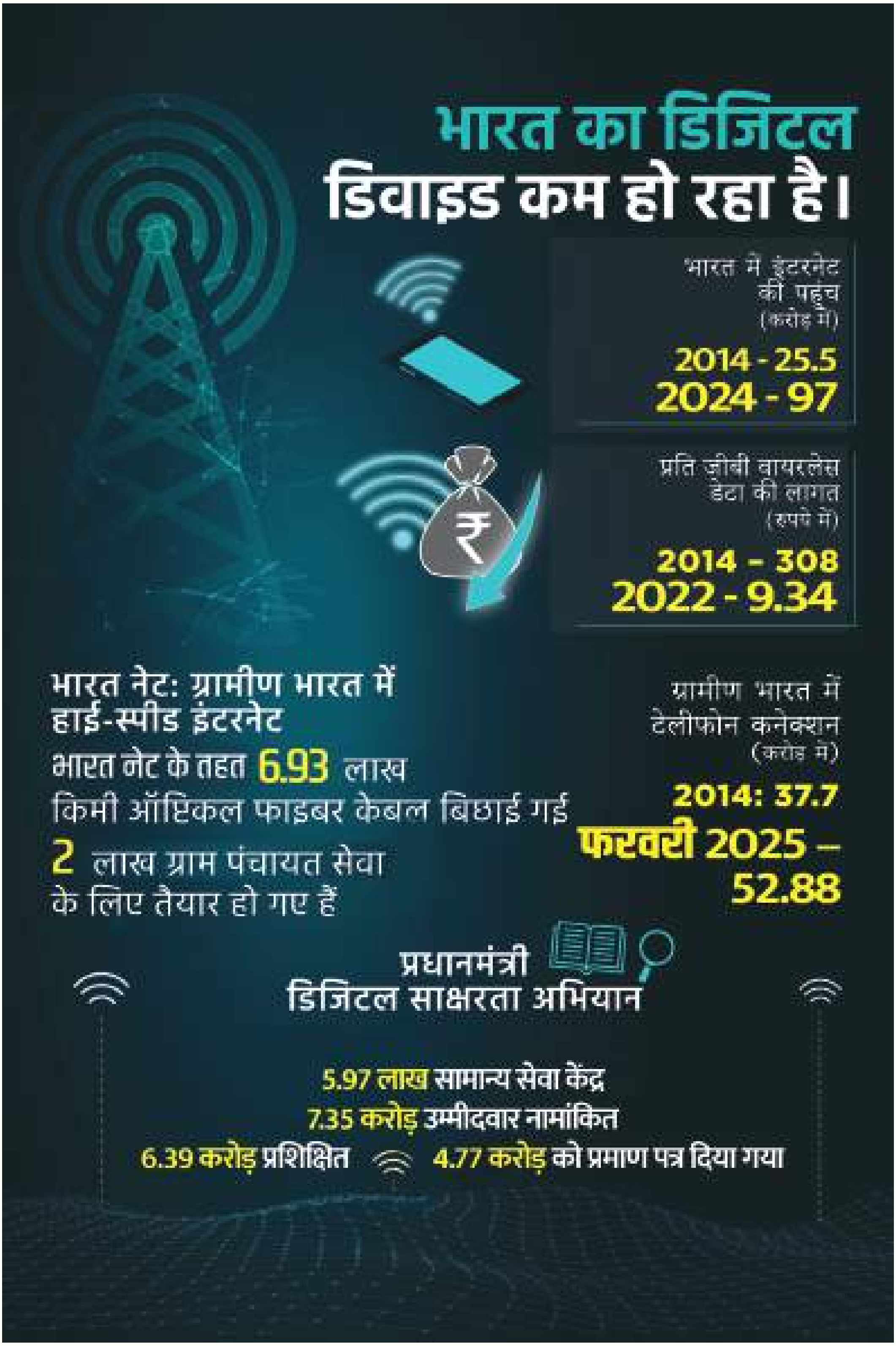
भारत का डिजिटल
डिवाइड कम हो रहा है।
भारत में इंटरनेट
की पहुंच
(करोड़ में)
2014 - 25.5
2024 - 97
प्रति जीबी वायरलेस
डेटा की लागत
(रुपये में)
2014 - 308
2022 - 9.34
भारत नेट: ग्रामीण भारत में
हाई-स्पीड इंटरनेट
भारत नेट के तहत 6.93 लाख
किमी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई
2 लाख ग्राम पंचायत सेवा
के लिए तैयार हो गए हैं
ग्रामीण भारत में
टेलीफोन कनेक्शन
(करोड़ में)
2014: 37.7
फरवरी 2025 –
52.88
प्रधानमंत्री
डिजिटल साक्षरता अभियान
5.97 लाख सामान्य सेवा केंद्र
7.35 करोड़ उम्मीदवार नामांकित
6.39 करोड़ प्रशिक्षित
4.77 करोड़ को प्रमाण पत्र दिया गया

22 महीनों में भारत के 99.6% जिलों में 5G रोलआउट

विशाल अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदमों ने दुनिया में विशेष छाप छोड़ी है। साथ ही वैज्ञानिक अन्वेषण तथा तकनीकी नवाचार के प्रति देश की प्रतिबद्धता भी मजबूती से प्रदर्शित हुई है। अंतरिक्ष क्षेत्र के अनुप्रयोग के प्रभावी और कुशल उपयोग के माध्यम से भारत की समग्र प्रगति को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) लगातार एक वैश्विक अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में विकसित हुआ है।

यह परिवर्तन सरकार के निरंतर समर्थन से संभव हुआ है जिससे भारत के अंतरिक्ष मिशनों को लगातार बढ़ावा दिया है और नई उंचाइयों तक पहुंचाया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, अंतरिक्ष अन्वेषण के महत्व को राष्ट्रीय विकास के उत्प्रेरक के रूप में पहचाना गया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में उनका जुड़ाव तब शुरू हुआ जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उनकी दूरदर्शिता ने अंतरिक्ष क्षेत्र में अनुप्रयोगों को प्रभावी शासन के समाधान में परिवर्तित करना सुनिश्चित किया। पीएम गति शक्ति योजना में उसी तकनीक का लाभ उठाया जा रहा है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें निर्बाध रूप से क्रियान्वित करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। केवल दूरदर्शी नेता ही समझ सकते हैं कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अन्वेषण ही अंतरिक्ष में रहस्यों को खोलने और पृथ्वी पर प्रभावी शासन को गति देने की कुंजी है।

> "हम वहां पहुंचे, जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत"
>
> - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, 23 अगस्त 2023

प्रधानमंत्री ने इस बात को मजबूती से कहा है कि भारत का सफल चंद्रमा मिशन अकेले भारत की सफलता नहीं है, यह भारत का मानव-केंद्रित दृष्टिकोण है जिसका विश्वव्यापी रूप से स्वागत किया गया है और हमारा चंद्र मिशन भी उसी मानव-केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है, इसलिए यह सफलता पूरी मानवता की है।

प्रधानमंत्री मोदी को भरोसा है कि 'ग्लोबल साउथ' सहित दुनिया के सभी देश ऐसी उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम हैं और भारत की प्रधानमंत्री को भरोसा है कि ग्लोबल साउथ सहित दुनिया के सभी देश ऐसी उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम है और भारत की तरह सभी चंद्रमा और उस से आगे की आकांक्षाएं रख सकते हैं,

आकाश

की अनंत ऊंचाइयों की ओर

चंद्रयान 3

इसरो और भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण

- चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला पहला देश
- चंद्रमा पर पहुंचने वाला विश्व का चौथा देश
- चंद्रयान 3 की लैंडिंग को ध्यान में रखते हुए **23 अगस्त** को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया
- रोवर प्रज्ञान पर लगा लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप (एलआईबीएस) उपकरण ने दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह में सल्फर (S) की उपस्थिति की पुष्टि की

चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-3

भारत की चंद्रमा-यात्रा के दो दशक

सुलझ रहे चंद्रमा के रहस्य

चंद्रयान 1
पहली उड़ान

- प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त 2003 को चंद्रयान परियोजना की घोषणा की थी। यह अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया और इसने 2009 तक काम किया
- उद्देश्य - अंतरिक्ष में तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने और परीक्षण के लिए चंद्रमा की परिक्रमा करना
- खर्च - ₹ 386 करोड़

चंद्रयान 2
एक यादगार प्रयास

- जुलाई 2019 में लॉन्च
- उद्देश्य - चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट-लैंडिंग करना और सतह पर एक रोबोटिक रोवर को संचालित करना
- खर्च - ₹ 603 करोड़

चंद्रयान 3
अंधेरे पक्ष पर रौशनी

- 14 जुलाई 2023 को लॉन्च
- उद्देश्य - विक्रम लैंडर के माध्यम से चंद्रमा पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग, प्रज्ञान रोवर की क्षमताओं को प्रदर्शित करना और इन-सीटू वैज्ञानिक प्रयोग करना
- खर्च - ₹ 615 करोड़
- लैंडिंग पॉइंट **शिव शक्ति पॉइंट**

इसरो का पिछले 11 साल का अंतरिक्ष रिकॉर्ड

- कुल लॉन्च मिशन – 100
- अंतरिक्ष बजट बढ़कर 13416.2 करोड़ हुआ
- स्पैडेक्स (स्पेस डॉकिंग एक्सपेरीमेंट) मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की एक पहल है, इसका उद्देश्य पृथ्वी के कक्ष में मलबे की चुनौती से निपटना है
- अंतरिक्ष क्षेत्र में 328 से भी अधिक नए स्टार्ट-अप सामने आए हैं जो अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को नई उचाइयाँ दे रहे हैं।

भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र दे रहा है गुरुत्वाकर्षण को चुनौती

- उद्योग, शिक्षा और स्टार्ट-अप का एक परिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए IN-SPACE की स्थापना की गई
- भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम-एस सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया
- अग्निकुल कॉसमॉस द्वारा भारत का पहला निजी लॉन्चपैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित
- सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष- आधारित वेधशाला – श्रेणी का भारतीय सौर मिशन, आदित्य एल-1, सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया
- भविष्य में, गगनयान परियोजना में मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता की परिकल्पना की है

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन

भारत की अंतरिक्ष छलांग: इसरो ने 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बनाई है। 2027 में मानव मिशन और 2040 तक मानवयुक्त चंद्रमा मिशन पर काम चल रहा है

अलग-अलग समुदाय हो, या फिर अलग-अलग क्षेत्र, हम हर प्रकार के डिविजन को दूर कर रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में हम विवादों के बॉर्डर नहीं बल्कि विकास के कॉरिडोर बना रहे हैं

-नरेन्द्र मोदी

नॉर्थ ईस्ट बन रहा विकास का नया इंजन

12

सारांश

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने हमेशा समावेशी विकास को प्राथमिकता दी है और सरकार की उत्तर-पूर्व नीति इस क्षेत्र को मुख्यधारा में लाने के लिए उसके प्रयासों को प्रतिबिंबित करती है।

यह नीति न केवल आर्थिक विकास और आंतरिक सुरक्षा पर जोर देती है, बल्कि क्षेत्र की अनूठी संस्कृति पहचान के संरक्षण और उत्सव पर भी जोर देती है

पिछले 11 वर्षों में दिल्ली अब खुद प्रधानमंत्री, उनके सहयोगी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के नियमित दौरे के माध्यम से उत्तर-पूर्व के दरवाजे पर पहुँच गई है। प्रधानमंत्री, देश और विश्व के बाकी हिस्सों के लिए उत्तर-पूर्व संस्कृति के एक दूत बन गए हैं।

पिछले 11 वर्षों में उत्तर-पूर्व में आर्थिक विकास के लिए विशेष निवेश किया जा रहा है। पिछले 11 वर्षों में काई परियोजनाएं पूरी की गई हैं। उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) के तहत 974 औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत हुई हैं। पूर्वोत्तर के विकास के लिए 31.03.2025 तक 1010.99 करोड़ रुपये; वर्ष 2024-25 में 400 करोड़ रुपये दिए गए। केंद्रीय बजट 2022-23 के एक भाग के रूप में उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल (PM-DevINE) की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य विशेष प्रभाव वाली परियोजनाओं के वित्तपोषण के माध्यम से इस क्षेत्र का तीव्र और समग्र विकास करना है।

कई दशकों से कनेक्टिविटी की कमी और खराब बुनियादी ढांचा इस क्षेत्र के अलगाव का मुख्य कारण बना हुआ था। लंबे समय से लंबित अनगिनत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को किया गया। प्रतिष्ठित परियोजनाओं जैसे कि बोगीबील पुल, जिसका पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की घोषणा के 16 साल बाद 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया, रेलवे नेटवर्क का विस्तार, आजादी के बाद मिजोरम में पहली बार यात्री ट्रेन का ट्रायल किया गया।

सरकार ने क्षेत्र में नए हवाई अड्डों के संचालन के साथ-साथ क्षेत्र के पहले एम्स सहित नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पर भी ध्यान केंद्रित किया है। बेहतर कनेक्टिविटी के प्रभाव को इस क्षेत्र में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के रूप में देखा जा सकता है।

उत्तर-पूर्व ने दशकों तक आंतरिक सुरक्षा से संबंधित गंभीर चुनौतियों का सामना किया था। मोदी सरकार के उठाए गए प्रभावी कदमों के करण उत्तर-पूर्व में सुरक्षा की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। साल 2014 के बाद से चरमपंथी घटनाओं और इसके चलते सुरक्षाकर्मियों व नागरिकों की मौत में भारी कमी आई है। शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने से क्षेत्र में शांति और हिंसा में कमी आई है। इन प्रयासों ने क्षेत्र में अफ्स्पा (सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून) का मार्ग प्रशस्त किया है दायरे को कम करने का रास्ता दिखाया है। इस क्षेत्र में राज्यों के बीच लंबे समय से लंबित विवाद एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है। अंततः मोदी सरकार के सक्रिय प्रयासों से कई दशकों से चले आ रहे विवादों का समाधान अब स्थायी रूप से होने लगा है। हाल ही में असम और अरुणाचल प्रदेश ने राज्यों की साझा सीमा पर दशकों पुराने विवाद के समाधान को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

बांस को घास घोषित करने के ऐतिहासिक निर्णय और राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत ने इस क्षेत्र में बांस आधारित उत्पादों के उत्पादन को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अवसरों पर जैविक खेती को बढ़ावा देने और विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य बनने को लेकर सिक्किम की सफलता को रेखांकित किया है। भारत की कहानी में हाशिए पर होने के बाद, उत्तर-पूर्व अब तेजी से देश के विकास इंजनों में से एक बन रहा है।

* * *

मुख्य बातें

AFSPA क्षेत्रों में
75%
कमी

16 साल बाद
बोगीबील पुल
का इंतजार
हुआ पूरा

2014 के मुकाबले 2024 में
उग्रवाद की घटनाओं में
64% की
गिरावट

बोडो शांति समझौता 2020 और नागा, कार्बी, एनएलएफटी (एसडी), आदिवासी समूहों, डीएनएलए, यूएलएफए, एनएलएफटी और एटीटीएफ के साथ शांति समझौते ने एनईआर में शांति

सभी राज्यों की
राजधानियों को
ब्रॉड-गेज
से जोड़ा जा रहा

पिछले 11 वर्षों में
10 ग्रीनफील्ड
एयरपोर्ट का निर्माण

एनईआर के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन के तहत, 434 एफपीसी बनाए गए, जो **1.73 लाख हेक्टेयर** को कवर करते हैं और **2.19** किसानों को लाभान्वित करते हैं।

वर्तमान में
चल रही हैं
5000 किमी
की सड़क
परियोजनाएं

पूर्वोत्तर के लिए
44,859 करोड़
की लगभग 3,613 परियोजनाएं
स्वीकृत

बांस और संबंधित उद्योग
को बढ़ावा देने के लिए
राष्ट्रीय बांस
मिशन
स्थापित

असम में किए जा रहे हैं
15 मेडिकल कॉलेज
स्थापित

वन धन योजना
के तहत
3.3 लाख
संग्रहकर्ता लाभान्वित

उपलब्धियां

दिल्ली पूर्वोत्तर की दहलीज पर

प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर का कम से कम 70 बार दौरा किया है। यह किसी भी प्रधानमंत्री के लिए एक रिकॉर्ड है। जब वे ऐसे कार्यों के माध्यम से अपनी प्राथमिकताएं बताते हैं, तो पूरी सरकारी मशीनरी इस क्षेत्र के महत्व को समझती है।

- **प्रगति के लिए शांति**
- एनएससीएन (आईएम) के साथ रुपरेखा समझौता, 2015
- त्रिपुरा शांति समझौता, (एनएलएफटी/एसडी) 2019
- बोडो शांति समझौता, 2020
- ब्रू पुनर्वास समझौता, 2020
- कार्बी-एंगलोंग शांति समझौता, 2021
- असम-मेघालय सीमा समझौता, 2022
- आदिवासी असम शांति समझौता, 2022, डीएनएलए शांति समझौता 2023, उल्फा शांति समझौता 2023, एनएलएफटी और एटीटीएफ
- शांति समझौता 2024
- शांति समझौतों ने क्षेत्र में हिंसा को काफी हद तक कम कर दिया है।
- उग्रवाद और नागरिक मौतों में उल्लेखनीय गिरावट।
- दशकों से चले आ रहे सीमा विवाद आखिरकार सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझ रहे हैं।
- **विकास की राह**
- मोदी सरकार लगातार पूर्वोत्तर के सभी हिस्सों को भारत के रेलवे मानचित्र पर ला रही है।
- तीन राज्यों की राजधानियाँ - असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश - ब्रॉड गेज रेल से जुड़ी हुई हैं।
- अन्य राज्यों की राजधानियों को जोड़ने का काम चल रहा है।
- पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों के बीच यात्रा का समय कम होने से आर्थिक अवसरों में सुधार होगा।
- कनेक्टिविटी से देश भर में पूर्वोत्तर में उत्पादित वस्तुओं की बिक्री और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा।
- आर्थिक गतिविधि रोजगार के लिए पलायन को कम करेगी और विकास को बढ़ावा देगी।

* * *

क्या आप जानते हैं?

आजादी के 75 वर्षों बाद मालगाड़ी पहली बार मणिपुर में 2022 में और मेघालय में 2023 और मिजोरम में पहला रेल इंजन 2025 में पहुंचा।

पूर्वोत्तर में संचालित हवाई अड्डे

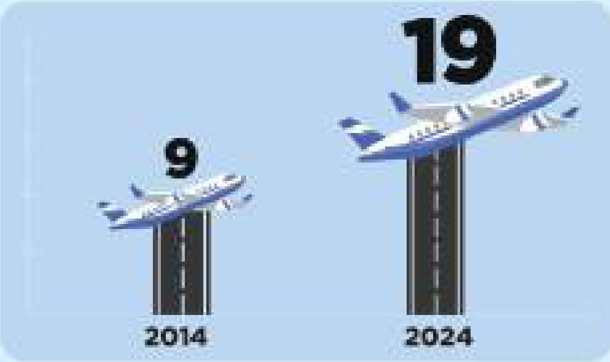

सपने देखना और उन्हें साकार करना

पूर्वोत्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दिया जा रहा है

मणिपुर में रानी गैदिन्ल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना।

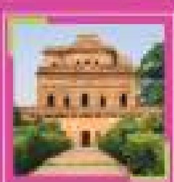

असम के शिवसागर को एक प्रतिष्ठित स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां पर एक ऑन-साइट संग्रहालय भी होगा।

क्या आप जानते हैं?

असम 15 अस्पतालों के साथ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कैंसर देखभाल नेटवर्क होगा।

8 का उद्घाटन पहले ही हो चुका है और 7 और निर्माणाधीन हैं।

पहले चरण में डिब्रूगढ़, कोकराझार, बारपेटा, दरांग, तेजपुर, लखीमपुर, जोरहाट और ईटानगर में आठ कैंसर अस्पताल बनाए जा रहे हैं।

दूसरे चरण में, धुबरी, नलबाड़ी, गोलपारा, नागांव, शिवसागर, तिनसुकिया और गोलाघाट में सात नए कैंसर अस्पताल बनाए जाएंगे।

अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भी एक कैंसर अस्पताल बनाया जा रहा है।

पूर्वोत्तर में कृषि सशक्तिकरण

- पूर्वोत्तर भारत **खाद्य तेल उत्पादन** के विस्तार को आकार देगा।
- इस क्षेत्र को **जैविक खेती के लिए वैश्विक केंद्र** में बदला जा रहा है।
- वन धन विकास योजना ने 3.3 लाख संग्रहकर्ताओं और **19,155 एसएचजी की मदद की।**
-
- **बांस को घास के रूप में पुनर्वर्गीकृत** करने और राष्ट्रीय बांस मिशन ने बांस उद्योग को बढ़ावा दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निरंतर प्रयास रहा है कि गुमनाम नायकों को उचित तरीके से सम्मानित किया जाए। इसी के अनुरूप, देश ने 2022 को लाचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के रूप में मनाया। लाचित बोरफुकन (24 नवंबर, 1622-25 अप्रैल, 1672) असम के अहोम साम्राज्य की शाही सेना के प्रसिद्ध जनरल थे, जिन्होंने मुगलों को हराया और औरंगजेब के अधीन मुगलों की लगातार बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक रोका। उन्होंने 1671 में लड़ी गई सरायघाट की लड़ाई में असमिया सैनिकों को प्रेरित किया और मुगलों को करारी और अपमानजनक हार दी।

डोनी पोलो हवाई अड्डा- अरुणाचल प्रदेश के इतिहास और संस्कृति का गवाह

एडवांटेज असम 2.0

- दो दिवसीय एडवांटेज असम 2.0 निवेश और अवसंरचना शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन गुवाहाटी, असम में किया गया।

- राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 में 4.3 लाख करोड़ रुपये के निवेश की पेशकश।
- 80 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया, जिससे मजबूत अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव दिखा।

- प्रमुख निवेशकों ने कृषि, डिजिटल सेवाओं और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में 1.55 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने का संकल्प लिया।

- व्यापक आउटरीच में 9 रोड शो, राजदूतों की बैठकें और क्षेत्र-विशिष्ट बातचीत शामिल थीं।

- पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर की शिक्षा में 21,000 करोड़ रुपये के निवेश पर प्रकाश डाला - 800 से अधिक नए स्कूल, एम्स, मेडिकल कॉलेज और आईआईआईटी।

- यह शिखर सम्मेलन एक नई आर्थिक क्रांति का प्रतीक है जो पूर्वोत्तर को दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत के प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित करता है।

यह भारत की समृद्ध विरासत है जो समयानुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है। नित्य नूतन स्वीकारती रही है। और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए।

-नरेन्द्र मोदी

विरासत और विकास

13

सारांश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के समृद्ध सभ्यतागत इतिहास और संस्कृति को पहचान दिलाने पर ज़ोर दिया है जिसके वे हकदार हैं। दशकों की उपेक्षा के बाद, उनके नेतृत्व में कई ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों को पुनर्स्थापित और पुनर्जीवित किया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं के माध्यम से वाराणसी में नगर की संकरी गलियों, घाटों और मंदिर परिसरों का कायाकल्प किया गया है। इसी तरह, उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना और गुवाहाटी में माँ कामाख्या कॉरिडोर जैसी पहलों का उद्देश्य अत्याधुनिक सुविधाएँ प्रदान करके भक्तों के लिए आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ाना है, साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

900 किलोमीटर लंबी चारधाम सड़क परियोजना चार पवित्र धामों को बारहमासी निर्बाध सड़क संपर्क प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के हृदय में समाहित केदारनाथ में पुनर्विकास परियोजनाओं की प्रगति की भी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से निगरानी की है। केदारनाथ परिसर में आदि शंकराचार्य की नव अनावरण प्रतिमा सभी क्षेत्रों में सभ्यता और सांस्कृतिक एकता का शाश्वत प्रतीक होगी। अगस्त 2020 में, आधुनिक भारत के इतिहास में एक अविस्मरणीय क्षण के रूप में, प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में राम मंदिर के लिए किए गए भूमिपूजन में सहभागी बने थे।

औपनिवेशिक मानसिकता की किसी भी पहचान को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री ने 'कर्तव्य पथ' का उद्घाटन किया, जो तत्कालीन राजपथ से सार्वजनिक स्वामित्व और सशक्तिकरण के परिवर्तन के उदाहरण का प्रतीक है। देश की खोई हुई विरासत को वापस लाना मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। सदियों से, असंख्य अमूल्य कलाकृतियाँ को चोरी करके विदेशों में तस्करी के माध्यम से भेज दिया गया था, मोदी सरकार ने 'हमारे देवताओं को वापस लाने' के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई विदेशी यात्राओं के दौरान वैश्विक नेताओं और बहुपक्षीय संस्थानों से चर्चा की। पिछले 11 वर्षों में कई अमूल्य पुरावशेष भारत वापस लाए गए हैं।

मोदी सरकार ने राष्ट्र-निर्माताओं को विशेष पहचान दी है। गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने केवड़िया को न केवल वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थान दिया है अपितु इसे भारत के लौह पुरुष को स्मरण करने का एक माध्यम भी बना दिया है। जलियांवाला बाग परिसर के पुनरुद्धार और 'पंचतीर्थ' के रूप में डॉ. बी.आर. अंबेडकर से संबंधित स्थलों के विकास जैसी परियोजनाएं हमारे राष्ट्र-निर्माताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और उपलब्धियों को सार्वजनिक स्मृति के तौर पर हमारे दिलों में अंकित करेंगी। मोदी सरकार ने सभी राष्ट्रीय नायकों के राजनीतिक दृष्टिकोण या विचारधारा से इतर उन्हें मान्यता दी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वीरतापूर्ण विरासत का सम्मान करने और उनका महोत्सव मनाने के लिए इंडिया गेट पर उनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है।

भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान को दर्शाने वाला दिल्ली में नवउद्घाटित प्रधानमंत्री संग्रहालय भी सभी राष्ट्रीय नायकों को निष्पक्ष मान्यता देने का साक्षी है।

2019 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया, यह देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को स्मरण करता है। हालाँकि यह 1961 से विचाराधीन थी, लेकिन इस महत्वपूर्ण परियोजना में ज्यादा प्रगति नहीं हुई थी। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना को बहुत आवश्यकतानुरुप त्वरित गति दी और 2015 में स्वीकृति के बाद कार्य प्रारंभ हुआ।

जब बात बेहतरीन तरीकों को अपनाने और आधुनिक दृष्टिकोण के साथ अपनी संस्कृति को उजागर करने की पहल करने की आती है, तो भारत बाकी दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। भारत की सांस्कृतिक विविधता ने लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय जिज्ञासा पैदा की है। अभिज्ञान-शाकुंतलम जैसा एक पारंपरिक नाटक महाभारत जैसे महाकाव्य के साथ मौजूद है। हर अणु को लोककथाओं और परंपराओं के एक शानदार ब्रह्मांड में बदल दिया गया है। मनोरंजन के साथ इतिहास और तकनीक के संयोजन के परिणामस्वरुप दुनिया का सबसे अद्भुत आर्थिक बाजार बना है, जिसे ऑरेंज इकोनॉमी के रूप में जाना जाता है। विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (WAVES) पहली बार भारत में आयोजित किया गया था ताकि भारत को दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में एक अग्रणी के रूप में स्थापित किया जा सके। मई 2025 में मुंबई में आयोजित इस मेगा इवेंट में दुनिया को भारतीय कला, संस्कृति और सामग्री की शक्ति और जीवंतता दिखाई गई।

'काशी तमिल संगमम' (केटीएस) 1.0 और केटीएस 2.0 का आयोजन क्रमशः नवंबर 2022 और दिसंबर 2023 में वाराणसी में किया गया। केटीएस 3.0 का आयोजन फरवरी 2025 में तीन शहरों (महाकुंभ के अनुरूप अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी) में किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य देश के दो सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षण केंद्र-तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का उत्सव मनाना, उन्हें फिर से मजबूत बनाना और पुनः स्थापित करना था । मोदी सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का महोत्सव मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, इसका उद्देश्य देश की सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाना है।

* * *

मुख्य बातें

विश्व स्तरीय
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल प्रोजेक्ट

अयोध्या
में भव्य
राम मंदिर
का निर्माण

स्वदेश दर्शन
के तहत चिन्हित किए गए विषयगत सर्किट के तहत
76 परियोजनाएँ
विकसित

2014 से अब तक
642
चोरी हुई कलाकृतियां
भारत लाई गईं, 2013 तक केवल 13 वापस आईं

207.3 करोड़
की लागत से **केदारनाथ** पुनर्विकास परियोजना

चार धाम एनएच कनेक्टिविटी कार्यक्रम के तहत
825 किलोमीटर
एनएच विकसित किए जाएँगे

3.5 करोड़ रुपये
की लागत से **सोमनाथ मंदिर** पुनर्निर्माण परियोजना

सिख तीर्थयात्रियों के लिए
करतारपुर साहिब कॉरिडोर
का उद्घाटन

हृदय योजना
के तहत 12 हेरिटेज शहरों का विकास

आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश भर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और देशभक्ति के साथ आजादी के 75 साल पूरे होने का उत्सव मनाया जाएगा

PRASHAD योजना
के तहत सांस्कृतिक स्थलों के विकास के लिए
1,899 करोड़ रुपये
का निवेश

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025
केंद्रीकृत डिजिटलीकरण और एक मजबूत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता, जवाबदेही और शासन को स्थापित करता है

उपलब्धियां

लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के पदचिह्नों का अनुसरण

माहनतम रानियों में से एक लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर का मंदिरों के कायाकल्प में योगदान आज भी देशभर में याद किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी उनके ही पदचिह्नों पर चल रहे हैं।

लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर	पीएम मोदी
वाराणसी में मौजूदा काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण	मंदिर के चारों ओर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विकास
वाराणसी के प्रसिद्ध घाटों का जीर्णोद्धार	घाटों की सफाई, नमामि गंगे से गंगा का प्रदूषण कम हुआ
अयोध्या में सरयू घाट का नवीनीकरण कराया	भव्य राम मंदिर का भूमिपूजन
जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया	सोमनाथ मंदिर के आसपास विकास कार्य, पार्वती मंदिर का निर्माण

पूर्व के राजनेताओं के विपरीत पीएम मोदी को देश की विरासत और संस्कृति से गहरा लगाव

- प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी संस्कृति को सम्मान देने में कभी कदम पीछे नहीं खींचा।
- सरकार भी भारतीय संस्कृति और मूल्यों को बढ़ावा देने में निरंतर जुटी है।
- प्रधानमंत्री मोदी **गणमान्य लोगों को जो उपहार देते हैं** और वैश्विक नेताओं को जिन स्थानों पर ले जाते हैं, वह एक प्रकार से हमारी सांस्कृतिक विरासत की अभिव्यक्ति है।
- चोरी हुए Antiquities और Artefacts की वापसी के लिए उन्होंने सक्रिय प्रयास किए हैं।

सोमनाथ से केदारनाथ तक, अयोध्या से अजमेर तक, वाराणसी से वेलंकन्नी तक

- मोदी सरकार महत्वपूर्ण स्थलों को संरक्षित करना अपना कर्तव्य मानती है, **चाहे वह किसी भी क्षेत्र या धर्म के हों**।
- सोमनाथ, अयोध्या, केदारनाथ जैसे स्थलों पर प्रधानमंत्री मोदी के कार्य जगजाहिर हैं। **PRASHAD Scheme के तहत हर धर्म के स्थानों का विकास किया जा रहा है**।
- चेरामन जुमा मस्जिद, हजरतबल, अजमेर, सेंट थॉमस श्राइन और वेलंकन्नी को अपग्रेड किया गया है।
- कश्मीर में सेंट ल्यूक चर्च का जीर्णोद्धार किया गया और तीन दशक के बाद फिर से खोल दिया गया।

भारत के महापुरुषों का सम्मान

- स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अखंड भारत के निर्माण में **सरदार वल्लभभाई पटेल** के योगदान का सम्मान है।
- **नेताजी सुभाष चंद्र बोस** की विरासत को सम्मान देने के लिए पुरानी फाइलों को जारी करने के साथ ही इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है।
- साबरमती आश्रम के पुनर्विकास के माध्यम से **महात्मा गांधी की विरासत** को आगे बढ़ाया गया।
- पंचतीर्थ **डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर** को देश की चर्चा के केंद्र में लाकर उनके योगदान को नई पहचान देता है।
- **जलियां वाला बाग स्मारक** का जीर्णोद्धार स्वतंत्रता संग्राम की यादों को भावी पीढ़ियों के लिए प्रासंगिक बनाता है।
- **11 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय** विकसित किए जा रहे हैं।
- राष्ट्र-निर्माताओं को पहचान और सम्मान देने में कोई राजनीतिक पूर्वाग्रह नहीं है। प्रधानमंत्री संग्रहालय **न तो एक व्यक्ति और न ही एक पार्टी** के लिए के लिए बनाया गया है, बल्कि यह सभी प्रधानमंत्रियों के लिए है।

* * *

सरकार के बड़े काम

क्या आप जानते हैं?

वर्ष 2013 से पहले, विदेशों से केवल 13 चोरी की पुरावशेष भारत लौटाए गए थे। तब से अब तक प्रधानमंत्री मोदी की निरंतर राजनीतिक और कूटनीतिक पहल के कारण, **642 चोरी की गई प्राचीन वस्तुएं वापस पा ली गई हैं** और भारत लौटने के विभिन्न चरणों में है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में भगवान श्री देवनारायण जी की जन्मभूमि में

सोमनाथ मंदिर विहार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष के अवसर पर लोगों को तिरंगा घर लाने और इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु “हर घर तिरंगा” अभियान शुरू किया।

“भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग कई समाजों और राष्ट्रों की भलाई का मार्ग दिखाता है। यह करुणा और दया के महत्व पर प्रकाश डालता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं विचार और कर्म दोनों में सादगी का प्रतीक है।”

-नरेंद्र मोदी

सिख संस्कृति का उत्सव

पवित्र गुरुओं का सम्मान

श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व

श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व

करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन

पीएम संग्रहालय, नई दिल्ली

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी

काशी विश्वनाथ गलियारे का एक एरियल व्यू

भारत मंडपम

> 'भारत मंडपम' आह्वान है भारत के सामर्थ्य का,
> भारत की नई ऊर्जा का। 'भारत मंडपम' दर्शन है,
> भारत की भव्यता का और भारत की इच्छाशक्ति का।
> **- नरेन्द्र मोदी**

- भारत मंडपम - की उत्पत्ति भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम के विचार से हुई है, जो सार्वजनिक समारोहों के लिए एक मंडप था।
- सम्मेलन केंद्र भवन का वास्तुशिल्प डिजाइन भारतीय परंपराओं से प्रेरित है
- भारत मंडपम में नटराज की मूर्ति 27 फीट ऊंची है और इसका वजन 18 टन है। यह अष्टधातु से बनी सबसे ऊंची मूर्ति है।

नया संसद भवन

- वास्तु पर आधारित त्रिकोणीय डिज़ाइन।
- स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित पवित्र सेंगोल, जो धार्मिक शासन का प्रतीक है।
- संविधान हॉल भारत की लोकतांत्रिक विरासत और प्रमुख ऐतिहासिक दस्तावेज़ को प्रदर्शित करता है।
- राजस्थान के बलुआ पत्थर जैसी स्वदेशी सामग्रियों से निर्मित यह भवन भारत की सांस्कृतिक और स्थापत्य पहचान को दर्शाता है।
- भूकंपरोधी, सौर ऊर्जा और वर्षा जल संचयन के साथ टिकाऊ डिज़ाइन।

विरासत भी विकास भी

भव्य-दिव्य-नव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या में संबोधन के मुख्य बिंदु

22 जनवरी, 2024, ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं। ये एक नए कालचक्र का उद्गम है

प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कण-कण से जुड़े हुए हैं

रामलला के इस मंदिर का निर्माण, भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है

हमें नित्य पराक्रम, पुरुषार्थ, समर्पण का प्रसाद प्रभु राम को चढ़ाना होगा। इनसे नित्य प्रभु राम की पूजा करनी होगी, तब हम भारत को वैभवशाली और विकसित बना पाएंगे

प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ के उद्घाटन के अवसर पर
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया

अमृत काल के पंच प्राण

वेव्स 2025: नवाचार और मीडिया के भविष्य को आकार देना

- मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में दुनिया का पहला वैश्विक अभिसरण शिखर सम्मेलन विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 1 से 4 मई, 2025 तक मुंबई में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया।
- शिखर सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और कुल मिलाकर 1 लाख से अधिक आगंतुक आए। 1,000 से अधिक वैश्विक और भारतीय मीडिया और मनोरंजन कंपनियों ने भाग लिया।
- 77 देशों ने वेव्स घोषणा को अपनाया।
- 140 से अधिक सत्रों में 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं ने भाग लिया, जिसमें प्रमुख हस्तियों द्वारा 50 से अधिक मुख्य भाषणों वाले पूर्ण सत्र शामिल हैं।
- वेव्स बाज़ार ने ₹1,300 करोड़ से अधिक के व्यापारिक सौदे और चर्चाएँ आयोजित कीं। महाराष्ट्र सरकार ने वेव्स 2025 में कुल ₹8,000 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- वेवक्स के तहत, टियर 1 और टियर 2 शहरों के 30 मीडिया और मनोरंजन स्टार्टअप ने अपने अनूठे विचारों को सीधे 45 बड़े निवेशकों के सामने रखा। 500 से ज़्यादा स्टार्टअप ने अपनी गतिविधियों का प्रदर्शन किया।
- आईआईसीटी को विश्वस्तरीय संस्थान में बदलने के लिए एडोब, गूगल और एनवीआईडीआईए जैसे उद्योग जगत के नेताओं के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

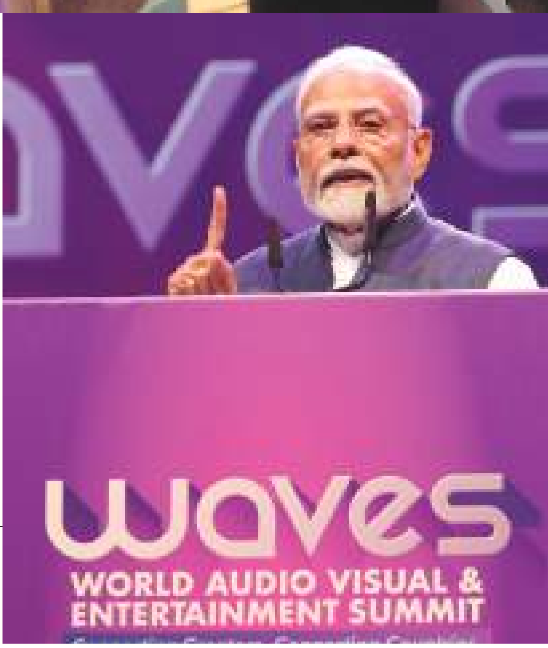
waves
WORLD AUDIO VISUAL &
ENTERTAINMENT SUMMIT

waves
WORLD AUDIO VISUAL &
ENTERTAINMENT SUMMIT

भारत प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने की हमारी संस्कृति के अनुरूप सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

-नरेन्द्र मोदी

पर्यावरण एवं सतत विकास

14

सारांश

अथर्ववेद में कहा गया है, 'पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके बच्चे हैं'। भारतीय दर्शन और जीवनशैली हमेशा से ही प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व की संकल्पना के साथ जुड़ी रही है।

पिछले 11 वर्षों में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है।

जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कार्यभार ग्रहण किया तो भारत को वैश्विक स्तर पर जलवायु संबंधित वार्ताओं में एक बाधक के रूप में देखा जा रहा था। हालाँकि, प्रधानमंत्री ने भविष्य के लिए समाधान हेतु मार्ग प्रशस्त किया है। सीओपी 21 के बाद से, जलवायु न्याय के प्रधानमंत्री के सिद्धांत ने यह सुनिश्चित किया है कि जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समानता की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जाए। भारत का ध्यान एक 'निष्पक्ष सौदा' प्रदान करने पर केंद्रित रहा है। ग्लासगो में सीओपी 26 में, प्रधानमंत्री ने एलआईएफई (LiFE) का विचार प्रस्तुत किया। भारत का मानना है कि जलवायु कार्रवाई व्यक्तिगत स्तर पर आरंभ होती है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन की जटिल समस्या का एक सरल समाधान उपलब्ध कराया है।
देश में वन आच्छादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले दशक के दौरान, भारत में बाघों की संख्या में दोगुनी से भी अधिक की वृद्धि हुई है और आज भारत में विश्व की बाघों की संख्या की 75% आबादी रहती है। इसके अतिरिक्त, अफ्रीकी चीतों को एक महादेश से दूसरे महादेश में स्थानांतरण से भी भारत की वन्यजीवन विविधता को बढ़ावा मिला है। 2023 में, 70 वर्षों के बाद, भारत में चीता शावकों का जन्म हुआ, यह प्रजाति देश में पहले विलुप्त हो चुकी थी।

जहाँ कई देश अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहे हैं, भारत ने अंतिम समय सीमा से बहुत पहले ही अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। उदाहरण के लिए, गैर-जीवाश्म स्रोतों से स्थापित विद्युत क्षमता का 40% अर्जित करने का लक्ष्य, जो सीओपी 21 में निर्धारित किया गया था, को निर्धारित समय सीमा से दस साल पहले पूरा कर लिया गया। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लिए निर्धारित लक्ष्य को भी अंतिम समय सीमा से 5 महीने पहले ही हासिल कर लिया गया।

नमामि गंगे कार्यक्रम की बदौलत इस पवित्र नदी के प्रदूषण को सफलतापूर्वक रोक दिया गया और इससे अनगिनत स्थानों पर जल की गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया। यह लक्ष्य प्रधानमंत्री श्री मोदी के दिल के बेहद निकट रहा है जैसाकि उन्हें प्राप्त उपहारों की नीलामी से मिली सभी आय को नमामि गंगे कार्यक्रम को दान करने के उनके निर्णय से जाहिर होता है।
पिछले 11 वर्षों के दौरान ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की ओर तीव्र रूपांतरण देखा गया है। नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर के लिए बहुत से प्रोत्साहन और इनपुट की निम्न लागत के कारण नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ में भारी कमी दर्ज की गई है।

इसके अतिरिक्त, उजाला कार्यक्रम के कारण हजारों करोड़ रुपये की बचत हुई है और कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन में भी कमी आई है।

इस बीच, स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने में अपने वैश्विक नेतृत्व की भागीदारी के रूप में, प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व के तहत भारत ने इस क्षेत्र में अगुवाई की और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई।

हाल ही में लांच किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य भारत को ऊर्जा के मामले में आत्म निर्भर बनाना तथा हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात के लिए एक हब बनाना भी है।

स्वच्छता से लेकर सिंगल -यूज़-प्लास्टिक से बचने तक प्रधानमंत्री ने अक्सर नागरिकों को अपनी जीवनशैली में ऐसा बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित किया है जो पर्यावरण में योगदान दे सके। इन प्रयोजनों को जन आंदोलनों में रुपांतरित करने के द्वारा उन्होंने सार्वजनिक आदतों में अस्थायी बदलाव की जगह बड़े पैमाने पर परिवर्तन को सुनिश्चित किया है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के अनुसार, हमारा ग्रह एक है लेकिन हमारे प्रयास कई होने चाहिए- एक पृथ्वी, कई प्रयास। भारत बेहतर पर्यावरण और वैश्विक कल्याण के लिए होने वाले किसी भी प्रयास में सहायता करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहेगा।

* * *

मुख्य बातें

2022 में बाघों की गिनती के अनुसार भारत में कुल
3,682 बाघ
है जो की एक रिकॉर्ड है

प्रोजेक्ट चीता
विश्व की पहली अंतरमहाद्वीपीय जंगली मांसाहारी जीव स्थानांतरण परियोजना

आपदा रोधी उपायों के लिए
₹46,000 करोड़
एनडीआरएफ की 16 बटालियन, तन्यक ढांचा, डायल 112 प्रणाली

भारत ने निर्धारित समय से
9 साल पहले COP 21 लक्ष्य
हासिल कर लिया

2014 से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता
लगभग तिगुनी

2014 से सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता
3645+% बढ़ी है

विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क
(2,245 मेगावाट से अधिक) भादला, राजस्थान में शुरू

पीएम-कुसुम
के तहत लगेंगे
49 लाख
कृषि सोलर पंप

उजाला योजना
के तहत
36.87 करोड़
एलईडी बल्ब वितरित

13 भारतीय समुद्र तटों
को अब
ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट

जम्मू और कश्मीर का
पल्ली
भारत का पहला **'कार्बन न्यूट्रल पंचायत'** है

एक पेड़ माँ के नाम
142+ करोड़ पौधारोपण

उपलब्धियां

सतत विकास सुनिश्चित करना

- मोदी सरकार ने दिखाया कि **विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण** भी संभव है।
- मोदी सरकार में पर्यावरण कानूनों में हुए सुधार ने **Compliance और Ease of Doing Business दोनों को प्रोत्साहित किया**

वैश्विक जलवायु परिवर्तन वार्ताओं को भारत दे रहा आकार

- भारत पहले की तुलना में आज Climate Change संबंधी वार्ताओं में **Leading Voice बना**
- भारत 'Climate Justice' को वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित चर्चा के केंद्र में लाया।
- प्रधानमंत्री मोदी की **'Panchamrit' और 'LiFE यानि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट'** की पहल भारत को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक रोल मॉडल के रुप में सामने लाया है।
- **GOBARdhan,** एसबीएम-जी के एक भाग के रुप में 30 अप्रैल, 2018 को लॉन्च की गई वेस्ट टू वेल्थ पहल है। जो भारत सरकार के अर्थव्यवस्था और मिशन लाइफ इनिशिएटिव में से एक है।
- GOBARdhan परियोजनाओं में बायोगैस और बायो स्लरी की बिक्री से उद्योग/उद्यमी, ग्रामीण परिवारों, किसान, स्वयं सहायता समूहो, गौशाला और ग्राम पंचायत को लाभ हुआ है।
- GOBARdhan जैव-कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करता है, जिसके परिणामस्वरुप गाँवों में स्वच्छता और मवेशियों के गोबर और ठोस कृषि अपशिष्ट को खाद और बायोगैस में परिवर्तित करके धन और ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है।

भारत के Green Landscape को बदल रही है जनभागीदारी

- Big Targets और Speedy Achievement भारत की Renewable Energy Policy की पहचान
- 2014 के बाद सौर ऊर्जा क्षमता में 41 गुना वृद्धि हुई
- प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण संरक्षण में जनभागीदारी को प्रोत्साहित किया
- स्वच्छ भारत से लेकर सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर रोक लगाने तक, लोगों को प्रेरित कर दैनिक आदतों में स्वैच्छिक बदलाव लाए।

* * *

क्या आप जानते हैं ?

ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने 'लाइफ' के रूप में दुनिया के सामने 'वन-वर्ड मूवमेंट' पर जोर दिया, जिसका मतलब **'लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट'** है।

प्रधानमंत्री ने दुनिया से **पर्यावरण अनुरूप जीवन शैली' यानी LiFE** को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक वैश्विक मिशन बनाने का आह्वान किया। इसका विजन न केवल ऊर्जा उत्पादन बल्कि ऊर्जा संरक्षण और बेहतर जीवन पर भी जोर देता है। इन समाधानों में ऊर्जा कुशल एसी, गीजर, हीटर और ओवन शामिल हैं।

सरकार के बड़े काम

- प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की योजना 2030 तक सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाने की है

- 2014 में भारत में 26 रामसर स्थल थे। पिछले 11 वर्षों में भारत ने 59 नए रामसर स्थलों को जोड़कर अपनी प्रतिबद्धता में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

स्वच्छ गंगा का सपना
हो रहा साकार

शब्द

कार्यवाही

नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में एक प्रमुख पहल के रूप में शुरू

- ₹ 40,481 करोड़ रुपए की लागत से 494 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें से 315 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता में वृद्धि से नदी स्वच्छ हुई है
- डॉल्फिन जैसी जलीय प्रजातियां लौट रही हैं।
- नदी में फेंके जाने वाले लाखों लीटर प्रदूषक पदार्थ रुक गए हैं।
- प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की नीलामी से प्राप्त रकम नमामी गंगे परियोजना पर खर्च की जाएगी।

बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की भारत की कहानी

पीएम मोदी ने दुनिया से वादा किया था कि भारत 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता तक पहुंच जाएगा

महत्वाकांक्षी? लेकिन भारत पहले से ही रिकॉर्ड गति स्थापित कर रहा है

गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा कुल स्थापित क्षमता का 49.1% है

2014 के बाद से भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता में **2.9 गुना** की वृद्धि

मार्च 2014 तक

76.38 GW

भारत की स्थापित स्वच्छ ऊर्जा क्षमता

केवल 11 वर्षों में,

228.28 GW

के साथ भारत की क्षमता लगभग तिगुनी हुई

(अप्रैल,2025)

यहां जानिए कि भारत कैसे अक्षय ऊर्जा में एक उभरता हुआ वैश्विक नेता है!

- भारत के पास अब विश्व की **चौथी सबसे बड़ी** स्वच्छ ऊर्जा क्षमता है
- भारत के पास **चौथी सबसे बड़ी** स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता है
- भारत के पास **तीसरी** सबसे बड़ी सौर ऊर्जा क्षमता है

अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक निवेश और तैनाती के अवसरों के आकर्षण पर देशों को रैंक करता है।

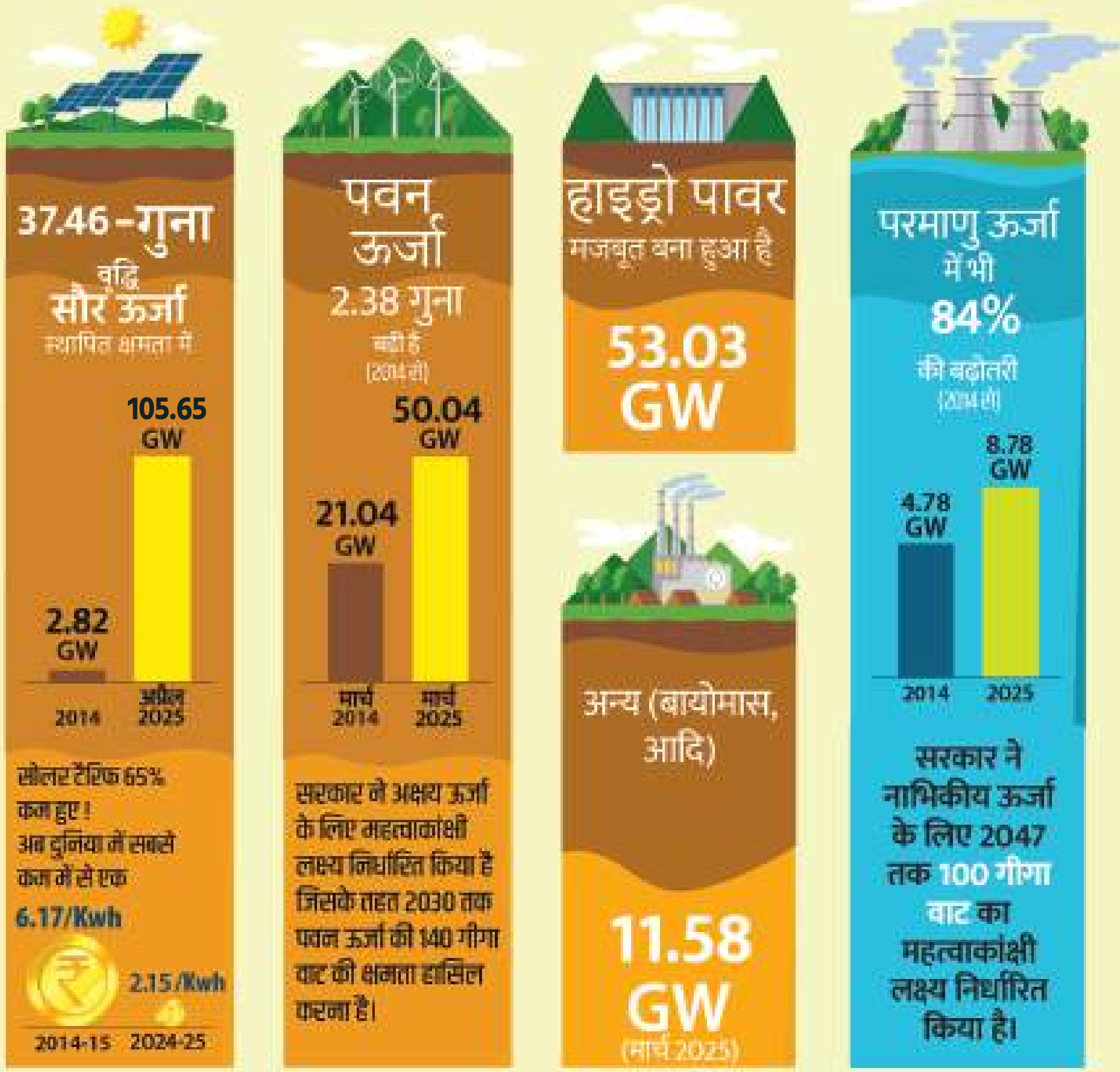

भारत उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है

कॉप-21 के गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 40% ऊर्जा प्राप्त करने के लक्ष्य को निर्धारित समय से लगभग एक दशक पहले ही प्राप्त कर लिया है। भारत सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

वैश्विक परिवर्तन लाना

पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाने की वैश्विक पहल की अगुआई की, जिसमें वर्तमान में 105 सदस्य देश और 18 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं।

हर घर में बिजली, भारत का सशक्तिकरण: पीएम सूर्य घर योजना

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 11.88 लाख घरों को सौर ऊर्जा से रोशन कर रही है, सब्सिडी और ऋण को सुव्यवस्थित करती है, और सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कम आय वाले परिवारों के लिए छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देती है।

हमारा संकल्प

पीएमजेडीवाई: प्रधानमंत्री जन-धन योजना

2014

बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच का विस्तार

55.22 करोड़
बैंक खाते

स्वच्छ भारत मिशन

2014

सभी ग्रामीण घरों में शौचालयों का विस्तार

12 करोड़
घरेलू शौचालयों का निर्माण

हमारा संकल्प

पीएमएसबीवाई: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

2015

भारत सरकार की दुर्घटना बीमा योजना

51.06 करोड़
नागरिक नामांकित

पीएमएमवाई: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

2015

छोटे व्यवसायियों को ₹ 10 लाख तक का माइक्रो-क्रेडिट लोन

52.5+ करोड़
लोन स्वीकृत

- लॉन्च वर्ष
- लाभ का विवरण
- लाभार्थियों की संख्या

विकसित भारत

पीएम-किसान: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

2019

किसानों को ₹ 6000 प्रति वर्ष का सुनिश्चित नकद ट्रांसफर।

अब तक **11 करोड़ से अधिक** किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने हेतु 3.68 लाख करोड़ वितरित

पीएमजीकेएवाई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना

2020

81 करोड़

से अधिक व्यक्तियों को मुफ्त राशन

विकसित भारत

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना कार्ड

2018

मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज तक पहुंच

40 करोड़ से ज्यादा

स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी

पीएमयूवाई: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

2016

खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन के लिए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन

10.33+ करोड़

महिलाएं लाभान्वित

पीएमजेजेबीवाई: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

2015

भारत सरकार की जीवन बीमा योजना

23.64 करोड़

नागरिक नामांकित

विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम:

रोपवे, एआई उपलब्धियां और वैश्विक सम्मान

विकास भी, विरासत भी: कनेक्टिविटी और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा

केदारनाथ रोपवे परियोजना

12.9 किमी लंबा रोपवे, **₹4,081 करोड़** की परियोजना, प्रतिदिन **18,000** यात्री

हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना

12.4 किमी लंबा रोपवे, ₹2,730 करोड़ की परियोजना प्रतिदिन **11,000** यात्री

प्रभाव

यात्रा का समय 8-9 घंटे से घटकर मात्र **36 मिनट!**

प्रधानमंत्री सिलवासा (दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव) में NAMO अस्पताल के उद्घाटन के दौरान।

> **आधुनिक अवसंरचना के विकास और जीवन सुगमता** पर ध्यान केंद्रित कर हमें आर्थिक वृद्धि और प्रगति को गति देनी चाहिए।
>
> **प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी**

डिजिटल इंडिया: आधार से एआई तक एक तकनीकी क्रांति

आधार: भारत की डिजिटल छलांग को गति

(फरवरी 2025 में)

- **225 करोड़** आधार लेन-देन
- **43 करोड़** ई-केवाईसी लेन-देन
- **12.54 करोड़** फेस ऑथेंटिकेशन – अब तक का सर्वाधिक!

भारत की एआई सिद्धि: बड़े पैमाने पर नवाचार

एआई कोष:
सुरक्षित एआई नवाचार मंच

iGOT-AI:
अधिकारियों के लिए स्मार्ट सुझाव

एआई कंप्यूट पोर्टल:
10,000 जीपीयू कार्यशील, 8,000 और शीघ्र

इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स:
एआई प्रतिभा को बढ़ावा

सभी के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित

देश भर में **16,000 +** पीएम भारतीय जनऔषधि परियोजना केंद्र

दवाओं पर **50-90%** तक बचत

75 करोड़ सुविधा सैनिटरी नैपकिन मात्र ₹1 में वितरित

वैश्विक सम्मान: बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी को किया सम्मानित

आनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित

रणनीतिक नेतृत्व और कोविड-19 सहायता के लिए सम्मान

भारत-बारबाडोस राजनयिक संबंधों को मजबूती

मोदी 3.0 की एक साल की उपलब्धियां

एक नजर में

एमएसपी के माध्यम से आय की गारंटी

गेहूं और धान की खरीद के लिए एमएसपी के माध्यम से 2.44 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया जाएगा, जिससे किसानों के लिए स्थिर आय और मूल्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

मखाना बोर्ड - बिहार के सुपरफूड को बढ़ावा देना

बिहार में मखाना को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड की स्थापना की जाएगी। किसानों को सशक्त बनाने और स्वस्थ नाश्ते के विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

जनजातियों का सशक्तिकरण, ग्राम समृद्धि

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया। अभियान का उद्देश्य ₹79,156 करोड़ के बजट के साथ 6300 से अधिक आदिवासी बहुल गांवों को संतृप्त करना है, जिससे 5 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।

दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन

घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और पोषण और रणनीतिक खाद्य सुरक्षा के लिए आयात निर्भरता को कम करने के लिए तुअर, उड़द और मसूर पर ध्यान केंद्रित करने वाला विशेष राष्ट्रीय मिशन।

पीएम धन धान्य कृषि योजना

बजट 2025-26 में घोषित नई योजना के तहत 100 कम उत्पादकता वाले जिलों को लाभ मिलेगा, जिससे केंद्रित उत्पादकता और ऋण-आधारित समर्थन के माध्यम से 1.7 करोड़ किसानों को सशक्त बनाया जाएगा।

जल जीवन मिशन (जेजेएम)

जेजेएम का बजटीय परिव्यय बढ़ाकर ₹67,000 करोड़ किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल कनेक्शन प्राप्त करने के उद्देश्य से मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया। मिशन से 15.62 करोड़ ग्रामीण परिवार लाभान्वित हो रहे हैं

ग्रामीण विद्युत आपूर्ति

वर्ष 2025 में ग्रामीण क्षेत्रों को प्रतिदिन औसतन 22.6 घंटे बिजली प्राप्त हो रही है, जिससे बिजली की निरंतर उपलब्धता बनी हुई है।

सभी के लिए किफायती यूरिया

मार्च 2018 से यूरिया की आपूर्ति अपरिवर्तित वैधानिक रूप से अधिसूचित एमआरपी पर जारी है, जिससे इनपुट लागत चुनौतियों के बीच भारतीय किसानों के लिए सामर्थ्य और समर्थन सुनिश्चित हो रहा है।

सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान

ग्राम पंचायत स्तर पर जमीनी स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा देकर कुपोषण को खत्म करने और पोषण परिणामों में सुधार करने का एक मिशन।

जन औषधि केंद्र: सभी के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवा

मार्च 2025 तक 16,000 से अधिक स्टोरों के साथ, जन औषधि केंद्र 50 से 90% कम कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ प्रदान कर रहे हैं, जिससे पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवा सस्ती और सुलभ हुई है।

वैश्विक व्यापार का प्रवेशद्वार:

वधावन बंदरगाह का उदय भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह वधावन, महाराष्ट्र में 76,000 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित किया जा रहा है - जिससे समुद्री रसद में वृद्धि होगी और भारत के वैश्विक व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

इतिहास और नवाचार को जोड़ना: अत्याधुनिक पंबन ब्रिज

भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल, ऐतिहासिक पंबन रेल पुल, 6 अप्रैल, 2025 को उद्घाटन किया गया। इंजीनियरिंग का एक चमत्कार, यह रामेश्वरम से कनेक्टिविटी को बढ़ाता है।

घाटी में वंदे भारत: जम्मू-श्रीनगर रेल का सपना साकार होने वाला है

USBRL परियोजना के तहत जम्मू-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही शुरू होने वाली है, जो सुरम्य कश्मीर घाटी में तेज़, आधुनिक रेल यात्रा का वादा करती है। सीआरएस की मंजूरी मिल गई है।

भारत को पंख: उड़ान 2.0 की उड़ान और तेज़ हुई

संशोधित उड़ान योजना का लक्ष्य 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों और 4 करोड़ यात्रियों को जोड़ना है, जिससे पहाड़ी और पूर्वोत्तर जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा।

विमानन क्षेत्र में एक नया युग

भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 का उद्देश्य समकालीन आवश्यकताओं और वैश्विक मानकों के अनुरूप भारत के विमानन क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना है। नया कानून मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देगा। अधिनियम में अतिरेक को हटाया गया है और अपील के लिए प्रावधान किए गए हैं।

₹1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष: शहरों को विकास केन्द्रों के रूप में बढ़ावा देना

शहरों को गतिशील विकास केन्द्रों में बदलने, भारत के महानगरीय क्षेत्रों में सतत शहरी विकास और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए ₹1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष शुरू किया गया।

साइबर सुरक्षित भारत और आधार: डिजिटल इंडिया को सुरक्षित और सशक्त बनाना

सरकारी अधिकारियों की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साइबर सुरक्षित भारत पहल, व्यापारियों और नागरिकों के लिए सीएससी कल्याण शिविर। सीआईएसओ डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रमों के 3 बैच आयोजित किए गए; 88 सीआईएसओ/सीटीओ और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

अप्रैल 2025 तक 210 करोड़ आधार लेनदेन, 37.3 करोड़ ई-केवाईसी लेनदेन और 14 करोड़ चेहरा प्रमाणीकरण के साथ आधार भारत की डिजिटल छलांग को शक्ति प्रदान करता है।

समावेशी विकास के लिए जाति डेटा

मंत्रिमंडल ने नीति निर्माण के लिए सटीक डेटा सुनिश्चित करने के लिए आगामी जनगणना में जाति गणना को मंजूरी दे दी है। 1931 के बाद से यह पहली ऐसी आधिकारिक कवायद है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता और समावेशिता है।

पीएम - विद्यालक्ष्मी योजना: मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता

यह योजना देश के शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने वाले मेधावी छात्रों को शिक्षा ऋण के विस्तार की सुविधा प्रदान करेगी और उसे आगे बढ़ाएगी, जिसका अर्थ है कि हर साल 22 लाख से अधिक छात्र इसके दायरे में आएंगे।

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन

कैबिनेट ने 2024-25 से 2030-31 तक के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन (एनएमईओ-तिलहन) को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य तिलहन उत्पादन में भारत को सात वर्षों में आत्मनिर्भर बनाना है।

पीएम ई-ड्राइव योजना शुरू की गई

कैबिनेट ने दो साल की अवधि में ₹10,900 करोड़ के परिव्यय के साथ पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट में क्रांति (पीएम ई-ड्राइव) योजना को मंजूरी दी

एकीकृत पेंशन योजना के तहत सुनिश्चित पेंशन

कैबिनेट ने 24 अगस्त, 2024 को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस को मजबूत करने, सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन, न्यूनतम पेंशन और मुद्रास्फीति सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी।

एक राष्ट्र एक सदस्यता (ONOS)

सरकार ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित सभी उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय उच्च प्रभाव वाले विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक देशव्यापी पहुँच प्रदान करने के लिए एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना को मंजूरी दी है। इस योजना से 1.8 करोड़ छात्र, संकाय, शोधकर्ता आदि लाभान्वित होंगे।

***

सत्यमेव जयते
भारत सरकार

सी.बी.सी., मै. विबा प्रेस प्रा. लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित